• वर्ष-4
• अंक-127
रायपुर, मंगलवार
07 जनवरी 2025
• पृष्ठ-8
• मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» वकालत में बढ़िया कैरियर

मुख्यमंत्री साय शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने दंतेवाड़ा जाएंगे

नक्सली हमला, 8 जवान शहीद

बीजापुर। एक हैरान करने वाली घटना में, सोमवार को बीजापुर में नक्सलियों ने आईईडी विस्फोटक का उपयोग करके अपने वाहन को उड़ा दिया, जिसमें आठ जवान और एक ड्राइवर की मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। विस्फोट में कई अन्य लोगों के घायल होने की खबर है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह धमाका बीजापुर जिले के बेदरे-कुटरू रोड पर उस वक्त हुआ जब जवान एक ऑपरेशन से लौट रहे थे। हताहतों की संख्या और बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 07 जनवरी को बीजापुर जिले के कुटरू में आईईडी ब्लास्ट में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने दंतेवाड़ा जाएंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार श्री साय सवेरे 9.35 बजे पुलिस लाईन हेलीपेड रायपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर 10.50 बजे दंतेवाड़ा पहुंचेंगे और वहां शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम के बाद पूर्वान्ह 11.35 बजे कारली पुलिस लाईन हेलीपेड से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर 12.55 बजे गरियाबंद जिले के राजिम स्थित कॉलेज ग्राउण्ड स्टेडियम पहुंचेंगे। श्री साय दोपहर 1.35 बजे राजिम में मंदिर दर्शन करेंगे और राजिम माता जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अपरान्ह 3 बजे रायपुर लौट आएंगे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पूरा देश जानता है कि हमारी सरकार को सत्ता में आये एक साल से ज्यादा हो गया है. हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री भी मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुझे विश्वास है कि उनका संकल्प पूरा होगा। बीजापुर आईईडी ब्लास्ट पर आईजी बस्तर पी सुंदरराज ने कहा कि पिछले 3 दिनों से नारायणपुर जिले, दंतेवाड़ा और बीजापुर क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान चल रहा था। इस ऑपरेशन के दौरान हमने 5 नक्सलियों के शव बरामद किए थे और एक जवान की जान चली गई थी। उन्होंने कहा कि जब टीम वापस लौट रही थी तो बीजापुर के अंबेली इलाके में नक्सलियों ने ढ्ढश्वष्ठ ब्लास्ट किया था। हमले में दंतेवाड़ा डीआरजी के 8 जवान और एक ड्राइवर की जान चली गई।

नक्सली हमला कायराना - रमन सिंह

हमले विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने इस घटना पर कहा कि जब भी इनके खिलाफ बड़े ऑपरेशन होते हैं तो ये नक्सली कायराना हमले पर उतर आते हैं। मैं इस हमले में शहीद हुए जवानों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार जो बड़ा कदम उठा रही है। इस कदम को और आगे बढ़ायें। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बीजापुर ढ्ढश्वष्ठ विस्फोट पर कहा कि बीजापुर से नक्सलियों की कायराना हरकत की जानकारी आई है। यह नक्सलियों की कायराना हरकत है। यह हताशा, निराशा में की गई कार्रवाई है। इन जवानों की शहादत ज़ाया नहीं जाएगी और बहुत जल्द छत्तीसगढ़, बस्तर नक्सल मुक्त होगा।

बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) सुंदरराज पी ने बताया कि कुटरू थाना क्षेत्र के अंबेली गांव के पास दोपहर करीब 2.15 बजे नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर एक वाहन को उड़ा दिया। यह घटना तब हुई जब दंतेवाड़ा जिले के जिला रिजर्व गार्ड(डीआरजी) के जवान नक्सल विरोधी अभियान के बाद अपनी एसयूवी कार से लौट रहे थे। अधिकारी ने बताया कि सभी आठ डीआरजी जवानों और वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। डीआरजी राज्य पुलिस की एक इकाई है और इसमें ज्यादातर स्थानीय आदिवासियों और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को भर्ती किया जाता है।

व्यर्थ नहीं जाएगी जवानों की शहादतः अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद को खत्म कर देगी। उन्होंने आगे कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। गृह मंत्री ने लिखा कि बीजापुर (छत्तीसगढ़) में ढ्ढश्वष्ठ ब्लास्ट में ष्ठक्रत्र के जवानों को खोने की सूचना से अत्यंत दुखी हूँ। वीर जवानों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएँ व्यक्त करता हूँ।

अमित शाह ने आगे कहा कि इस दु:ख को शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हम मार्च 2026 तक भारत की भूमि से नक्सलवाद को समाप्त करके ही रहेंगे। वहीं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा ने आज ढ्ढश्वष्ठ विस्फोट में हमारे 8 जवान और एक ड्राइवर शहीद हुए हैं। मैं उनकी शहादत को नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, जिस तरह से लगातार नक्सलियों को परास्त किया जा रहा है, उससे वे हताश हैं और ऐसी कायराना हरकतें कर रहे हैं। जल्द छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा होगा और यहां शांति बहाल होगी।

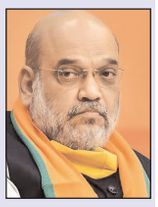

यह जांच का विषय - उपमुख्यमंत्री

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बीजापुर आईईडी विस्फोट पर कहा कि यह कैसे हुआ यह जांच का विषय है... अब हम इस पूरे नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए और दृढ़ता और ताकत के साथ काम करेंगे... उन्होंने (केंद्रीय गृह मंत्री) और दृढ़ता के साथ कार्रवाई करने की बात कही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सोमवार को नक्सलियों ने एक वाहन को बारूदी सुरंग में विस्फोट कर उड़ा दिया, जिसमें जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) के आठ जवान और एक चालक की मौत हो गई।

डबल इंजन की सरकार बनने से केन्द्र से मिल रहा भरपूर समर्थन : साय

रायपुर। श्रद्धेय अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया है और हमारा संकल्प है कि-हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को संवारेंगे। डबल इंजन की सरकार बनने से केन्द्र सरकार से छत्तीसगढ़ को भरपूर समर्थन मिल रहा है। हाल ही में केन्द्र सरकार ने सड़क और हवाई कनेक्टीविटी के साथ-साथ कई रेल परियोजनाओं की भी मंजूरी दी हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने एक साल में ही मोदी की गारंटी के ज्यादातर कामों को पूरा कर लिया है। सबका साथ-सबका प्रयास और सबका विकास के क्रम में महासमुंद जिले में विकास का पहिया अब तेजी से घूम रहा है। आने वाले समय में विकास में और तेजी आएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज महासमुंद में विभिन्न विकास कार्यों के लोकर्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए यह बात कही।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने 217 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत के 419 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इनमें 111 करोड़ रूपये के 335 कार्यों का लोकार्पण और 106 करोड़ रूपये के 84 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है। कार्यक्रम में 271 हितग्राहियों को करीब सवा करोड़ रूपये की सामग्रियों का वितरण किया गया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों के लिए 18 लाख आवास स्वीकृति की गारंटी दी थी। उसे पूरा करते हुए शपथ के दूसरे ही दिन ही हमारी सरकार ने आवासहीन हितग्राहियों के आवास की स्वीकृति दी। अभी साढ़े तीन लाख आवास की स्वीकृति और मिलेगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि महासमुंद जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। प्राचीन नगरी सिरपुर और देवाधिदेव भगवान गंधेश्वरनाथ महादेव की ख्याति पूरे देश में है। लक्ष्मण मंदिर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने की दिशा में हम तेजी से प्रयास कर रहे हैं। इको पर्यटन के क्षेत्र में कोडार जलाशय को विकसित किया जा रहा है। वहीं शिशुपाल पर्वत का सौंदर्यीकरण करने की दिशा में भी काम हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि महासमुंद जिला मुख्यालय की प्रमुख सड़क बरोंडा चौक महासमुंद से बम्हनी तक सड़क चौड़ीकरण और पुल-पुलिया निर्माण का हमने शिलान्यास किया है। अब इस मार्ग पर आवागमन सुलभ होगा। इसी प्रकार महासमुंद से तुमगांव-अछोला मार्ग चौड़ीकरण और सात महतारी सदन निर्माण के लिए भी शिलान्यास हुआ है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में हमारी सरकारी निरंतर कार्य कर रही है।

जस्टिन ट्रुडो का पीएम पद से इस्तीफा

ओटावा। कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद उनके 10 साल पुरानी सत्ता का अंत हो गया। ट्रूडो ने भारतीय समयानुसार रात करीब 10 बजे इस्तीफे का एलान किया। जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे से पहले एक अधिकारी ने बताया कि सरकार के प्रति बढ़ते असंतोष के कारण उन्होंने पद छोड़ने का फैसला लिया। ट्रूडो के अलावा वित्त मंत्री भी इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में कनाडा की राजनीति में अस्थिरता बढ़ने के संकेत हैं। कनाडाई सरकार के एक अधिकारी ने कहा, सत्ताधारी लिबरल पार्टी में अगले नेता का चुनाव होने तक ट्रूडो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि देश की संसद का सत्र 27 जनवरी से प्रस्तावित था। अब इस्तीफे के कारण संसद की कार्यवाही 24 मार्च तक स्थगित रहेगी। वहीं, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो ने कहा, मैं पार्टी नेता के पद से तथा पार्टी द्वारा अगले नेता का चयन करने के बाद प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे रहा हूं... कल रात मैंने लिबरल पार्टी के अध्यक्ष से यह प्रक्रिया शुरू करने को कहा%। जस्टिस ट्रूडो 2015 में प्रधानमंत्री बने थे।

ट्रंप की सजा पर रोक लगाएं वकीलों का अनुरोध

न्यूयॉर्क। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वकीलों ने न्यूयॉर्क के न्यायाधीश से सजा पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। वकीलों ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अदालत के फैसले को चुनौती देंगे। इसलिए उनकी सजा पर रोक लगाई जानी चाहिए। एपी की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी ट्रायल में दोषी पाया और सजा सुनाई। वकीलों ने इस पर रोक लगाने की मांग की है। अब नजरें न्यूयॉर्क के न्यायाधीश के फैसले पर टिकी हैं। मामले में डोनाल्ड ट्रंप के वकीलों ने कहा कि वे स्टेट अपील कोर्ट से जज जुआन मर्चन के पिछले हफ्ते के फैसले को पलटने की मांग करेंगे। इस फैसले में जज ने शुक्रवार को सजा की तारीख तय की थी।

प्रमुख समाचार

एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं, हालात पर नजरः नड्डा

नईदिल्ली। भारत में अब तक ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (एचएमपीवी) के तीन मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से दो कर्नाटक में और एक गुजरात में है। हालांकि, स्वास्थ्य अधिकारी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह कोई नया रोगज़नक़ नहीं है। उन्होंने कहा कि नियमित फ्लू शॉट्स या यहां तक कि तीन कोविड वैक्सीन की खुराक व्यक्ति को इस संक्रमण से प्रतिरक्षित बनाती है। वहीं, अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का भी बयान सामने आया है। कहा कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान पहली बार 2001 में हुई थी और यह कई सालों से पूरी दुनिया में घूम रहा है। एचएमपीवी श्वसन के माध्यम से हवा में फैलता है। यह सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह वायरस सर्दियों और शुरुआती वसंत महीनों के दौरान अधिक फैलता है। हालिया रिपोर्टों पर, चीन में एचएमपीवी के मामले, स्वास्थ्य मंत्रालय, आईसीएमआर और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र चीन के साथ-साथ पड़ोसी देशों की स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं।

अब बिना शर्त जमानत मिली, जेल से बाहर आए प्रशांत

नईदिल्ली। जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के कुछ घंटों बाद सोमवार को बिना शर्त जमानत मिल गई। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत दी थी। यही कारण रहा कि प्रशांत किशोर ने जमानत लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। हालांकि, अब कोर्ट की ओर से उन्हें बिना शर्त जमानत दे दी गई है। प्रशांत किशोर को जेल से बाहर लाया गया है। किशोर बिहार लोक सेवा आयोग की एक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अपना आमरण अनशन जारी रखने पर अड़े हुए हैं। इससे पहले दिन में उन्हें पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इन सबके बीच प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि सुबह 5 से 11 बजे तक मुझे पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया और अलग-अलग जगहों पर ले जाया जाता रहा। किसी ने मुझे नहीं बताया कि मुझे कहां ले जाया जा रहा है, जबकि मैंने उनसे कई बार पूछा। प्रशांत किशोर ने आगे दावा किया कि 5 साल बाद, वे मुझे फतवा के सामुदायिक केंद्र में ले गए।

शीश महल को लेकर भाजपा का केजरीवाल पर बड़ा आरोप

नईदिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली की सरकार किस प्रकार से काम कर रही है उसका मुआयना ष्ट्रत्र ने किया है और उसकी रिपोर्ट आई है। आप और केजरीवाल पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग कहते थे सरकारी बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, उन्होंने किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया, उसका काला चिट्ठा ष्ट्रत्र की इस रिपोर्ट में है। भाजपा नेता ने दावा किया कि सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक, 17 मार्च 2020 को दिल्ली के क्कङ्खष्ठ ने प्रस्ताव दिया कि केजरीवाल के आवास को फिर से तैयार किया जाना है। पीडब्ल्यूडी ने इमारत को तोड़कर एक मंजिल जोड़ने का प्रस्ताव दिया। हैरानी की बात ये है कि महज एक ही दिन में क्कङ्खष्ठ का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की हवेली की रीमॉडलिंग पर 7.61 करोड़ रुपये का खर्च आया था। टेंडर 8.62 करोड़ रुपये में जारी किया गया था यानी टेंडर की लागत 13.21त्न अधिक थी।

रिटायर्ड अफसर चला रहे बिहार में सरकारः तेजस्वी

नईदिल्ली। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए उन्हें एक ऐसा नेता बताया जो थका हुआ है और उनका दिमाग ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार थक चुके हैं और रिटायर्ड अफसरों के सहारे सरकार चला रहे हैं। कोई भी निर्णय लेने लायक नीतीश कुमार अब नहीं रहे हैं। पूरी तरीके से हाईजैक हो रखे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में पुलिस ने अपराधियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। आज भी 156 अपराधों की सूची मैंने जारी की है। तेजस्वी ने साफ तौर पर कहा कि अब नीतीश कुमार जी की साख नहीं रही है। प्रशांत किशोर को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि एक कहानी लिखी गई है जिसमें एक निर्देशक, निर्माता, फाइनेंसर, अभिनेता, वैनिटी वैन है, कौन ये करा रहे हैं किस वजह से करा रहे हैं ये हम जानते हैं। किसी को छात्रों से लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से एक फिल्म दिखाई जा रही है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। जिससे हम अवगत हैं। ये भाजपा की बी टीम है।

कमेटी से बातचीत को राजी हुए आंदोलनकारी किसान

नईदिल्ली। पंजाब सरकार द्वारा पीठ को सफलता के बारे में सूचित करने के बाद न्यायमूर्ति सूर्यकांत और एन कोटिस्वर सिंह की पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि बेहतर समझ कायम होगी...बातचीत अच्छा आकार लेगी। पीठ ने पंजाब सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के एक बयान के बाद सकारात्मक नतीजों की उम्मीद जताई। सिब्बल ने अदालत को सूचित किया कि कुछ प्रदर्शनकारी चर्चा के लिए समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नवाब सिंह से मिलने के लिए सहमत हुए हैं। सुको ने सोमवार को पंजाब-हरियाणा सीमा पर लंबे समय से चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन को संबोधित करने में प्रगति के लिए आशा व्यक्त की, जब पंजाब सरकार ने बताया कि प्रदर्शनकारी किसानों का एक वर्ग बातचीत के लिए अदालत द्वारा नियुक्त पैनल के अध्यक्ष से मिलने के लिए सहमत हो गया है। जगजीत सिंह डल्लेवाल के नेतृत्व में किसान, जो 41 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, प्रणालीगत कृषि सुधारों और न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी की मांग को लेकर फरवरी 2024 से सीमा पर डेरा डाले हुए हैं।

आमने-सामने की लड़ाई से भाग रहे नक्सली, नई भर्ती का संकट

जितेंद्र भारद्वाज

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। इसके लिए शाह, सुरक्षा एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। गृह मंत्रालय और नक्सल प्रभावित राज्यों में बैठकों के दौर चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ सहित दूसरे राज्यों में सुरक्षा बलों के नए कैंप और %फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस% (एफओबी) स्थापित किए जा रहे हैं। अभी तक 200 से अधिक नए कैंप स्थापित हो चुके हैं। ऐसे में नक्सली बौखला चुके हैं। सीआरपीएफ सहित विभिन्न सुरक्षा बलों के हाथ तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। इसके चलते नक्सलियों के सामने नई भर्ती का भी संकट खड़ा हो गया है। एनआईए द्वारा उनके वित्तीय संसाधनों पर भी चोट की जा रही है। यही वजह है कि अब नक्सली, %आईईडी% ब्लास्ट का सहारा ले रहे हैं। उनके लिए आमने-सामने की लड़ाई संभव नहीं रही। नक्सलियों द्वारा पांच तरह के आईईडी ब्लास्ट किए जा रहे हैं। यहां तक कि वे ब्लास्ट के लिए 1.95 डेस्क टाइमर का इस्तेमाल कर रहे हैं।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलियों के सामने नई भर्ती का संकट खड़ा हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ सरकार, नक्सलियों को पूर्ण सफाया करने में जुट गई है। शाह कह चुके हैं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में यह अंतिम लड़ाई है। माओवादी गतिविधियां, आखिरी चरण में हैं। इस वजह से नक्सली बौखलाहट में हैं। वे किसी भी तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। पिछले कुछ समय से नक्सली दस्ते आमने-सामने की लड़ाई से भाग रहे हैं। उन्हें मालूम है कि सुरक्षा बलों के साथ सीधी लड़ाई में वे बच नहीं सकेंगे। इसी वजह से माओवादी, %आईईडी% ब्लास्ट पर ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इसे किसी भी जगह पर दबा दिया जाता है। कोई भी दूर बैठा व्यक्ति इसे संचालित कर सकता है। सीआरपीएफ द्वारा गत वर्षों में हजारों आईईडी/टिफिन बम बरामद किए गए हैं।

देश में लगभग सात सौ से अधिक ब्लास्ट मामलों की जांच कर चुके एक अनुभवी बैलिस्टिक एक्सपर्ट कहते हैं कि कुछ वर्षों से नौसिखिये आतंकी और नक्सली %आईईडी/टिफिन% बम का इस्तेमाल करने लगे हैं। कश्मीर, पंजाब, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों या उत्तर पूर्व में जितने भी राष्ट्र विरोधी समूह सक्रिय हैं, अब वे सीधे तौर पर सुरक्षा बलों के साथ टकराने से बचने लगे हैं।

अगर कहीं पर एंबुश (घात लगाकर हमला करना) होता है तो भी उसमें विस्फोटकों का ही अधिक इस्तेमाल होता है। सीधी मुठभेड़ में उन्हें सुरक्षा बलों के हाथों भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसके चलते अब माओवादी संगठन, आईईडी विस्फोट तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भारी संख्या में ऐसे विस्फोटक तैयार कराए जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में तैनात सुरक्षा बलों के एक बड़े अधिकारी का कहना है कि अब सीधी मुठभेड़ का दौर खत्म हो चला है। आईईडी तकनीक के द्वारा लगभग सौ मील दूर बैठकर विस्फोट किया जा सकता है। ऐसे में नक्सली, सुरक्षा बलों के सामने मरने के लिए क्यों आएंगे। आईईडी विस्फोट करने में टाइमिंग बहुत अहम प्वाइंट है। एक्सपर्ट व्यक्ति ही इसे सुरक्षित तरीके से ब्लास्ट कर सकता है। भले ही देश में उच्च विस्फोटक जैसे आरडीएक्स/पीईटीएन आसानी से नहीं मिलते हैं, लेकिन कम क्षमता वाले विस्फोटक पोटाशियम, चारकोल, आर्गेनिक सल्फाइड, नाइट्रेट और ब्लैक पाउडर आदि से आईईडी और टिफिन बम तैयार कर लिए जाते हैं।

छत्तीसगढ़ में तो पीडब्लूडी एवं माइनिंग विभाग, कई तरह के विकास कार्यों में जिलेटिन स्टिक का इस्तेमाल करते हैं। इसकी मदद से इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस %आईईडी%, टिफिन बम और दूसरे तरह के प्रेशर बम तैयार किए जा सकते हैं।

आईईडी को रिमोट कंट्रोल, इंफ्रारेड, मैग्नेटिक ट्रिगर्स, प्रेशर-सेंसिटिव बार्स या ट्रिप वायर की मदद से संचालित किया जाता है। कम आयु के नक्सलियों को रिमोट कंट्रोल से ही आईईडी विस्फोट करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रेशर कूकर बम कैसे तैयार होता है, ये भी उन्हें सिखाया गया है। आतंकी/नक्सली, यही तरीका प्रयोग में ला रहे हैं। बैलिस्टिक एक्सपर्ट के मुताबिक, अब टिफिन बम बड़े स्तर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। रिमोट या टाइमर के द्वारा आसानी से यह ब्लास्ट हो जाता है। ऐसे ब्लास्ट तैयार करने के लिए नक्सलियों के पास कंटेनर, केमिकल, डेटोनेटर, इनिशिएटर और वायर सब कुछ होता है। डेटोनेटर को पावर देने के लिए माओवादी, ड्राई बैटरी सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्पेशल डेटोनेटर भी आने लगे हैं।

स्पेशल डेटोनेटर में घड़ी का सेल लगाया जा रहा है। अगर ज्यादा वोल्टेज की जरूरत है तो वहां तीन चार सेल जोड़ देते हैं। मार्केट में स्विच आसानी से उपलब्ध हो जाता है। बैलिस्टिक एक्सपर्ट के अनुसार, ब्लास्ट की घटना में टाइमिंग एक बड़ा फैक्टर होता है। अगर ये ठीक नहीं रहा तो विस्फोट करने वाला खुद भी मारा जाता है। आतंकी एवं नक्सली, 1.95 डेस्क टाइमर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सबके लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। एबीसीडी स्विच की जगह पर दूसरी टर्म आ गई है। अगर एक्सपर्ट नहीं है तो टाइम आगे पीछे हो जाता है। नतीजा, समय पर ब्लास्ट नहीं होता। नक्सलियों द्वारा आईईडी विस्फोट करना, यह सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती है।

दो महिला नक्सली समेत कुल पांच माओवादी ढेर

भारी मात्रा में हथियार बरामद, मुठभेड़ जारी

जगदलपुर। नारायणपुर और दंतेवाड़ा की सीमा में चल रही मुठभेड़ में पुलिस जवानों ने दो महिला नक्सली सहित पांच नक्सलियों को मार गिराया है, इसके अलावा पुलिस जवानों ने हथियार भी बरामद किए हैं। मामले के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नक्सल विरोधी सर्च अभियान में चार जिले दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर एवं कोंडागांव की डीआरजी के साथ एसटीएफ की संयुक्त पार्टी अबूझमाड़ क्षेत्र में गई हुई थी।

इस दौरान नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, इस घटना में पुलिस जवानों ने नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए गोलीबारी की, नक्सलियों ने पुलिस की जवाबी कार्यवाही से भाग निकले, इस दौरान जब इलाके की सर्चिंग किया गया तो 5 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। जिसमें दो महिला नक्सली शामिल थीं।

बताया जा रहा है कि सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच 04 जनवरी के शाम से रुक रुक कर मुठभेड़ चल रही थी, सर्च ऑपरेशन के दौरान अब तक दो महिला नक्सली सहित कुल 5 वर्दीधारी नक्सलियों

के शव बरामद हुए है। पुलिस ने इलाके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किये हैं। मुठभेड़ एवं सर्च अभियान अभी भी जारी है।

बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि जवान अब भी मौके पर ही मौजूद हैं और इलाके की सर्चिंग कर रहे हैं। अब तक दो महिला नक्सली सहित कुल 5 वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद हुए है। उन्होने बताया कि मारे गये नक्सलियों में डीकेएसजेडसी पीएलजीए प्लाटून नंबर 32 के सीनियर कैडर के नक्सली शामिल होने की संभावना है, जिनकी शिनाख्त की जा रही है।

नक्सलियों ने जवानों के वाहन को उड़ाया

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जवानों को ले जा रहे वाहन को नक्सलियों ने आईईडी से उड़ाया है। कुटरू मार्ग में हुए इस नक्सल हमले में 7 से अधिक जवान शहीद हो गए हैं। जबकि 8 से अधिक जवानों के घायल होने की सूचना है। इस घटना की पुष्टि बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने की है।

जानकारी के मुताबिक, सोमवार को सुरक्षाबलों के जवानों का काफिला बीजापुर के कुटरू मार्ग से जवानों को लेकर जा रहा था। इसी दौरान पहले से घात लगाए नक्सलियों ने सुरक्षाबलों के एक वाहन को आईईडी ब्लास्ट कर उड़ा दिया। इस नक्सली हमले में 7 से अधिक जवानों के शहीद होने की सूचना है। जबकि 8 से अधिक जवान घायल हो गए हैं।

नक्सलियों ने पत्रकार मुकेश की हत्या की कड़ी निंदा करते हुए जारी किया प्रेस नोट

बीजापुर। नक्सलियों के दक्षिण सब जोनल के प्रवक्ता समता ने आज सोमवार को पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या को लेकर एक प्रेस नोट जारी किया है। जिसमें नक्सलियों ने पत्रकार की हत्या की कड़ी निंदा की है और खेद भी व्यक्त किया है। इसके साथ ही पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या की जांच की मांग की है।

विदित हो कि छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले पर कहा है कि मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इस मामले की गहनता से जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईपीएस मयंक गुर्जर के नेतृत्व में 11 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। हम मामले की स्पीडी ट्रायल के लिए पूरी कोशिश करेंगे। उन्होने कहा है कि हत्या का सरगना कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर है वह कांग्रेस प्रदेश का पदाधिकारी है।

कोरबा में सराफा व्यवसायी की हत्या हमलावर लूट ले गए क्रेटा कार

कोरबा। कोरबा जिले के नया ट्रांसपोर्ट नगर से लगे इलाके लालू राम कॉलोनी में सराफा व्यवसायी की हत्या कर दी गई। उन्हें लहुलुहान हालत में अस्पताल ले जाया गया लेकिन रास्ते मे ही मौत हो चुकी थी।

घटना के बाद सोमवार को बिलासपुर रेंज के आईजी डॉ. संजीव शुक्ला कोरबा पहुंचे। कोरबा पहुंचते ही आईजी घटना स्थल पर पहुंचे और पूरे मामले से अवगत हुए। आईजी और उनकी टीम ने मृतक के परिजनों से पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद जिस तरह से आईजी का दौरा कोरबा में हुआ है। उससे कहीं न कहीं पुलिस पर इस मामले को सुलझाने का बड़ा दबाव है।

प्रारंभिक तौर पर मिली जानकारी के मुताबिक होटल ब्लू डायमंड के सामने अमृता ज्वेलर्स के संचालक गोपाल राय सोनी का निवास है। रात करीब 9 बजे अपने घर पर थे कि घर के बाहर खड़ी उनकी क्रेटा कार को चोरी करने का प्रयास किया गया। उन्होंने बाहर निकल कर अज्ञात चोरों को रोकने की कोशिश की तो उन पर हमला कर दिया गया और क्रेटा कार (जेएच 01सीसी 4455), सफेद कलर की लूट कर भाग निकले। दूसरी तरफ यह जानकारी भी सामने आ रही है कि उनके घर में घुसकर अज्ञात लोगों ने हमला किया और फिर वाहन चोरी कर ले गए। गोपाल राय सोनी पर किस चीज से हमला

किया गया है यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में सर्राफा व्यवसायी और परिजन अस्पताल पहुंचे। अस्पताल की ओर से सूचना सिविल लाइन थाना रामपुर में दे दी गई है। पुलिस भी अलर्ट हो चुकी है। घटना की खबर आम होते ही शहर में सनसनी फैल गई है। जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी दल-बल के साथ घटनास्थल लालूराम कॉलोनी पहुंच चुके हैं।

ज्वैलर्स एसोशिएशन ने जताया विरोध

हत्या के विरोध में ज्वेलर्स एसोशिएशन ने विरोध जताया है वही दो दिनों तक दुकान बंद करने का आह्वान किया है। सराफा कारोबारियों में दहशत के माहौल में है और बंद के विरोध कर रहे है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज निकाल कर अलग टीम जांच कर रही है घर के बाहर पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों के अलावा लोगों की भीड़ एकत्रित है।

चिरमिरी निगम के साजा पहाड़ रहवासी परेशान

17 साल बाद भी बुनियादी सुविधाएं नहीं

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। एमसीबी के नगर निगम चिरमिरी के वार्ड क्रमांक-01 साजापहाड़ के रहवासी पिछले 17 साल से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। वार्ड के आधा दर्जन मोहल्लों में बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं। 2008 में नगर निगम चिरमिरी अस्तित्व में आया। उस समय नगर निगम का दायरा बढ़ाने के लिए वनांचल गांव साजापहाड़ सहित आसपास के क्षेत्रों को जोड़कर वार्ड क्रमांक-01 बनाया गया। लेकिन इतने वर्षों के बाद भी यहां विकास कार्य नहीं हुए।

वार्ड के रहवासी आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। नगर निगम में शामिल हुए 17 साल बाद भी क्षेत्र में सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। बारिश के दिनों में कई मोहल्लों में आवागमन बाधित हो जाता है। नालों पर पुलिया नहीं होने से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। पेयजल के लिए लोग कुएं और हैंडपंप पर निर्भर हैं, जो गर्मियों में सूख जाते हैं। मजबूरी में लोग नालों और गड्ढों के पानी का उपयोग करते हैं।

स्थानीय महिला सुनीता ने बताया कि क्षेत्र में एकमात्र हैंडपंप है, जिसका उपयोग पूरा मोहल्ला करता है। खराब होने पर लोग नाले का पानी इस्तेमाल करने को मजबूर होते हैं। बिजली न होने से लोग मोमबत्ती और टॉर्च का

सहारा लेते हैं। तो वहीं कलेश्वरी राजवाड़े ने बताया कि सड़क नहीं होने के कारण मरीजों को खाट पर उठाकर ले जाना पड़ता है। यहां के लोग विकास कार्यों को लेकर बार-बार प्रशासन से गुहार लगाते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता। यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ सरकार में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की विधानसभा के अंतर्गत आता है।लेकिन क्षेत्र की बदहाल स्थिति सरकार की उपेक्षा को दर्शाती है।

वार्ड पार्षद संतोष सिंह ने कहा छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा वार्ड है, जहां की स्थिति बेहद खराब है। वार्ड क्रमांक-01 वन भूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कांग्रेस शासनकाल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ।अब भाजपा सरकार के कार्यकाल में विकास कार्य शुरू किए जाएंगे।

वहीं इस बारे में नगर निगम आयुक्त का कहना है कि जिस इलाके की बात हो रही है वो एसईसीएल का दुर्गम क्षेत्र है।लेकिन आने वाले समय में वहां भी मूलभूत सुविधाएं पहुंच जाएंगी।

नगर निगम आयुक्त रामप्रसाद आंचला ने कहा चिरमिरी का अधिकांश क्षेत्र एसईसीएल और वन विभाग के अधीन आता है।बिजली सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और जल्द ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

आपको बता दें कि चिरमिरी निगम के वार्ड क्रमांक 1 के भुरकुंडडांड, बाजनपथरा और कारीमाटी जैसे मोहल्लों में 127 मतदाता हैं।सड़क के अभाव के कारण यहां के लोग जंगलों और पहाड़ियों के बीच बनी पगडंडियों से गुजरते हैं। तो वहीं कंदामार, लामीगोड़ा और पचास मील क्षेत्र के लगभग 195 मतदाता बारिश के दिनों में अपने घरों तक नहीं पहुंच पाते। यहां के नालों में उफान आता है और एक दशक पहले बनी पुलिया के बावजूद सड़क नहीं बनाई गई। साजापहाड़ और महुआखाड़ी के 137 मतदाता भी सीसी सड़क और पेयजल जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं।

बीएसपी में ब्लास्ट होने से बाहर आया हॉट मेटल

प्लांट में मची अफरा-तफरी

दुर्ग। भिलाई स्टील प्लांट में आज बड़ा हादसा हो गया, जिससे प्लांट में अफरातफरी का माहौल है। ब्लास्ट फर्नेस-5 में ब्लास्ट होने की वजह से हॉट मेटल बाहर बह गया। घटना के बाद पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। आग को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। इस ब्लास्ट के कारण केबल जलकर राख हो गया है।

बताया जा रहा है कि लीकेज की शिकायत के चलते ब्लास्ट फर्नेस 5 को बंद करने की तैयारी थी। शट डाउन लेकर इसे कैपिटल रिपेयर में लिया जाना था। इससे पहले ही हादसा हो गया। फर्नेस के नीचे का हिस्सा फटने की वजह से दहकता हुआ हॉट मेटल बाहर छटक गया, जिससे हड़कंप मच गई है।

भयानक स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है।

घटना की सूचना मिलते ही भिलाई स्टील प्लांट के उच्चाधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि हॉट मेटल बाहर आने की वजह से भीषण आग लगी। आग को नियंत्रित करने के लिए बीएसपी के दमकल विभाग की टीम जुटी हुई है। वहीं हादसे का कारण अब तक आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं हो सका है। स्थिति को नियंत्रित करने के बाद बीएसपी प्रबंधन उच्च स्तरीय जांच की जाएगी।

अनुकंपा और आंगनबाड़ी नियुक्ति मिलने पर हितग्राहियों के खिले चेहरे

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गरियाबंद जिले को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने पूर्व विधायक गोवर्धन मांझी की मांग पर देवभोग को 36 गांव से जोड़ने वाले बेलाट नाले पर उच्चारित पुल बनाने का ऐलान किया। साथ ही धवलपुर, जिडार, जुगाड़ एवं पीपरछेड़ी में 10 करोड़ रुपए की लागत से 4 नए सर्वसुविधायुक्त छात्रावास का निर्माण की घोषणा की। सरकार की बेहतर योजना क्रियान्वयन के लिए सीएम साय ने जिला प्रशासन की तारीफ भी की। वहीं अनुकंपा पाने वालों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से थैंक यू सीएम सर कहकर आभार जताया।

पूर्व विधायक गोवर्धन मांझी ने सभा में पूल निर्माण की मांग रखी थी। जिसपर सीएम साय ने देवभोग के बेलाट नाले पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण का बड़ा ऐलान किया। सीएम साय ने सुपबेड़ा में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के साथ ही किडनी बीमारी के अनसुलझे केस को सुलझाने गांव में जल्द ही रिसर्च शुरू करने की बात कही है। सीएम ने कहा कि संबंधित वैज्ञानिक व विशेषज्ञों से संपर्क कर लिया गया है,जल्द रिसर्च शुरू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुसार जिले में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण और आंगनबाड़ी के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। लगभग 50 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति मिल चुकी है। साथ ही 206 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की भर्ती भी हुई है। जिला मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शामिल होकर जिला प्रशासन की इस विशेष अभियान की प्रशंसा की। साथ ही लाभान्वित हितग्राहियों ने एक स्वर में थैंक्यू सीएम सर कहकर मुख्यमंत्री साय का आभार जताया। दरअसल कार्यक्रम स्थल में लगाये गये विभागीय स्टॉल के अवलोकन के दौरान मुख्यमंत्री साय अनुकंपा नियुक्ति के हितग्राही और नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका से मुलाकात की।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

भनवारटंक से गौरेला के जंगल लौटी बाघिन

बिलासपुर। बेलगहना के भनवारटंक जंगल में बाघिन विचरण करने आई थी। यहां से देर रात तक बाघिन मरवाही वन मंडल के गौरेला रेंज जंगल की ओर लौट गई। इसके साथ ही आसपास क्षेत्र के रहने वाले ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। वहीं, वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी 24 घंटे बाघिन पर नजर रखे हुए हैं। ताकि कोई भी व्यक्ति बाघिन को नुकसान न पहुंचाए। शनिवार की देर रात बाघिन जंगल के रास्ते से भ्रमण करती हुई आगे बढ़ गई। रविवार की सुबह तक वह मरवाही वन मंडल के गौरेला रेंज के जंगल पहुंच गई है। मरवाही वन मंडल के अधिकारी व कर्मचारी बाघिन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आसपास के गांव के लोगों को सावधान रहने के लिए अलर्ट कर दिया गया है। बहरहाल अभी तक बाघिन द्वारा किसी व्यक्ति व वन्य प्राणियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाई हैं। रेडियो कॉलर के माध्यम से बाघिन का लोकेशन के बारे में लगातार पता चल रहा है। डीएफओ सत्यदेव शर्मा ने बताया कि दिसंबर 2024 को बाघिन को मनेंद्रगढ़ चिरमिरी के आसपास बाघिन को पकड़ा गया था।

जिला न्यायधीशों से हाईकोर्ट ने मांगा संपत्ति का ब्यौरा

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के जिला सत्र न्यायालयों में पदस्थ सत्र न्यायधीशों व अन्य वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को हाईकोर्ट ने अपनी सम्पत्ति का विवरण घोषित करने का निर्देश दिया है। इन सभी से बीते वर्ष तक की स्थिति में वार्षिक ब्यौरा मांगा गया है। छत्तीसगढ़ के बालोद, बलौदा-बाजार, बस्तर में जगदलपुर, बेमेतरा, बिलासपुर, बलरामपुर रामानुजगंज, धमतरी, दुर्ग, रायपुर, जशपुर, कबीरधाम (कवर्धा), मुंगेली , कोरबा, रायगढ़, राजनांदगांव, सरगुजा, (अंबिकापुर, सूरजपुर, महासमुंद, उत्तर बस्तर (कांकेर), कोरिया (बैकुंठपुर), जांजगीर-चांपा, कोंडागांव, दक्षिण बस्तर (दंतेवाडा) में पदस्थ जिला न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों द्वारा संपत्ति की घोषणा प्रस्तुत की जानी है। इस संबंध में हाईकोर्ट ने सभी जिला न्यायधीशों को पत्र प्रेषित कर अपने जिले में पदस्थ सभी न्यायिक अधिकारियों से निर्धारित प्रारूप में 31 दिसंबर 2024 तक सम्पत्तियों की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित पीडीएफ प्रारूप में हाईकोर्ट रजिस्ट्री में ई-मेल 28 फरवरी तक करना होगा।

जादू-टोना करने के आरोप में छह लोग गिरफ्तार

मलकानगिरी। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में ओरकेल पुलिस सीमा के अंतर्गत चितापारी-4 गांव में धार्मिक समारोह की आड़ में जादू-टोना करने के आरोप में पुलिस ने रविवार को छत्तीसगढ़ के छह लोगों को गिरफ्तार किया। रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय प्रशासन ने गांव में तीन दिवसीय धार्मिक समारोह की अनुमति दी थी। हालांकि, दूसरे दिन आरोपियों ने अनुष्ठान के नाम पर जादू-टोना किया। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए ओरकेल पुलिस ने एक विशेष टीम बनाई और मौके पर छापा मारा। आरोपी खाट पर जादू-टोना करते पाए गए। उन्होंने एक बुजुर्ग महिला पर भी डायन होने का आरोप लगाया और उसे गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया। पुलिस ने बुजुर्ग महिला को बचाया और छह जादूगरों को गिरफ्तार किया। खाट समेत जादू-टोने की रस्मों में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें जब्त कर ली गईं। पुलिस ने आरोपियों द्वारा इस्तेमाल की गई कार भी जब्त कर ली। सभी को स्थानीय अदालत में पेश किया गया।

डा. प्रवेश शुक्ला को उच्च न्यायालय से मिली राहत

बिलासपुर। छत्तीसगढ उच्च न्यायालय ने सहायक प्राध्यापक गैस्ट्रो सर्जरी विभाग डा प्रवेश शुक्ला को बड़ी राहत देते हुए राज्य शासन द्वारा उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को निरस्त कर दिया है। उल्लेखनीय है कि शराब घोटाले के आरोपी जेल की सलाखों के पीछे बंद अनवर ढेबर को इलाज कराने के लिए रायपुर सेंट्रल जेल से जिला अस्पताल लाया गया था। जिला अस्पताल में लोअर इंडोस्कोपी मशीन के खराब होने के कारण डा प्रवेश शुक्ला ने उसे एम्स रेफर कर दिया था। इसको लेकर राज्य शासन ने सेवा में कमी और अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए डा प्रवेश शुक्ला की सेवा समाप्त करने के साथ ही गोलबाजार थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। डा. शुक्ला ने अपने वकील अधिवक्ता संदीप दुबे के माध्यम से उच्च न्यायालय में स्वास्थ्य विभाग के अफसरों पर आरोप लगाते हुए कहा कि बगैर विभागीय जांच कराए और उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए बिना कलंकपूर्ण आदेश पारित कर उनकी सेवा समाप्त किये जाने के आदेश को लेकर याचिका दायर की थी।

उचित मूल्य दुकान चंगेरी के संचालन हेतु आवेदन आमंत्रित

गौरेला पेंड्रा मरवाही। मरवाही अनुविभाग के अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान चंगेरी के आबंटन के लिए 10 जनवरी 2025 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य दुकानों के संचालन के लिए निर्धारित एजेंसी आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, ग्राम पंचायत, महिला स्व सहायता समूह, लघु वनोपज समिति एवं अन्य सहकारी संस्था को आबंटित किया जाना है। अतः जो एजेंसी (महिला स्व सहायता समूह को तीन माह पूर्व छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है) शासकीय उचित मूल्य दुकान का संचालन करना चाहते हैं, वे अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ 10 जनवरी 2025 तक कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मरवाही में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

नकली उद्यानिकी विभाग अधिकारी ने कई गांववालों को लगाया चूना

गौरेला पेंड्रा मरवाही। रविवार को गौरेला थाना क्षेत्र के कई गांव के लोग थाने पहुंचे और खुद के साथ ठगी होने की शिकायत दर्ज कराई। ठेंगाडांड, केवची, पकरिया दमदम, सहित कई गांव के लोगों ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके गांव में एक व्यक्ति आया और खुद को उद्यानिकी विभाग का अधिकारी बताकर उन्हें सस्ते में कृषि उपकरण देने का झांसा दिया।

उद्यानिकी विभाग का अधिकारी बताकर ठगी- ग्रामीणों के मुताबिक आरोपी का नाम रामदास रैदास है। जो गौरेला के धनगवा का रहने वाला है। महीनेभर पहले से वह गांव गांव घूमकर लोगों को शासन की योजनाओं के बारे में बताता था। आरोपी ने उन्हें सस्ते दर पर कृषि उपकरण जैसे धन कुट्टी मशीन, सोलर पंप, फेंसिंग जाली देने का झांसा दिया और गांव के कई लोगों से 5 हजार रुपये से लेकर 30 हजार रुपये ऐंठ कर ले गया। जब कई दिन बीत गए तो ग्रामीणों को अपने साथ ठगी का

एहसास हुआ। जिसके बाद ग्रामीण थाने पहुंचे।

सुखदेव सिंह ने बताया कि रामप्रसाद रैदास नाम से गांव में जा जाकर उद्यानिकी विभाग का अधिकारी बताकर योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर ठगी करता था। हमारे गांव के कई लोगों के साथ ही आसपास के गांव वालों के साथ भी ठगी कर चुका है। गौरा से सभी आए हैं। 5 से 7 लाख रुपये की ठगी कर चुका है।

रिपोर्ट लिखाने आए कमलेश बताते हैं कि बैगा लोगों के लिए अच्छी स्कीम है। 6000 रुपये की मांग की। 3000 रुपये दिया था। जीवन यादव बताते हैं कि कृषि विभाग का अधिकारी बताकर चक्की दिलाने की बात बोलकर 5000 रुपये लेकर फरार हो गया। कई लोगों के साथ उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। कई लोगों को महीने भर पहले इस तरह का झांसा दे चुका था।

गौरेला थाना प्रभारी नवीन बोडकर ने बताया कि रूपनडांड, ठेंगाडांड, केवची, पकरिया दमदम के लोगों को एक व्यक्ति धनकुट्टी मशीन, सौर ऊर्जा, मोटरपंप। जाली फेंसिंग सस्ते दर में दिलाने का झांसा देकर 5 हजार रुपये से 30 हजार रुपये लेकर ठगी किया। जब काफी लंबा समय हो गया तब लोगों को अपने साथ ठगी का एहसास हुआ। लगभग 25 से 30 किसानों के साथ ठगी हुई है। ये संख्या और बढ़ सकती है। आरोपी रामदास रैदास के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने दावा किया कि उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

डॉक्टर की सेवा समाप्त करने का आदेश कलंकपूर्ण : हाईकोर्ट

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने एक चिकित्सक की याचिका पर सुनवाई के बाद अपने फैसले में स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के रवैये पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि यह एक कलंकपूर्ण आदेश है, जिसमें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के उल्लंघन का स्पष्ट उल्लेख है। लिहाजा याचिकाकर्ता को विभागीय जांच में शामिल कर उसकी सुनवाई की जानी चाहिए, जो वर्तमान मामले में नहीं की गई है। मामला शराब कारोबारी अनवर ढेबर को लेकर डॉ। प्रवेश शुक्ला पर लगाए आरोप का है। डॉ। शुक्ला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

दरअसल, शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर को इलाज कराने के लिए रायपुर सेंट्रल जेल से जिला अस्पताल लाया गया था, जहां लोअर इंडोस्कोपी मशीन के खराब होने के कारण डॉ। प्रवेश शुक्ला ने उसे एम्स रेफर कर दिया था। मामले में सेवा में कमी और अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए राज्य

शासन ने उसकी सेवा समाप्त करने के साथ ही गोलबाजार थाने में एफआईआर दर्ज करा दी, जिसे लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिसमें कहा है कि बगैर विभागीय जांच कराए और उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए बिना कलंकपूर्ण आदेश पारित कर उसकी सेवा समाप्त कर दिया गया है। ऐसे आदेश से उसका कैरियर चौपट हो जाएगा।

सहायक प्राध्यापक गैस्ट्रो सर्जरी विभाग डॉ। प्रवेश शुक्ला ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 08 अगस्त 2024 को अस्पताल अधीक्षक एवं एकेडेमिक इंचार्ज द्वारा आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उसकी सेवा शासकीय दाऊ कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़ ('डीकेएस अस्पताल') में सहायक प्रोफेसर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के पद से समाप्त कर दी गई है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि वह एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। उसके पास एमबीबीएस, एमएस (सर्जरी), डॉ. एनबी (डॉक्टरेट ऑफ नेशनल बोर्ड सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी) सुपर स्पेशलिस्ट कोर्स की डिग्री है और वह गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्जन के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध डॉक्टर है। प्राइवेट प्रैक्टिस के बजाय उसने सरकारी अस्पताल में काम करने को प्राथमिकता दी है। वह छत्तीसगढ़ का एकमात्र डॉक्टर है जो डीकेएस अस्पताल में तैनात था।

संक्षिप्त समाचार

जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी : मुख्यमंत्री साय

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज बीजापुर जिले के कुटरू में नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी ब्लास्ट में 8 जवानों सहित एक वाहन चालक के शहीद होने की दु:खद घटना पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मेरी संवेदनाएं शहीदों के परिजनों के साथ है। ईश्वर से शहीद जवानों की आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर में चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान से नक्सली हताश हैं और विचलित होकर ऐसी निंदनीय और कायराना हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और नक्सलवाद के खात्मे के लिए हमारी यह लड़ाई मजबूती से जारी रहेगी।

महापौर तथा अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण प्रक्रिया आज

रायपुर। नगरीय निकायों में आम निर्वाचन के लिए नगर निगमों में महापौर तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में अध्यक्ष के पदों के लिए आरक्षण प्रक्रिया 7 जनवरी 2025 को संपादित की जाएगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा पूर्व में इसके लिए 27 दिसम्बर 2024 की तिथि निर्धारित की गई थी। अपरिहार्य कारणों से 27 दिसम्बर को होने वाली आरक्षण की कार्यवाही को स्थगित कर इसके लिए अब 7 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई थी। रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में 7 जनवरी को सवेरे साढ़े दस बजे से आरक्षण की प्रक्रिया संपादित की जाएगी। आरक्षण की कार्यवाही के अवलोकन के इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर उपस्थित रह सकते हैं। उल्लेखनीय है कि नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 में प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के लिए छत्तीसगढ़ नगर पालिका (महापौर तथा अध्यक्ष के पद का आरक्षण) नियम 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत नगर पालिक निगमों के महापौर तथा नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायत के अध्यक्षों के पदों के आरक्षण की कार्यवाही संपादित की जा रही है।

कलेक्टर गौरव ने सम्हाला नगर निगम रायपुर में प्रशासक की कमान

रायपुर। रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने सोमवार को नगर पालिक निगम रायपुर में प्रशासक के तौर पर पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा समेत अन्य अधिकारी - कर्मचारी उपस्थित थे। प्रशासक को चार्ज न देने का दावा करने वाले महापौर एजाज ढेबर इस अवसर पर उपस्थित नहीं थे। निगम कर्मचारियों ने कलेक्टर सिंह का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया।

पुलिस भर्ती में भेदभाव पर फूटा अभ्यर्थियों का गुस्सा

रायपुर। पुलिस भर्ती का एक विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है कि अब दूसरा विवाद शुरू हो गया है। अबकी बार माना पुलिस कैंप में हो रही पुलिस भर्ती को लेकर विवाद है, जिसमें फिजिकल टेस्ट में भेदभाव का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थी सड़क पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। माना पुलिस कैंप में पुलिस विभाग में ड्राइवर के लिए हो रही भर्ती में शामिल होने के लिए प्रदेश के अलग-अलग जिलों से अभ्यर्थी आए हैं, उनका आरोप है कि एडमिट कार्ड होने के बावजूद सीट नहीं है कहकर उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा है। यही नहीं अभ्यर्थियों का आरोप है कि ओबीसी और जनरल का पद नहीं होने का हवाला देकर उन्हें भर्ती प्रक्रिया से वंचित किया जा रहा है। रही-सही कसर फिजिकल टेस्ट में भेदभाव कर पूरी की जा रही है। भर्ती में इस भेदभाव को लेकर अभ्यर्थी सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं।

राज्य में 4 लाख 45 हजार 897 नागरिकों का ऑनलाईन प्रकृति परीक्षण किया गया

रायपुर। भारत सरकार आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में 29 अक्टूबर 2024 को नवम् राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश का प्रकृति परीक्षण अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान का प्रथम चरण संविधान दिवस दिनांक 26 नवम्बर 2024 से पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर 2024 तक संपन्न हुआ। ऑनलाईन अभियान के अंतर्गत मोबाईल एप्लीकेशन के द्वारा देश के एक करोड़ नागरिकों के आयुर्वेदीय सिद्धांत अनुसार प्रकृति (वात-पित्त-कफ) परीक्षण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। राज्य में 25 दिसंबर 2024 तक आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से जुड़े कुल 3,551 महाविद्यालयीन शिक्षकों, चिकित्सकों, छात्रों, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों तथा निजी चिकित्सकों द्वारा बतौर स्वयंसेवक (वालेंटियर) कुल 4,45,897 नागरिकों का ऑनलाईन प्रकृति परीक्षण किया गया। छत्तीसगढ़ में इस अभियान को काफी अच्छा प्रतिसाद मिला तथा राज्य का प्रदर्शन बिहार, ओड़िशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, उत्तराखण्ड जैसे अनेक राज्यों की तुलना में काफी बेहतर रहा। अभियान के प्रथम चरण का समापन 25 दिसंबर 2024 को माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मुख्य आतिथ्य में जशपुर जिले के कुनकुरी में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को प्रकृति परीक्षण कार्ड भेंट किया गया।

सीएम साय ने गरियाबंद को दी 338 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात

■ **पीएम जन-मन योजना से मिले चार नये हॉस्टल**

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पीएम जनमन योजना के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों के जीवन में विकास का उजियारा लाने की बड़ी पहल की है। पीएम जनमन योजना के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। गरियाबंद विशाल वन क्षेत्र और प्राकृतिक सुंदरता से समृद्ध जिला है। यहां बड़ी संख्या में विशेष पिछड़ी जनजातियां रहती हैं, जिनकी विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार मोदी की गारंटी के हर वायदे को पूरा कर रही है। ये बातें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गरियाबंद जिले के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित आमसभा में कहीं। इस दौरान सीएम ने गरियाबंद को 338 करोड़ रुपए के 193 कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन किया।

इनमें 119 करोड़ रुपए के 44 कार्यों का लोकार्पण और 219 करोड़ रुपए के 149 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है। उन्होंने इस मौके पर जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र देवभोग-झाखरपारा के 36 गांवों के लोगों की सुविधा के लिए बेलाट नाले पर पुल निर्माण की घोषणा की। कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में 99 हितग्राहियों को कृषि पंप, मछली जाल सहित एक करोड़ 27 लाख रूपये विभिन्न सामग्रियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों में पात्र लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपा।

इस दौरान साय ने कहा कि पीएम जनमन योजना अंतर्गत 2 हजार 528 से अधिक आवास गरियाबंद में हमारे कमार जनजाति के लोगों के लिए स्वीकृत किये गये हैं। गरियाबंद जिले में ही इस योजना के माध्यम से 58 करोड़ रुपए की लागत से 49 सड़कें बन रही हैं। सड़कों के पूर्ण होने से कमार जनजाति की बसाहटें अब

मुख्यधारा से जुड़ जाएगी, कमार जनजाति के बच्चे अब आसानी से उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। कमार बसाहटों तक आसानी से जरूरत पड़ने पर एंबुलेंस पहुंच पाएगी।

उन्होंने कहा कि जब हमने कुंभ मेले का आयोजन राजिम में आरंभ कराया था तब त्रिवेणी संगम की इस नगरी में पूरे देश से संतों का समागम हुआ। राजिम का यश और बढ़ा। दुर्भाग्य से पूर्ववर्ती सरकार ने इसकी गरिमा कम कर दी।

हमारी सरकार ने इसे फिर से उसी भव्य रूप में आरंभ किया है। अगले महीने राजिम कुंभ का आयोजन पुन: होगा। इस बार भी पूरी भव्यता से इस सुंदर समारोह का आयोजन हम करेंगे। राजिम में संत-समागम होगा और हम सब इस सत्संग का लाभ प्राप्त करेंगे। सिकासार कोडार लिंक परियोजना के सर्वे का कार्य तेजी से हो रहा है। 112 किमी अंडर ग्राउंड नहर लाइनिंग का कार्य पूरा होने पर गरियाबंद जिले के हजारों किसान लाभान्वित होंगे। सुपेबेड़ा के किडनी के मरीजों के लिए डायलिसिस सुविधा के लिए जिला मुख्यालय एवं देवभोग में डायलिसिस सेंटर आरंभ किये गये हैं। इस समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए स्वास्थ्य विभाग को अनुसंधान के निर्देश दिए गए हैं।

सीएम ने गरियाबंद प्रवास के दौरान केन्द्र सरकार की विशेष योजना 'पीएम जनमन' के तहत 4 नये छात्रावास भवनों का शिलान्यास किया। ये छात्रावास धवलपुर, जिडार, जुगाड़ और पीपरछेड़ी में बनाए जाएंगे। इन छात्रावासों को पूर्ण करने के लिए 10 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की गई है। वनांचल गरियाबंद जिले में कमार विशेष पिछड़ी जनजाति निवास करती है। इन वर्गों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए पीएम जनमन योजना के तहत इन छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है।

साय का जांजगीर चांपा दौरा, करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन

जांजगीर चांपा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जांजगीर चांपा जिले में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन कर रहे हैं। सीएम साय नए साल पर जिले को कुल 183.41 करोड़ रुपए की लागत के 285 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन कर रहे हैं। इसमें 118.39 करोड़ की लागत के 112 कार्यों का भूमिपूजन और 65.02 करोड़ के 173 कार्यों का लोकार्पण शामिल हैं।

सीएम विष्णुदेव साय 65.02 करोड़ की लागत के 173 कार्यों का लोकार्पण कर रहे हैं। जिसमें लोक निर्माण विभाग के 28.17 करोड़ रुपए की लागत से 21 कार्य, सीजीएमएससी के 7.56 करोड़ रुपए की लागत से 8 कार्य, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के 19.41 करोड़ रुपए की लागत से 114 कार्य, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क के 2.86 करोड़ रुपए की लागत से 8 कार्य, गृह निर्माण मण्डल के 1.19 करोड़ रुपए की लागत से 2 कार्य, जनपद पंचायत नवागढ़ 2.32 करोड़ रुपए की लागत से 8 कार्यों का लोकार्पण कर रहे हैं।

सीएम नगर पालिका परिषद अकलतरा 0.47 करोड़ रुपए की लागत से 1 कार्य, जनपद पंचायत बम्हनीडीह 0.62 करोड़ रुपए की लागत से 2 कार्य, जनपद पंचायत पामगढ़ 1 करोड़ रुपए की लागत से 4 कार्य, जनपद पंचायत अकलतरा 0.68 करोड़ रुपए की लागत से 2 कार्य, जनपद पंचायत बलौदा 0.60 करोड़ रुपए की लागत से 2 कार्य और कृषि उपज मंडी समिति चांपा 0.13 करोड़ रुपए की लागत से 1 कार्य का लोकार्पण शामिल है।

सीएम साय 118.39 करोड़ की लागत के 112 कार्यों का भूमिपूजन कर रहे हैं। जिसमें लोक निर्माण विभाग के 8.16 करोड़ रुपए की लागत से 4 कार्य, जल संसाधन संभाग जांजगीर के 31.06 करोड़ रुपए की लागत से 14 कार्य, नगर पंचायत राहौद के 26.19 करोड़ रुपए की लागत से 1 कार्य, सीजीएमएससी के 16.63 करोड़ रुपए की लागत से 1 कार्य, कार्य। अभि. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 9.14 करोड़ रुपए की लागत से 11 कार्य, गृह निर्माण मण्डल के 6 करोड़ रुपए की लागत से 3 कार्य, जनपद पंचायत नवागढ़ 4.31 करोड़ रुपए की लागत से 12 कार्य, नगर पालिका परिषद चांपा 5.82 करोड़ रुपए की लागत से 5 कार्य, नगर पालिका परिषद अकलतरा 1.63 करोड़ रुपए की लागत से 8 कार्य शामिल है।

इसके अलावा गर पंचायत पामगढ़ 2.04 करोड़ रुपए की लागत से 13 कार्य, जनपद पंचायत बलौदा 1.54 करोड़ रुपए की लागत से 8 कार्य, जनपद पंचायत बम्हनीडीह 0.70 करोड़ रुपए की लागत से 2 कार्य, जनपद पंचायत पामगढ़ के 0.56 करोड़ रुपए की लागत से 3 कार्य, नगर पंचायत नरियरा में 1.15 करोड़ रुपए की लागत से 7 कार्य, जनपद पंचायत अकलतरा 0.29 करोड़ रुपए की लागत से 1 कार्य, नगर पंचायत सारागांव 0.20 करोड़ रुपए की लागत से 1 कार्य, कृषि उपज मंडी समिति अकलतरा के 2.26 करोड़ रुपए की लागत से 16 कार्य, महिला एवं बाल विकास के 0.60 करोड़ रुपए की लागत से 1 कार्य एवं कृषि उपज मंडी चांपा समिति के 0.12 करोड़ रुपए की लागत से 1 कार्य का भूमि पूजन भी शामिल है।

रायपुर शहर-रायपुर ग्रामीण में रमेश ठाकुर और श्याम नारंग को मिली जिम्मेदारी

■ **भाजपा के 15 जिलाध्यक्ष नियुक्त**

रायपुर। बीजेपी संगठन महापर्व के तहत चल रहे संगठनात्मक चुनाव के प्रदेश निर्वाचन अधिकारी खूबचंद पारख ने 15 जिलों के लिए जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। भाजपा रायपुर शहर जिला की कमान रमेश ठाकुर को दी गई है। वहीं श्याम नारंग को रायपुर ग्रामीण जिला की जिम्मेदारी सौंपी गई है। छह जनवरी को बाकी जिला अध्यक्षों का चुनाव होगा। प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव दस जनवरी से पहले होने का है।

बता दें कि 15 जिलों में 37 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जहां से 37 प्रदेश प्रतिनिधियों का निर्वाचन हो गया है। 18 प्रदेश प्रतिनिधि, जो एससी-एसटी और महिला वर्ग से आते हैं के भी नाम तय किया जा चुके हैं जिनके चुनाव की प्रक्रिया प्रदेश से होगी। इस तरह से 55 प्रदेश प्रतिनिधियों का चुनाव हो चुका है। भाजपा संगठन चुनाव प्रदेश निर्वाचन अधिकारी पारख ने बताया कि छह जनवरी को बाकी जिला अध्यक्षों का चुनाव होगा। प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव दस जनवरी से पहले होने का है।

भाजपा जिलाध्यक्षों की सूची-

रायपुर (शहर) जिला - रमेश ठाकुर
रायपुर (ग्रामीण) जिला - श्याम नारंग
कांकेर जिला - महेश जैन
भिलाई जिला - पुरुषोत्तम देवांगन
दुर्ग जिला - सुरेंद्र कौशिक
बीजापुर जिला - घासीराम नाग
गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला - लालजी यादव
बालोद जिला - चेमन देशमुख
सूरजपुर जिला - मुरलीधर सोनी
मुंगेली जिला - दीनानाथ केशरवानी
रायगढ़ जिला - अरुणधर दीवान
बलरामपुर जिला - ओमप्रकाश जायसवाल
जशपुर जिला - भरत सिंह

चौकी मोहला मानपुर जिला- नम्रता सिंह
कोरबा जिला - मनोज शर्मा

गरियाबंद जिला अध्यक्ष बने अनिल चंद्राकर, अंबिकापुर में भारत सिंह सिसोदिया को मिली जिम्मेदारी

छत्तीसगढ़ में लगातार दूसरे दिन भाजपा जिला अध्यक्षों की नियुक्ति जारी है। खबर लिखे जाने तक चार जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान किया गया है। रविवार को 15 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी। वहीं आज गरियाबंद जिला अध्यक्ष की भी घोषणा कर दी गई है। अनिल चंद्राकर को गरियाबंद जिला अध्यक्ष बनाया गया है। भाजपा नवीन कार्यालय में भाजपा चुनाव संगठन प्रभारी श्री चंद सुंदरानी ने प्रदेश मंत्री किशोर महानंद की मौजूदगी में नाम की घोषणा की गई। इस दौरान विधायक रोहित साहू, जिले के सभी मंडल के पदाधिकारियों के अलावा जिले के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे।

भारत सिंह सिसोदिया को सरगुजा बीजेपी का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व में भारत सिंह सिसोदिया किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रह चुके है। वे भाजपा के कार्य समिति सदस्य रह चुके हैं। इसके अलावा भारत सिसोदिया जशपुर के जिला प्रभारी रह चुके है।

सरगुजा और गरियाबंद के साथ महासमुंद जिला अध्यक्ष की घोषणा कर दी गई है। एतराम साहू को महासमुंद का नया जिलाध्यक्ष बनाया गया है। संगठन के जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रदेश महामंत्री रामू रोहरा ने जिला भाजपा कार्यालय मे घोषणा की है। बता दें कि एतराम साहू संगठन मे मीडिया प्रभारी एवं स्काउट एंड गाइड के जिला अध्यक्ष रह चुके है।

वहीं जांजगीर जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी टिकेश्वर गवेल को दी गई है। वर्तमान में टिकेश्वर जिला महामंत्री भाजपा का दावित्व संभाल रहे हैं। पूर्व में वह भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला महामंत्री रह चुके हैं।

जगदलपुर भाजपा जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी वेद प्रकाश पांडे को दी गई है। इससे पहले रूपसिंह मंडावी ने इस दायित्व को संभाला है। बस्तर संभाग के भाजपा अध्यक्ष कई जिलों में बदले गए है।

इसी प्रकार मनेन्द्रगढ़-एम ।सी ।बी जिला अध्यक्ष चम्पा देवी पावले को बनाया गया है। एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ के जिला भाजपा कार्यालय में जिला निर्वाचन अधिकारी कमल भान सिंह ने घोषणा की। छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ जिला के भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे।

बिलासपुर शहर जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दीपक सिंह ठाकुर को दी गई है। दीपक पूर्व में युवा मोर्चा में पदाधिकारी रह चुके हैं।

वहीं मोहित जायसवाल को बिलासपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष बनाया गया है। मोहित जायसवाल भाजपा महामंत्री हैं। जिले के संगठनात्मक विभाजन के बाद मोहित जायसवाल पहले ग्रामीण जिलाध्यक्ष बने हैं।

छत्तीसगढ़ में नए नगरीय निकायों का गठन

रायपुर। छत्तीसगढ़ में इस साल नगरीय निकाय चुनाव होना है। तैयारी को लेकर फुल तैयारी चल रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में पिछले साल जनवरी से दिसम्बर के बीच नौ नए नगरीय निकायों का गठन किया गया है। वहीं सात नगर पंचायतें का प्रमोशन कर उन्हें नगर पालिका के रूप में बदल दिया गया है। पिछले वर्ष गठित नगरीय निकायों को मिलाकर अब कुल 192 नगरीय निकाय हो गए हैं। इनमें 14 नगर निगम, 54 नगर पालिका और 124 नगर पंचायत शामिल हैं।

स्थानीय रहवासियों की मांगों पर राज्य शासन ने संवेदनशीलतापूर्वक विचार करते हुए जन-आकांक्षाओं को पूरा करने नए नगरीय निकायों के गठन को मंजूरी दी है। इससे उभरते शहरों के रूप में विकसित हो रहे कस्बों में शहरी सुविधाएं जुटाने के कामों को और गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य की कस्बाई आवादी की मांग और उभरते शहरों के अनुरूप अधोसंरचनात्मक विकास को गति देने बीते कैंलेडर वर्ष 2024 में नौ नए नगर पंचायतों का गठन किया गया है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्रीअरुण साव की पहल पर स्थानीय जन-आकांक्षाओं को पूर्ण करने तथा उन्हें मूर्त रूप देने नए नगरीय निकायों के गठन तथा ज्यादा आबादी वाले नगर पंचायतों के नगर पालिकाओं में उन्नयन की त्वरित कार्यवाही की गई है।

जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों की मांग पर वर्ष-2024 में जनवरी से दिसम्बर के बीच राजनांदगांव जिले के लाल बहादुर नगर और घुमका, मुंगेली के जरहागांव, कोरिया के पटना, बेमेतरा के कुसमी, गरियाबंद के देवभोग, सूरजपुर के शिवनंदनपुर, जांजगीर-चांपा के बम्हनीडीह और बालोद जिले के पलारी को नगर पंचायत बनाया गया है।

वहीं गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के गौरेला नगर पंचायत और पेंड्रा नगर पंचायत का नगर पालिका के रूप में उन्नयन किया गया है।

रुचिर गर्ग ने दिया कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा

रायपुर। पत्रकारिता छोड़ राजनीति में आने वाले रुचिर गर्ग फिर से पत्रकारिता में लौटने वाले है। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष दीपक बैज को भेज को भेजते हुए लिखा है कि विन्रमतापूर्वक आपको सूचित कर रहा हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ । दरअसल, मैं किसी भी तरह की सक्रिय अथवा निष्क्रिय राजनीति से अलग होकर एक बार फिर पत्रकारिता में ही संभावनाएं तलाशना चाहता हूँ ।

जब मैंने पत्रकारिता से अवकाश लेकर राजनीति की राह पकड़ी थी तब भी मेरे लिए लक्ष्य धर्मनिरपेक्षता और संवैधानिक मूल्यों के हक में खड़े रहना था, और आज भी मेरी प्रतिबद्धता इन मूल्यों के प्रति उतनी ही गहरी है । मैं कामना करता हूँ कांग्रेस पार्टी इस देश की महान स्वतंत्रता संग्राम से उपजे मूल्यों के साथ ही लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के प्रति हमेशा ही प्रतिबद्ध रहे । गौरतलब है कि रुचिर गर्ग छत्तीसगढ़ के जाने-माने पत्रकारों में से एक हैं उन्होंने प्रिंट और टीवी मीडिया में सालों तक अपनी सेवाएं दी हैं । 2018 विधानसभा चुनाव के पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया था और भूपेश बघेल के साथ जुड़े रहे। 5 साल मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार के तौर पर उन्होंने काम किया इस दौरान पत्रकारों की हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने लिए थे । जिसमें कई पत्रकारों को झूठे मामले में जेल भी भेजा गया था और कई पत्रकारों पर झूठा अपराध दर्ज भी किया गया था। वहीं पत्रकार सुरक्षा कानून का ड्राफ्ट भी उन्होंने तैयार कराया था। हालांकि कैबिनेट से मंजूरी और विधानसभा से विधेयक पास होने के बाद भी यह कानून अब तक राजभवन में ही अटका हुआ है ।

हैदराबाद से आरोपी सुरेश चंद्राकर गिरफ्तार

जगदलपुर। बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद से फरार चल रहे आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को बीती रात एसआईटी की टीम ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। जिसे अपने साथ बीजापुर लाया जा रहा है। जहां आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने सुरेश की पत्नी को कांकेर जिले से गिफ्तार किया गया है।

पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या में शामिल तीन आरोपी रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए हैं। वहीं घटना के बाद से फरार चल रहे मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को भी एसआईटी की टीम ने पकड़ लिया है। पुलिस ने सुरेश चंद्राकर के कुछ बैंक अकाउंट को सीज किया है। वहीं प्रशासन ने सुरेश चंद्राकर द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कंस्ट्रेक्शन डंपिंग यार्ड बना रखा था। उसे भी बीते दिनों प्रशासन ने जेसीबी चलाकर हटा दिया।

जानकारी के लिए बता दें कि माओवादियों के प्रवक्ता समता ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या को ले कर एक प्रेस नोट जारी किया है। जिसमें माओवादियों ने पत्रकार की हत्या की कड़ी निंदा की है और खेद भी व्यक्त किया है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या की जांच की मांग की है ।मुकेश के द्वारा घटिया सड़क निर्माण को लेकर एक खबर प्रकाशित की गई थी। जिसके बाद ठेकेदार का भाई रितेश चंद्राकर एक जनवरी की रात को मुकेश को बीजापुर की चट्टानपारा स्थित ठेकेदार सुरेश चन्द्रकार के बाड़े में पहुंचा था। जहां रात को भोजन करने के दौरान आरोपी रितेश चन्द्रकार ने मुकेश चन्द्रकार से पारिवारिक सबंध होने के बावजूद हमारे काम में सहयोग की बजाय बाधा डालने की बात कही। इसी दौरान बहस हो गई।

इस दौरान आरोपी रितेश चन्द्रकार ने बाड़े में मौजूद सुपरवाईजर महेन्द्र रामटेके के साथ मिलकर मुकेश चन्द्रकार के सिर, छाती, पेट और पीठ पर लोहे की रॉड से वार कर हत्या कर दी थी। शव को ठीकाने लगाने के लिए पास के सेप्टीक टेंक में डाल दिया। उसे स्लेब के ढक्कन से बंद कर दिया था।

घटना के बाद रितेश ने हत्या की बात बताते हुए अपनी कार को ले जाकर रायपुर एयरपोर्ट के पास खड़ा किया और दिल्ली भाग गया, जबकि सुरेन्द्र अपनी कार से हैदराबाद भाग गया था। पुलिस ने इस मामले में रितेश को दिल्ली और अन्य आरोपियों को बीजापुर से गिरफ्तार किया गया था। जबकि मुकेश की हत्या के बाद बनाई गई एसआईटी टीम ने सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से गिरफ्तार कर उसे बीजापुर लाया जा रहा है,जहां आगे की कार्रवाई की जा रही है। सुरेश की पत्नी को कांकेर जिले से गिफ्तार किया गया है ।बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्रकार की हत्या के मामले में हत्यारों की गिरफ्तारी के बाद मुख्य आरोपी और ठेकेदार सुरेश चंद्रकार के अवैध कब्जे को धरसाई करने की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी ठेकेदार का गंगालूर सड़क पर पांच एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा था। ठेकेदार के फार्म हाउस पर बुलडोजर चला गया है। दूसरी ओर रायपुर एयरपोर्ट से आरोपी रितेश चंद्राकर की गाड़ी जब्त की गई है। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के सभी बैंक खाते और एटीएम ट्रांजैक्शन को सीज किया गया है। किसी भी तरह का डिजिटल ट्रांजेक्शन न कर पाए इस पर भी नजर रखी गई है। बीजापुर स्थित वन विभाग की जमीन पर ठेकेदार द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को खाली करवाने वन विभाग की टीम रवाना हुई। वहीं आरोपी के सभी अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला।

लीवर के चार टुकड़े, पांच पसलियां और गर्दन तोड़ी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में बर्बरता से हुई पत्रकार मुकेश चंद्राकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में दिल दहलाने वाला खुलासा हुआ है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि उसे बेरहमी से मारा गया था। उसे खौफनाक तरीके से मौत दी गई थी। दम निकलने से पहले उसे यातनाएं दी गईं। मुकेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि लीवर चार टुकड़ों में बंट मिला था, उसकी पांच पसलियां और गर्दन की हड्डी टूटी मिली है। इसके अलावा हाथ की हड्डी दो टुकड़ों में टूटी थी। इसके अलावा हार्ट पूरी तरह से फट मिला है। सिर पर भी चोट के 15 गंभीर निशान पाए गए हैं। मुकेश चंद्राकर का मर्डर कर ठेकेदार सुरेश चंद्राकर ने सेप्टिंक टैंक में डाल दिया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जिस डॉक्टर ने मुकेश चंद्राकर के शव का पोस्टमार्टम किया है, उनका कहना है कि मैंने अपने 12 साल के करियर में ऐसा मामला पहले कभी नहीं देखा। मुकेश की हत्या बेहद बेरहमी से की गई है। इस हत्याकांड ने पूरे देश और प्रदेश को हिला कर रख दिया है। उधर, मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद से फरार चल रहे आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को बीती रात एसआईटी की टीम ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। जिसे अपने साथ बीजापुर लाया जा रहा है। जहां आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने सुरेश की पत्नी को कांकेर जिले से गिफ्तार किया गया है।

सुरेश के बैंक अकाउंट सीज किए गए

पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या में शामिल तीन आरोपी रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए हैं। वहीं घटना के बाद से फरार चल रहे मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को भी एसआईटी की टीम ने पकड़ लिया है। पुलिस ने सुरेश चंद्राकर के कुछ बैंक अकाउंट को सीज किया है।

आपको बता दें कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर (33) एक जनवरी को अचानक लापता हो गए थे। तीन जनवरी को बीजापुर शहर के चट्टानपारा बस्ती में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की संपत्ति के सेप्टिक टैंक से मुकेश का शव बरामद किया गया था। जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है।

देश के डिजिटल भविष्य का नया स्वरूप

अश्विनी वैष्णव

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के 'भविष्य के शिखर सम्मेलन' में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, 'जब हम वैश्विक भविष्य के बारे में बात करते हैं, तो मानव केंद्रित दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए।' उनके ये शब्द लोगों को पहले रखने के भारत के दृष्टिकोण को प्रमुखता से दर्शाते हैं। इस दर्शन ने डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण (डीपीडीपी) नियम, 2025 के मसौदे को आकार देने में हमारे प्रयासों का मार्गदर्शन किया है। इसे अंतिम रूप दिए जाने के बाद डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 लागू हो जायेगा, जो नागरिकों के व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा के अधिकार की रक्षा के लिए वस्तुत: हमारी प्रतिबद्धता को ही रेखांकित करेगा। यह सशक्तीकरण का एक नया युग है। भारतीय नागरिक डीपीडीपी नियम, 2025 के केंद्र में हैं। डाटा के बढ़ते वर्चस्व वाली दुनिया में हमारा यह स्पष्ट रूप से मानना है कि व्यक्तियों को शासन की रूपरेखा के केंद्र में रखना अनिवार्य है। ये नियम दरअसल इस देश के नागरिकों को कई अधिकारों से सशक्त करते हैं। उदाहरण के लिए, सूचना आधारित सहमति, डाटा मिटाने की सुविधा और डिजिटल रूप से नामांकित व्यक्ति को नियुक्त करने की क्षमता आदि। यह स्पष्ट है कि इस देश के नागरिक अब उल्लंघनों या अनधिकृत डाटा उपयोग के सामने खुद को असहाय महसूस नहीं करेंगे। इसकी वजह यह है कि अब उनके पास अपनी डिजिटल पहचान को प्रभावी ढंग से सुरक्षित और प्रबंधित करने के लिए आवश्यक उपकरण होंगे। इन नियमों को सरलता और स्पष्टता के साथ तैयार किया गया है, साथ ही, इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक भारतीय, चाहे उनके पास तकनीकी ज्ञान कुछ भी हो, अपने अधिकारों को बखूबी समझ सकता है और उनका प्रयोग कर सकता है। इसमें सहमति स्पष्ट शब्दों में मांगी जाती है, तथा नागरिकों को अंग्रेजी या संविधान में सूचीबद्ध 22 भारतीय भाषाओं में से किसी में भी जानकारी प्रदान करना अनिवार्य किया गया है। यह रूपरेखा दरअसल समावेशिता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के बारे में बताती है। डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया गया है। दरअसल डिजिटल युग में बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता है। इसे मान्यता देते हुए इसके नियम नाबालिगों के व्यक्तिगत डाटा को संसाधित करने के लिए माता-पिता या अभिभावक की सत्यापन योग्य सहमति को अनिवार्य बनाते हैं। ऐसे ही अतिरिक्त सुरक्षा उपाय बच्चों को शोषण, अनधिकृत प्रोफाइल बनाने और अन्य डिजिटल नुकसान से बचाव सुनिश्चित करते हैं। इस अधिनियम के ये प्रावधान भविष्य की पीढ़ी के लिए एक सुरक्षित डिजिटल परिदृश्य बनाने के प्रति हमारे समर्पण को संपूर्णता में दर्शाते हैं। इसमें विनियमन के साथ विकास के संतुलन को साधने की कोशिश की गयी है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था वस्तुत: एक वैश्विक सफलता की गाथा रही है, और हम इस गति को बनाये रखने के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं। हमारी रूपरेखा डिजिटल अर्थव्यवस्था में नवाचार को सक्षम करते हुए नागरिकों के लिए व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा सुनिश्चित करती है। विनियमन पर बहुत अधिक जोर देने वाले कुछ अंतरराष्ट्रीय प्रारूपों के विपरीत हमारा दृष्टिकोण व्यवहारिक और भविष्योन्मुखी है। यह संतुलन सुनिश्चित करता है कि नागरिकों की सुरक्षा की जाये और नवाचार की उस भावना को किसी भी तरह से दबाया न जाये, जो हमारे स्टार्ट-अप और व्यवसायों को प्रेरित करती है। इससे छोटे व्यवसायों और स्टार्ट-अप के लिए अनुपालन बोझ कम हो जायेगा। हितधारकों की अलग-अलग क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए नियमों को वर्गीकृत जिम्मेदारियों के साथ डिजाइन किया गया है। ऐसे में, डाटा विश्वास के मूल्यांकन के आधार पर बड़ी कंपनियों के पास उच्च दायित्व होंगे, जो विकास को बाधित किए बिना जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। इन नियमों के मूल में 'डिजिटल से दर्शन' है। डाटा सुरक्षा बोर्ड मुख्य रूप से एक डिजिटल कार्यालय के रूप में काम करेगा, जिसे शिकायतों का समाधान करने और अनुपालन लागू करने का काम सौंपा गया है। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर हम दक्षता, पारदर्शिता और गति सुनिश्चित करते हैं।

अपनों के निशाने पर कांग्रेस पार्टी

रमेश सर्राफ धमोरा

कांग्रेस पार्टी इन दिनों अपने ही साथी दलों के निशाने पर है। भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों के संयुक्त इंडिया गठबंधन में शामिल विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं द्धारा कांग्रेस पार्टी से इंडिया गठबंधन का नेतृत्व वापस लेने की मांग की जा रही है। इंडिया गठबंधन में शामिल बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी खुले आम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठा रही है। उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कांफ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी को इंडिया गठबंधन के नेता पद से हटाने की मांग की हैं। ममता बनर्जी की मांग के समर्थन में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी अपनी सहमति जताई है। इससे इंडिया गठबंधन की स्थिति लगातार कमजोर हो रही है।

जून 2023 में 26 विपक्षी दलों के साथ बना इंडिया गठबंधन अब टूट के कगार पर खड़ा है। लोकसभा चुनाव में मिली हार और उसके बाद हरियाणा व महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हुई पराजय ने इस गठबंधन को कमजोर कर दिया है। इसी के चलते कांग्रेस के सहयोगी दल ही उसकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाकर अलग राह पकड़ने के संकेत दे रहे हैं। हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने तो कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर निकलवाने तक की धमकी दे दी है। कांग्रेस द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा के बाद से ही आम आदमी पार्टी कांग्रेस से खासी नाराज नजर आ रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस जिस तरह से चुनाव लड़ रही है उससे भाजपा को लाभ मिल रहा है। कांग्रेस नेता अजय माकन व संदीप दीक्षित के बयान विपक्ष को कमजोर करने के लिए भाजपा के कहने पर दिए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद चंद पवार), नेशनल कांफ्रेंस तो खुलकर कांग्रेस की मुखालफत करने लगी है।

हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी जीत तय मानकर आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने से इनकार कर दिया था। जिसके चलते आम आदमी पार्टी ने कई सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़कर 1.8 प्रतिशत वोट

प्राप्त किए थे। जबकि हरियाणा में कांग्रेस को 39.34 प्रतिशत वोट व भाजपा को 39.94 प्रतिशत वोट मिले थे। यदि हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी से समझौता करके चुनाव लड़ती तो निश्चय ही सरकार बन सकती थी। मगर कांग्रेस ने अवसर गवां दिया और वहां भाजपा ने आसानी से तीसरी बार पहले से भी अधिक बहुमत से सरकार बना ली। उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव में तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी थी। जबकि लोकसभा चुनाव कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर ही लड़ा था।

महाराष्ट्र में कांग्रेस नीत महा विकास अघाड़ी की करारी हार होने के बाद शिवसेना (यूबीटी) ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस ने हरियाणा में आप और समाजवादी पार्टी को सीट ना देकर गलती की थी। पार्टी के मुखपत्र सामना में भी लिखा गया कि कांग्रेस नेताओं के अति आत्मविश्वास और घमंड ने हरियाणा में हार के लिए भूमिका निभाई। पार्टी नेता संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस को लगने लगा था कि वह अकेले ही जीत सकती है। इसलिए किसी को भी सत्ता में भागीदार बनाना उचित नहीं समझा था।

पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस कुल 329 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। जिसमें से 145 सीटों पर बिना किसी गठबंधन की अकेले चुनाव लड़ी थी। जिसमें कांग्रेस 37 सीटों पर चुनाव जीती थी। कांग्रेस का बिना किसी दल से गठबंधन में जीत का रेशियो 25.52 प्रतिशत रहा था। जबकि कांग्रेस 184 सीटों पर साथी दलों से गठबंधन करके चुनाव लड़ी थी। इसमें कांग्रेस ने 62 सीट जीती थी और जीत का रेशियो 33.75 प्रतिशत रहा था। इस तरह से देखे तो कांग्रेस पार्टी को अकेले चुनाव लड़ने की बजाय गठबंधन साथियों की बदौलत बड़ी जीत हासिल हुई थी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 13 करोड़ 67 लाख 59 हजार 64 यानी 21.29 प्रतिशत वोट मिले थे। गठबंधन करने के कारण 2019 की तुलना में 2024 में कांग्रेस को 1.91 प्रतिशत अधिक वोट मिले थे।

कांग्रेस पार्टी ने पंजाब, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना व पश्चिम बंगाल में अपने बूते चुनाव लड़ा था। जबकि बिहार, गुजरात हरियाणा झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, पांडिचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। अंडमान निकोबार दीप समूह, आंध्र प्रदेश, दादरा नगर हवेली व दमन दीव, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड ऐसे प्रदेश है जहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल सका था।

हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका महाराष्ट्र में लगा जहां उनकी सीटे 44 से घटकर 16 रह गई। महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना (यूबीटी) व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के साथ महाविकास अघाड़ी बनाकर चुनाव मैदान में उतरी थी। वहां कांग्रेस सबसे अधिक 101 सीटों पर चुनाव लड़ी जिसमें महज 16 सीट ही जीत पाई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 80 लाख 20 हजार 921 वोट मिले जो कुल मतदान का 12. 42 प्रतिशत थे। महाराष्ट्र में कांग्रेस की जीत का स्ट्राइक रेट 15.38 प्रतिशत ही रहा।

संसद का शीतकालीन सत्र का समापन हो चुका है। जिसमें अधिकांश समय कांग्रेस ने अदानी मुद्दे को लेकर संसद नहीं चलने दी। इससे संसद का कार्य पूरी तरह प्रभावित रहा। इसको लेकर भी कांग्रेस की सहयोगी तृणमूल कांग्रेस, सपा ने कांग्रेस को घेरते हुये आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर बहस नहीं होने देना चाहती है तथा सिर्फ अदानी मुद्दे को ही जिंदा रखे हुए हैं। यदि संसद चलती तो कई तरह के मुद्दों पर सरकार को घेरा जा सकता था।

इंडिया अलायंस में जिस तरह की खटपट वर्तमान समय में चलने लगी है वह अलायंस के लिए शुभ नहीं मानी जा सकती है। अलायंस में शामिल दल ही विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व को नकारने लगे है इससे बुरी बात कांग्रेस पार्टी के लिए और क्या हो सकती है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर इंडिया गठबंधन बनाकर केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा को कड़ी टक्कर दी थी। वही गठबंधन अब धीरे-धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है।

आने वाले समय में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं। वहां भाजपा चुनाव जीतने की पूरी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि वह दिल्ली की सत्ता पर फिर से काबिज हो। मगर कांग्रेस का रवैया देखकर आम आदमी पार्टी भी सकते में है। पार्टी के नेता कांग्रेस को वोट कटवा के रूप में देख रहे हैं तथा खुले आम भाजपा की बी टीम के रूप में काम करने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दो सूची जारी कर दी है। शेष सीटों पर भी जल्दी ही प्रत्याशियों के नाम घोषित करने की तैयारी चल रही है। यदि दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी पराजित हो जाती है तो इंडिया गठबंधन के ताबूत में वह आखरी कील साबित होगी।

कांग्रेस को यदि इंडिया गठबंधन को बचाना है तो अपने सहयोगी क्षेत्रीय दलों की भावनाओं को समझ कर फैसला करना होगा। तभी कांग्रेस अपने राजनीतिक वजूद को बचा पाएगी। इंडिया गठबंधन टूटने की स्थिति में कांग्रेस का भी कमजोर होना तय माना जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस अकेले भाजपा से मुकाबला नहीं कर सकती है। गठबंधन के साथी दलों की मदद से ही कांग्रेस मजबूत हो सकेगी इस बात से कांग्रेस नेता भी अच्छे से वाकिफ है।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदों में अष्टादश पुराणों के नाम

(गतांक से आगे...)

जो (दुर्हण:) किसी से भी हनन नहीं होता (तेन) उस दारुमय शरीर की उपासना करने से (परस्तरम्) अतिशय उत्कृत वैकुण्ठ लोक को (गच्छ) प्राप्त हो ! और भी - यत्र देबो जगन्नाथ: परं पारं महोदधे: । बलभद्र: सुभद्रा च तत्रमाममृतं कृधि।। (ऋग्विरिशिष्ट)

अर्थात् - समुद्र के तट पर जहां जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा जी विराजते हैं वहां मुझे अमर कीजिये। वास्तव में अनङ्ग भीमदेव ने मन्दिर का जीर्णोद्धार मात्र किया है और उसीका सूचक सम्वत् लिखा है। माहात्म्य का सम्बन्ध मन्दिर से वा उसके बनाने वाले से नहीं, बल्कि अनादि वेद-प्रतिपाद्य जगन्नाथ जी से है। इसके अतिरिक्त जगन्नाथ शब्द का अक्षरार्थ जगत् संसार का नाथ स्वामी है, इस व्यापक अर्थ को छोड़ कर संकुचित अर्थ ग्रहण वह ईश्वर है । करने में कोई कारण नहीं है। उन्हीं चराचर के नाथ की प्रतिनिधि-प्रतिमा उड़ीसा में स्थित है, जिसका माहात्म्य वेद में वर्णित है, यदि उसीका माहात्म्य स्कन्दपुराण में वर्णित हो तो वह नवीन क्यों ? इसलिये स्कन्दपुराण प्राचीन और व्यासकृत है ।

(14) महाभारत आदिपर्व अध्याय 62 में 233खा 78 कि एक लक्ष श्लोकों वाला पवित्र महाभारत ग्रन्थ वेद-सम्मत है, और यही पुराण है। इससे %अठारह पुराण व्यासकृत हैं, इसकी सर्वथा जड़ कट गई ।

(15) हमें आक्षेप्ता की संस्कृतज्ञता पर दया महाभारत के उक्त श्लोक का यह भाव है ही नहीं, रहे हैं। सुनिये यह श्लोक इस प्रकार है । आती है, क्योंकि जो कि वे फरमा इदं हि वेदै: समितं पवित्रमपि चोत्तमम्। श्रव्याणामुत्तमं चेदं पुराणमृषिसंस्तुतम्।। (महाभारत आदि 62) अर्थात् - यह महाभारत वेद-सम्मत उत्तम और पवित्र है, ऋषियों द्वारा स्तुत यह पुराण श्रवणार्ह है। हम नहीं समझते कि इसमें वह कौनसा शब्द है जिसके द्वारा अठारह पुराण व्यासकृत नहीं यह भाव निकलता हो। **क्रमश: ...**

राजिम भक्तिन माता जयंती

अनिरुद्ध जोशी

भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का राजिम क्षेत्र रायपुर जिले में महानदी के तट पर स्थित है। यहां राजिम या राजीवलोचन भगवान रामचंद्र का प्राचीन मंदिर है। राजिम का प्राचीन नाम पद्मक्षेत्र था। पद्मपुराण के पातालखण्ड अनुसार भगवान राम का इस स्थान से संबंध बताया गया है।

राजिम में महानदी और पैरी नामक नदियों का संगम है। संगम स्थल पर कुलेश्वर महादेव का प्राचीन मंदर है। इस मंदिर का संबंध राजिम की भक्तिन माता से है। कहते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के राजिम क्षेत्र राजिम माता के त्याग की कथा प्रचलित है और भगवान कुलेश्वर महादेव का आशीर्वाद इस क्षेत्र को प्राप्त है।

इसी कारण राजिम भक्तिन माता जयंती 7 जनवरी को राजिम भक्तिन माता की याद में मनाई जाती है। छत्तीसगढ़ के लाखों श्रद्धालु यहां एकत्र होकर माता की पूजा करते हैं। राजिवलोचन मंदिर में लगे शिलालेख के अनुसार कलचुरी राजा जगपाल देव के शिलालेख में माता का उल्लेख मिलता है। 3 जनवरी 1145 को शिलालेख लगाया गया था।

कहते हैं कि यहां साहू समाज के लोग एकत्र होते हैं।

एक स्थानीय दंतकथा के अनुसार इस स्थान का नाम राजिव या राजिम नामक एक तैलिक स्त्री के नाम से हुआ था। कुलेश्वर मंदिर के भीतर सतीचैरा है, जिसका संबंध इसी स्त्री से हो सकता है। यहां भगवान रामचंद्र और कुलेश्वर महादेव के मंदिर के अलावा जगन्नाथ मन्दिर, भक्तमाता राजिम मन्दिर और सोमेश्वर महादेव मन्दिर भी है।

इस स्थान का नाम राजिम तेलिन के नाम पर इसलिए पड़ा क्योंकि यहां के तैलिय वंश लोग तिलहन की खेती करते थे। इन्हीं तैलिन लोगों में एक धर्मदास भी था जिसकी पत्नी का नाम शांतिदेवी था। दोनों विष्णु के भक्त थे और उनकी बेटी का नाम राजिम था। राजिम का विवाह अमरदास नामक व्यक्ति से हुआ। राजिम भी विष्णु की भक्त थी जो मूर्ति विहीन राजीवलोचन मंदिर में जाकर पूजा करती थी। उस समय राजिम तेलिन भगवान राजीव लोचन के ऊपर अपार श्रद्धा-भाव रखकर पूजा-पाठ करती थी। समय के साथ-साथ भगवान राजीव लोचन के ऊपर राजिम तेलिन की श्रद्धा-भक्ति बढ़ती गई। वह मंदिर में रहकर ही भगवान की सेवा करने लगी थी। राजिम की भक्ति, त्याग और तपस्या के चलते ही वह संपूर्ण क्षेत्र में माता की तरह प्रसिद्ध हो गई। भगवान के प्रति अपार सेवाभाव रखने व पुण्य-प्रताप के कारण ही आज पूरे देश में राजिम भक्तिन माता की अलग पहचान है और संपूर्ण क्षेत्र को ही राजिम कहा जाता है।

राजिम का मेला : राजिम का माघ पूर्णिमा का मेला संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ के लाखों श्रद्धालु इस मेले में जुटते हैं। माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक पंद्रह दिनों का मेला लगता है। इसे राजिम कुंभ मेला भी कहते हैं। महानदी, पैरी और सोढुर नदी के तट पर लगने वाले इस मेले में मुख्य आकर्षण का केंद्र संगम पर स्थित कुलेश्वर महादेव का मंदिर है। हालांकि अब इस मेले को राजिम माघी पुन्नी मेला कहा जाता है।

बांग्लादेश-भारत रिश्ता के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा साल 2025

अभिनय आकाश

शेख हसीना की सत्ता खत्म होने के बाद भारत से बांग्लादेश के संबंध बदल गए हैं। हसीना 5 अगस्त 2024 से भारत में हैं। भारत बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रहने की शिकायत करता रहा है। कई बार ऐसी बयानबाजी भी हुई जिसके चलते दोनों देशों के रिश्ते में कड़वाहट नजर आई। इस बीच ये सवाल उठ रहा है कि पिछले पांच महीनों में भारत और बांग्लादेश के आपसी संबंधों में आए तनाव से ज्यादा नुकसान किसे हो रहा है। वहीं बांग्लादेश की तरफ से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की गई है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद तौहिद हुसैन ने कहा कि उन्होंने भारत को सूचित किया है कि न्यायिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए शेख हसीना को वापस भेजा जाए। हालांकि ये माना जा रहा है कि भारत शेख हसीना के प्रत्यर्पण वाले अनुरोध पर किसी भी तरह का एक्शन लेने के मूड में नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रत्यर्पण अनुरोध के जवाब में अपने अगले कदम को स्पष्ट करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में 2025 भारत-बांग्लादेश संबंधों के लिए देखने लायक वर्ष होगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण विकास होंगे जो इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को फिर से परिभाषित कर सकते हैं। मुहम्मद यूनुस के अंतरिम नेतृत्व के साथ बांग्लादेश में राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं और इन परिवर्तनों के निहितार्थ दूरगामी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के निर्वासन के विवादास्पद मुद्दे से लेकर चुनावों में देरी, हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और पाकिस्तान और चीन के साथ बदलते गठबंधन तक, दांव कभी इतना बड़ा नहीं रहा। 2025 में लिए गए निर्णयों और कार्रवाइयों का दोनों देशों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे उनके आर्थिक, रणनीतिक और मानवीय भविष्य को आकार मिलेगा।

सबसे अहम मुद्दों में से एक हसीना के निर्वासन का अनुरोध है। इस अनुरोध पर भारत की प्रतिक्रिया

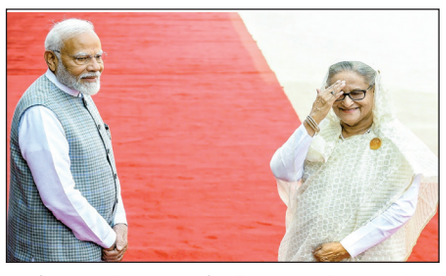

उसके राजनयिक रुख के लिए एक लिटमस टेस्ट होगी और इससे द्विपक्षीय संबंध मजबूत या तनावपूर्ण हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बांग्लादेश में चुनावों में देरी ने एक शक्ति शून्य पैदा कर दिया है जिसे जमात-ए-इस्लामी जैसे कट्टरपंथी समूह भरने के लिए उत्सुक हैं। इन समूहों का उदय, जो ऐतिहासिक रूप से भारत विरोधी रहे हैं, इस क्षेत्र को अस्थिर कर सकते हैं और हाल के वर्षों में हुई प्रगति को कमजोर कर सकते हैं। इसके अलावा, हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में यूनुस सरकार की विफलता ने तनाव बढ़ा दिया है, हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं ने अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। इन मानवाधिकार उल्लंघनों पर भारत की प्रतिक्रिया द्विपक्षीय संबंधों के भविष्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगी। वर्तमान बांग्लादेशी शासन का पाकिस्तान समर्थक और चीन समर्थक रुख भारत के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक चुनौतियाँ पैदा करता है। जैसे-जैसे बांग्लादेश इन देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए एक जटिल भू-राजनीतिक परिदृश्य से निपटना होगा। वर्ष 2025 भारत-बांग्लादेश संबंधों के लिए एक निर्णायक वर्ष होगा, जिसमें महत्वपूर्ण विकास होंगे जो दोनों देशों के भविष्य को आकार देंगे। इस वर्ष लिए गए निर्णयों का स्थायी प्रभाव होगा, और संबंधों में किसी भी गिरावट के बांग्लादेश के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और मानवीय स्थिति प्रभावित होगी जैसा पहले कभी नहीं हुआ।

मुहम्मद यूनुस के अंतरिम नेतृत्व में बांग्लादेश सरकार ने औपचारिक रूप से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत से निर्वासित करने का अनुरोध किया है। अगस्त 2024 में छात्र-नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन के बीच हसीना को निर्वासन झेलना पड़ा और उन्होंने भारत में शरण ली थी। यूनुस प्रशासन ने हसीना और उनके करीबी सहयोगियों पर मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हालाँकि, ठोस सबूतों की कमी और संभावित राजनयिक नतीजों को देखते हुए, भारत के पास इस अनुरोध का पालन करने का कोई अनिवार्य कारण नहीं है। इस अनुरोध पर भारत की प्रतिक्रिया भारत-बांग्लादेश संबंधों के भविष्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगी। अगर बांग्लादेश सरकार मामले को हद से ज़्यादा बढ़ाती है, तो इससे द्विपक्षीय संबंधों में तनाव आ सकता है। हसीना को निर्वासित करने से भारत के इनकार को मौजूदा बांग्लादेशी शासन के लिए समर्थन की कमी के रूप में देखा जा सकता है, जिससे संभावित रूप से राजनयिक तनाव पैदा हो सकता है। दूसरी ओर, अनुरोध का अनुपालन अंतरिम सरकार के कार्यों के समर्थन के रूप में देखा जा सकता है, जिनकी वैधता की कमी और मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए आलोचना की गई है।

यूनुस सरकार ने बांग्लादेश में समय पर चुनाव कराने में बहुत कम दिलचस्पी दिखाई है। अंतरिम प्रशासन ने मतदान की आयु घटाकर 17 वर्ष करने का प्रस्ताव दिया है, एक ऐसा कदम जिसकी चुनावी प्रक्रिया में संभावित देरी के लिए आलोचना की गई है। चुनावों में जितनी अधिक देरी होगी, बांग्लादेश में उतनी ही अधिक अराजकता फैलने की संभावना है, जिससे सत्ता में शून्यता पैदा होगी जिसका फायदा जमात-ए-इस्लामी जैसे कट्टरपंथी समूह उठा सकते हैं। ये समूह, जो ऐतिहासिक रूप से भारत विरोधी रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं, उदारवादी चुनावी आवाज़ों को दरकिनार कर सकते हैं और क्षेत्र को अस्थिर कर सकते हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का उदय भारत-बांग्लादेश संबंधों के लिए हानिकारक होगा। इन समूहों का भारत के हितों का विरोध करने और भारत विरोधी भावना को बढ़ावा देने का इतिहास रहा है। यदि वे नियंत्रण हासिल कर लेते हैं, तो इससे सीमा पार तनाव, सुरक्षा चुनौतियाँ और राजनयिक संबंधों में गिरावट हो सकती है। भारत सरकार को स्थिति पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए और बांग्लादेशी प्रशासन के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं बरकरार रहें और उदारवादी आवाजें हाशिए पर न रहें।

बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफलता के लिए यूनुस सरकार की आलोचना की गई है। देशद्रोह के आरोप में हिंदू भिक्षु चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी से तनाव बढ़ गया है और धार्मिक अल्पसंख्यकों की दुर्दशा उजागर हुई है। हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की कई घटनाएं हुई हैं, जिनमें उनके घरों, मंदिरों और व्यवसायों पर हमले भी शामिल हैं। भारत सरकार धैर्यपूर्वक स्थिति पर नजर रख रही है, लेकिन अगर यूनुस प्रशासन अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करने में लापरवाही बरतता रहा, तो भारत को और अधिक कठोर प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर भारत की प्रतिक्रिया द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण कारक होगी। भारत की कठोर प्रतिक्रिया से कूटनीतिक पतन हो सकता है और रिश्ते में और तनाव आ सकता है। हालाँकि, भारत की चुप्पी को अल्पसंख्यकों की दुर्दशा के प्रति उदासीनता, उसके नैतिक अधिकार को कमजोर करने के रूप में समझा जा सकता है। भारत सरकार को बांग्लादेशी प्रशासन के साथ राजनयिक चैनल बनाए रखते हुए अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की वकालत करते हुए एक नाजुक संतुलन बनाना चाहिए। मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में वर्तमान बांग्लादेश शासन ने पाकिस्तान और चीन के प्रति स्पष्ट झुकाव दिखाया है। विदेश नीति में इस बदलाव का भारत-बांग्लादेश संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। यूनुस प्रशासन का पाकिस्तान और चीन के साथ जुड़ाव इस क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हितों को कमजोर कर सकता है।

आज का इतिहास

1927 पहली ट्रांस-एटलांटिक व्यावसायिक टेलीफोन सेवा न्यूयॉर्क से लंदन के बीच शुरू हुई।
1937 नीदरलैंड की राजकुमारी जुलियाना ने हेग में लिपपे बायस्टरफर्ड के प्रिंस बर्नहार्ड से शादी की।
1940 शीतकालीन युद्ध-फिनिश 9 वें डिवीजन ने रोका और दर-सुओमुस्सालमी सड़क पर भारी सोवियत सेनाओं को नष्ट कर दिया।
1943 वाई-फाई के जनक मशहूर अमेरिकी सर्बियाई आविष्कारक निकोला टेस्ला का निधन हुआ।
1948 एयर नेशनल गार्ड के पायलट थॉमस मेंटल ने केंटकी के फोर्ट नॉक्स के पास यूएफओ का पीछा करते हुए अपनी पी -51 मस्टैंग को बुरी तरह कुचल दिया।
1950 डेवनपोर्ट के आयोवा शहर के मर्सी अस्पताल में आग लगने से 41 मरीजों की मौत हुई।
1953 अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने हाइड्रोजन बम के निर्माण की घोषणा की।
1972 स्पेन के इबीसा क्षेत्र में विमान दुर्घटना में छह चालक दल समेत 108 यात्रियों की मौत हुई।
1979 वियतनाम पीपुल्स आर्मी ने पोल पॉट और खमेर रूज को जमा करते हुए कम्बोडियाई राजधानी शहर फ्नोम पेन्ह पर कब्जा कर लिया, जिसने कम्बोडियन-वियतनामी युद्ध में बड़े पैमाने पर लड़ाई के अंत को चिह्नित किया।
1980 आपातकाल के तीन साल बाद भारी बहुमत के साथ इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हुई।
1985 सेलनेट ने 2 यूके सेल्यूलर नेटवर्क का शुभारंभ किया।
1986 अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने लीबिया के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की।
1989 जापान के वर्तमान सम्राट अकिहितो ने अपने पिता हिरोहितो की मृत्यु के बाद गद्दी संभाली, जिन्हें मरणोपरांत सम्राट शोएमा के नाम से जाना जाने लगा।
1990 पिछले 800 सालों में पहली बार पीसा की झुकती हुई मीनार को दर्शकों के लिए बंद कर दिया गया।
1993 घाना के चौथे गणराज्य का उद्घाटन इसके अध्यक्ष के रूप में जेरी रॉव्लिंग्स के साथ हुआ था।
1994 दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को सिडनी टेस्ट मैच में 5 रन से हराया।
1999 न्यूट गिंगरिच को घर के स्पीकर के रूप में फिर से चुना गया।
2011 अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन फुटबॉल टूर्नामेंट एएफसी एशियाई कप, आधिकारिक तौर पर कतर में खुलता है।

मणिपुर में माफी कोरा दिखावा न होकर सार्थक बदलाव करें

ललित गर्ग

मणिपुर में जातीय संघर्ष, व्यापक हिंसा एवं अराजक माहौल के लिए पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बीते साल के आखिरी दिन शांति की दिशा में एक सराहनीय पहल करते हुए 'माफी' मांगी है, इस माफी को लेकर राजनीति के गलियारों में व्यापक चर्चा है। क्योंकि इस हिंसा में मई 2023 से 250 से अधिक लोगों की जान चली गई और हजारों लोग बेघर हो गए है। लम्बे समय से यह प्रांत अस्थिरता, असंतोष एवं अशांति की आग में जल रहा है। एन बीरेन सिंह ने माफी मांगते हुए हिंसा के इस लंबे कालखण्ड एवं सिलसिले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और सभी समुदायों से अपील की कि पिछली गलतियों को भुलाकर वे शांति और सौहार्द कायम करें। हालांकि मुख्यमंत्री की इस अपील के अपने मतलब निकाले जा रहे है। कुछ लोगों का कहना है कि यह माफी बहुत पहले मांगी जानी चाहिए थी। कुछ का यह मानना है कि माफी ऐसे समय आई है जब मुख्यमंत्री चौतरफा दबाव में है। विरोधी तो बहुत पहले से उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, पिछले कुछ समय से खुद उनके विधायकों और सहयोगियों ने इस माफी को उनकी मजबूरी का परिणाम बताया है। निश्चित ही बीरेन सिंह के लिये माफी मांगना काफी नहीं है, अगर वह मानते हैं कि स्थिति को संभालने में नाकाम रहे तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था या केन्द्र को राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए था। अफसोसनाक यह है कि इस मसले पर अक्सर विवाद उभरते रहे और राजनीतिक शख्सियतों के बीच आरोप-प्रत्यारोप अक्सर बेलगाम बोल में तब्दील ही होते रहे, कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया, जो गैरजिम्मेदाराना राजनीति को दर्शाता है।

मणिपुर में 3 मई 2023 से ही बहुसंख्यक मैतेई और कुकी के बीच आरक्षण और आर्थिक लाभ को लेकर जो हिंसा शुरू हुई वह अभी थमने का नाम नहीं ले रही। कभी अपनी सांस्कृतिक सद्भावना के लिए जाना जाने वाला राज्य अब गहराते विभाजन एवं जातीय संघर्ष का सामना कर रहा है और लोग लगातार भय में जी रहे हैं। तनाव कम होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा। शांति एवं सद्भावना की तलाश अभी भी जारी है। मणिपुर में जब चंद दरिंदें दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनके साथ बर्बरतापूर्ण हरकत करते नजर आए तो पूरा प्रांत आक्रोश में आ गया। जनमानस की प्रतिक्रिया लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत महत्व रखती है। न तो राज्य सरकार ने और न ही केन्द्र सरकार ने हिंसा को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय किए और न ही शांति स्थापित करने के कोई प्रयास किए गए। मुख्यमंत्री एन. बीरेन सरकार डेढ़ साल से ज्यादा समय से खेमों में बंटती राजनीतिक उलझन में फंसी रही। सभी दल, नेता एवं सरकार नामुमकिन निशानों की ओर कौमों को दौड़ती रही। यह कौमों के साथ नाइंसाफी होने के साथ अमानवीयता की चरम पराकाष्ठा थी। क्योंकि ऐसी दौड़ जहां पहुंचाती है, वहां कामयाबी की मंजिल नहीं, बल्कि मायूसी का गहरा गड्ढा होता है।

मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह स्वीकारोक्ति कि ''मैं राज्य में जो कुछ हुआ उसके लिए खेद व्यक्त करना चाहता हूं। कई लोगों ने अपनों को खो दिया और कई लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। मैं खेद व्यक्त करता हूं और माफी मांगता हूं। लेकिन पिछले तीन-चार महीनों में अपेक्षाकृत शांति देखने के बाद, मुझे उम्मीद है कि आने वाले साल में स्थिति सामान्य हो जाएगी।'' प्रश्न है कि मुख्यमंत्री 18 माह के खून-खराबे के बाद अब क्यों माफी मांग रहे हैं? वे क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर वह स्थिति को संभालने में नाकाम रहे थे तो उन्हें बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। ताकि स्थितियों लगातार इतनी विकराल नहीं होती, इतनी अधिक जनहानि नहीं होती। देश के नेताओं को गाल बजाने की बजाय आम आदमी को परेशान करने वाली सामाजिक असुरक्षा, जातीय संघर्ष तथा हिंसा जैसे मुद्दों से निबटने के लिये दूरगामी नीतियों के क्रियान्वयन के प्रयास करने चाहिए। यूं तो मणिपुर हिंसा में इतने मासूमों की मौत के

बाद मुख्यमंत्री के माफी मांगने का कोई औचित्य नजर नहीं आ रहा। इसीलिये विपक्ष दल एवं कांग्रेस उन पर और केन्द्र सरकार पर हमलावर है। 19 महीनों में एन.बीरेन असंवेदनशील बने रहे और वर्ष के अंत में उन्होंने माफी मांगकर किस संवेदनशीलता का परिचय दिया है? अब सवाल यह है कि त्रासदी का अंत कैसे हो? कैसे शांति स्थापित हो? जरूरत है मनुष्य को बांटे नहीं, सत्य को ढंके नहीं।

बड़ा सवाल यह है कि राज्य द्वारा माफ़ी मांगना केवल दिखावा है और राजनीतिक अपयश निवारण और क्षतिपूर्ति की आवश्यकता मात्र है या किसी सार्थक बदलाव की बुनियाद। हालांकि इस तरह की राजनीतिक माफी अक्सर संदेहास्पद ही होती है क्योंकि माफ़ी में इससे कहीं अधिक की क्षमता होती है। सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने वाले नेताओं की संख्या में वृद्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय एवं चिन्तनीय रही है। माफ़ी मांगना एक ऐसी युक्ति है जिसका इस्तेमाल नेता अब अक्सर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिये करते हैं, ताकि वे कम से कम लागत पर अपनी गलतियों को पीछे छोड़ सकें या उनसे पीछा छूडा सके। लेकिन बीरेन सिंह की माफी की अच्छी बात यह है कि तमाम दबावों के बाद ही सही, राजनीति और समाज के हर प्रमुख हिस्से ने उनकी माफी को सकारात्मक कदम माना है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि इस माफी की पहल को विश्वसनीय बनाया जाये एवं ऐसे उपयोगी एवं जरूरी कदम उठाए जाये ताकि मणिपुर राज्य में मैतेई समुदाय और पहाड़ी क्षेत्रों में कुकी जनजातीय समुदायों के बीच चला आ रहा टकराव विराम पा जाये। जरूरी है कि केंद्र और राज्य की सरकार मुख्यमंत्री की इस पहल से उपजे सद्भाव को स्थायित्व देने की कोशिशें अविलंब शुरू कर दें।

2023 के मुकाबले 2024 की दूसरी छमाही में मणिपुर के हालात बेहतर रहे, संघर्ष की स्थितियां कम देखने को मिली। लेकिन पूर्व की हिंसक घटनाओं और मृतकों की संख्या को उससे बनने वाले माहौल से अलग करके नहीं देखा जा सकता। तनाव, संघर्ष और अविश्वास के जिस माहौल से मणिपुर गुजर रहा है, उसकी सचाई इसी हफ्ते कांगपोकपी जिले में कथित कम्युनिटी बंकरों को सुरक्षा बलों द्वारा नष्ट किए जाने पर हुए संघर्ष में 40 लोगों के जख्मी होने और कुकी नैशनल फ्रंट के कथित हमलों के खिलाफ चुराचांदपुर जिले में बंद का आह्वान किए जाने से स्पष्ट है। अभी भी असामान्य हालातों के बीच सवाल है कि मुख्यमंत्री की इस माफी का राज्य के अलग-अलग समुदायों के लोगों पर कैसा और कितना असर पड़ेगा? सवाल महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योकि यह आरोप संघर्ष शुरू होने के बाद से ही लगता रहा है कि मुख्यमंत्री और राज्य प्रशासन की भूमिका निरपेक्ष नहीं है। आरोप पूरी तरह गलत हो तो भी इससे इतना तो स्पष्ट है कि प्रदेश के लोगों का एक खेमा उन्हें अविश्वास भरी नजरों से देखता है। इतने गंभीर और मानवता के अस्तित्व को ही नकारने से जुड़े मसले पर भी समाज के लोगों में जो बंटवारे की प्रवृत्ति राजनीतिक कारणों से दिख रही है वो किसी भी नजरिए से देश की एकता और अखण्डता के लिये फायदेमंद नहीं है।

मुद्दा चाहे कोई भी, खांचों या खेमों में बांटने या बंटने का और आम लोगों को तोड़ने का या जोड़ने का- राजनीति से जुड़े लोगों, राजनीतिक दलों और नेताओं में तो शुरू से रहा है लेकिन जब समाज में आम लोग भी इस तरह के बंटवारे का हिस्सा बन जाते हैं तो इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ देश के नागरिकों का होता है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सरकार संकट में सही ढंग से नहीं निपटने के चलते अपनी विश्वसनीयता पहले ही खो चुकी है, लेकिन उसे पुनः हासिल करने के लिये माफी से आगे बढ़कर और अधिक सामाजिक एकता, समरसता एवं सौहार्द के प्रयत्न करने होंगे। हमारे देश की राजनीति की विडम्बना ही रही है कि लोगों को धर्म, जाति, वर्ग, भाषा, वर्ण के नाम पर बांट कर किसी न किसी तरह सत्ता हासिल करना। हालांकि सही मायने में लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति की परिभाषा और दायरा उससे कहीं ज्यादा व्यापक है। जातीय हिंसा का समाधान संवाद से ही होता है। राज्य सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मैतेई और कुकी समुदाय के साथ लगातार संवाद जारी रखना चाहिए।

दोस्ती में दगा करने की चीन की नहीं जा रही आदत?

प्रमोद भार्गव

अक्तूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई मधुर बातचीत और विवादित स्थलों को लेकर समझौते की कड़ियां आगे बढ़ने से ऐसा लगने लगा था कि भारत और चीन के रिश्ते पटरी पर आ रहे हैं। लेकिन दोस्ती में दगा करने के आदी चीन ने फिर वही कटुता पैदा करने वाली हरकतें शुरू कर दीं। चीन ने होतान प्रांत में दो नये जिले बनाने की घोषणा की है। इन जिलों की सीमा का विस्तार भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आता है। इसके पहले चीन ने तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी पर 137 अरब डॉलर की लागत से दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की घोषणा भी की है। ये विवादित घोषणाएं ऐसे समय में की गई हैं, जब दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों ने लगभग पांच साल बाद फिर से सीमाओं के संदर्भ में बातचीत शुरू की है। इसी बातचीत के चलते दोनों देश पूर्वी लद्दाख के डेमचोक और देपसांग क्षेत्रों से पीछे हटने पर सहमत हुए थे। गलवान में 2020 में घटी सैन्य घटना से पहले की स्थिति बहाल रखने पर भी सहमति बन गई थी। सनद रहे कि चीन ने अक्साई चिन के करीब 40000 वर्ग किमी क्षेत्र पर पहले से ही कब्जा किया हुआ है। लद्दाख में 14000 फुट की ऊंचाई पर स्थित दुर्गम गलवान नदी घाटी में चीनी सैनिकों की दगाबाजी के चलते 20 भारतीय वीर सपूतों को शहीद होना पड़ा था। चीन के भी 40 से अधिक सैनिक मारे गए थे। 20 अक्तूबर 1975 के बाद 2020 में पहली बार इतना बड़ा हिंसक सैन्य संघर्ष भारत-चीन सीमा विवाद के परिप्रेक्ष्य में घटा था। 1975 में अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला क्षेत्र में असम राइफल्स की पेट्रोलिंग पार्टी पर चीनी सैनिकों ने घात लगाकर हमला किया था। इसमें हमारे चार सैनिक शहीद हुए थे। अब बातचीत के बाद सेनाओं के पीछे हटने से लग रहा था कि स्थाई शांति बहाल हो जाएगी। परंतु लद्दाख के इसी क्षेत्र में दो नये जिलों की घोषणा से स्पष्ट हुआ है कि चीन की विस्तारवादी मंशा यथावत है। हालांकि भारत और चीन के बीच 1993 में प्रधानमंत्री पी.वी। नरसिंह राव ने चीन यात्रा के दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की दृष्टि से एक समझौता किया था। समझौते की शर्तों के मुताबिक निश्चित हुआ था कि एक तो दूसरे पक्ष के खिलाफ बल या सेना के प्रयोग की धमकी नहीं दी जाएगी। दूसरे, दोनों देशों की सेनाओं की गतिविधियां नियंत्रण रेखा पार नहीं करेंगी। यदि भूलवश एक पक्ष के जवान नियंत्रण रेखा पार कर लेते हैं तो दूसरी तरफ से संकेत मिलते ही नियंत्रण रेखा के उस पार चले जाएंगे। तीसरे, दोनों पक्ष विश्वास बहाली के उपायों के जरिये नियंत्रण रेखा के इलाकों में काम करेंगे। सहमति से पहचाने गए क्षेत्रों में कोई भी पक्ष सैन्य अभ्यास के स्तर पर कार्य नहीं करेगा। इसके बावजूद गलवान में सैन्य संघर्ष हो गया था।

श्रीलंका में भारतीय शहीदों की याद में, शांति और सम्मान की एक नजीर

कर्नल संजय पांडे

वर्ष 1987 के भारत-श्रीलंका समझौते के तहत भारतीय शांति सेना (आईपीकेएफ) की श्रीलंका में तैनाती भारत का पहला स्वतंत्र विदेशी राजनीतिक-सैन्य उद्यम था। यह भारत के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभुत्व का परिचायक तो था ही, क्षेत्रीय अलगाववाद को दो देशों की आपसी सहमति से खत्म करने, दो पड़ोसी देशों का क्षेत्रीय और वैश्विक शांति बनाए रखने के दायित्वों का अद्वितीय अनुसरण एवं दक्षिण एशिया में बिना किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था को शामिल किए शांति व्यवस्था बहाल करने की अद्भुत मिसाल रहा है।

इस पथप्रदर्शक राजनीतिक-सैन्य पहल को चाहे क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उतनी ख्याति नहीं मिली, पर यह भारतीय सेना के पराक्रम, अदम्य साहस, अदभुत रण कौशल, उत्कृष्ट बलिदान और उच्च सैन्य नेतृत्व की खूबियों के लिए भारतीय सैन्य इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। आईपीकेएफ ऑपरेशन जहां एक ओर सैन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का हिस्सा बन गया, वहीं भारतीय सैनिकों का बलिदान बटालियनों, रेजिमेंटों और सेना के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

भारतीय सेना की एक प्रतिष्ठित एवं जांबाज बटालियन 11, गढ़वाल राइफल्स को भी भारतीय शांति सेना का हिस्सा बनकर 1987 में श्रीलंका के उत्तर-पूर्व में सबसे दुर्गम व उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र मुल्लईतिवु में काम करने का मौका मिला। बटालियन त्रिंकोमाली में उतरकर मुल्लईतिवु तक पैदल मार्च करके तीन-चार दिनों में पहुंची थी। इस लंबे मार्च के दौरान ही लिट्टे ने बटालियन के साथ सुरक्षा के लिए चल रहे दो बीएमपी को बारूदी सुरंग से उड़ा दिया था। 11, गढ़वाल राइफल्स इस इलाके में पहुंचने वाली सबसे पहली बटालियन थी। बटालियन ने अपने अदम्य साहस व रण कौशल का परिचय देते हुए लिट्टे के शिविरों को खोज-खोजकर नष्ट किया, जो जाफना पर कब्जा होने के बाद घने जंगल के बीच बना नया जाफना के रूप में

जाना जाता था। अपने 15 महीने के कार्यकाल में बटालियन ने तत्परता से काम करते हुए लिट्टे की कमर तोड़ दी थी। हालांकि बटालियन को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा और लिट्टे जैसे प्रशिक्षित कैडर के साथ लड़ने में काफी कुछ सीखने को भी मिला।

बटालियन अपना हाई एल्टीट्यूड का कार्यकाल पूरा करके नए मिलिट्री स्टेशन पहुंची ही थी कि उसे चेन्नई में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा ड्यूटी के लिए जाने का हुक्म मिला। शुरुआती नुकसान के बावजूद बटालियन ने अपने पराक्रम का अभूतपूर्व परिचय देते हुए अपरिचित भू-भाग, अपरिचित वातावरण व भाषा के बावजूद, जंगलों में लिट्टे के महिला शिविर को बर्बाद किया। आईपीकेएफ की वापसी के बाद लिट्टे अपने को इन्हीं कैंपों को पुनर्जीवित कर श्रीलंकाई सेना से लड़ रही थी। उन क्षेत्रों में लिट्टे के 14 कैंपों की पहचान की गई है और वहां पर बारूदी सुरंग हटाने का कार्य अब भी चल रहा है।

आईपीकेएफ के ऑपरेशन के दौरान 11, गढ़वाल राइफल्स बटालियन के काफी जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन दिनों मृत सैनिकों को वापस मुख्य भूमि में भेजने का प्रावधान नहीं था। बटालियन के सभी मृतकों की अंत्येष्टि श्रीलंका में ही की गई थी। उन शहीदों और बटालियन के अविस्मरणीय समर्पण एवं कौशल की यादों को समेटे बटालियन के पांच अधिकारी अपनी धर्म पत्नियों के साथ, अपने छूटे हुए साथियों को श्रद्धांजलि देने के लिए नवंबर, 2024 में श्रीलंका गए थे।

छत्तीस साल बाद 11, गढ़वाल राइफल्स के वे अधिकारी, जिन्होंने आईपीकेएफ असाइनमेंट के दौरान अपने साथियों को खोया था, इस यात्रा में अपने दिवंगत साथियों के अंत्येष्टि स्थल पर पुष्प अर्पण कर प्रार्थना सभा भी की। ये अधिकारी श्रीलंकाई सेना की मदद से वानी जंगल के उन स्थानों पर भी गए, जहां उन्होंने लिट्टे के शिविरों पर हमला किया था। इस यात्रा के दौरान बटालियन के अधिकारियों ने पलटन के युवा अधिकारी 2/लेफ्टिनेंट मोहन जैकब की कब्र को भी श्रीलंकाई सेना की मदद से ढूंढ़ निकाला और वहां भी प्रार्थना की। इसी तरह अन्य गढ़वाली वीरों द्वारा दी गई आहुति के कई स्थलों पर शोक सभा कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।

यात्रा के अंतिम पड़ाव (कोलंबो) पर मैंने भी आईपीकेएफ स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। भारतीय सेना के सभी शहीद जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर बटालियन के अधिकारियों ने अपने खोए हुए सैनिकों का न सिर्फ सम्मान बढ़ाया है, बल्कि उनके बलिदान और वीरता की गाथाओं को पुनर्जीवित कर दिया है।

श्रीलंका में आईपीकेएफ द्वारा की गई कार्रवाई हमेशा शांति और पड़ोसियों के लिए पारस्परिक सम्मान के हमारे आंतरिक दर्शन का मानक बनी रहेगी। भारतीय सैन्य इतिहास का आईपीकेएफ पर एक अलग खंड प्रकाशित किया जाना चाहिए, जिसमें उनके कार्यों पर प्रकाश डाला जाए। उन शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक उपयुक्त तारीख भी निर्धारित की जानी चाहिए।

ट्रम्प के समर्थकों के बीच विवादास्पद हो गए आव्रजन और एच-1बी वीजा

कल्याणी शंकर

अमरीका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एक असामान्य स्थिति में हैं। वे अपने अभियान को निधि देने वाले अरबपति तकनीकी लोगों और अपने कट्टर समर्थकों दोनों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। आव्रजन और एच-1 बी वीजा ट्रम्प के मुख्य समर्थकों और उदारवादियों के बीच विवादास्पद हो गए हैं। ट्रम्प ने मस्क और सिलिकॉन वैली के धनी संरक्षकों का समर्थन किया है, जो मेहनती एच-1बी वीजा धारकों (मस्क के पास खुद एच-1बी वीजा था) के साथ अपने साम्राज्य का निर्माण करते हैं। जबकि तकनीकी नेता एक उदार एच-1बी वीजा व्यवस्था चाहते हैं।

'अमरीका फर्स्ट' कट्टरपंथी सभी स्तरों पर आव्रजन पर सख्त प्रतिबंध चाहते हैं। अपने पहले कार्यकाल में, ट्रम्प ने अमरीकी नागरिकों के हितों को प्राथमिकता दी, जिसका एच-1बी वीजा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। पदभार ग्रहण करने से कुछ दिन पहले, एच-1बी वीजा पर बहस छिड़ गई। ट्रम्प, जिन्होंने अपने पहले कार्यकाल में वीजा कार्यक्रम का विरोध किया था, अब इसका समर्थन करते हैं।

ट्रम्प की टीम के भीतर मतभेद हैं। सवाल यह है कि क्या ट्रम्प का दूसरा कार्यकाल अमरीकी कामगारों को प्राथमिकता देगा या फिर यह पारंपरिक रिपब्लिकन रुख पर लौटेगा कि आव्रजन मुख्य रूप से नियोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है? 'अमरीका फर्स्ट' के समर्थकों का तर्क है कि एच-1बी वीजा अमरीकी कामगारों से नौकरियां छीन लेता

है। ट्रम्प, एलन मस्क और विवेक रामास्वामी जैसे प्रभावशाली समर्थकों का दावा है कि वे अमरीका में इंजीनियरों की कमी को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। दक्षिण अफ्रीका के एक पूर्व नागरिक मस्क ने इस कार्यक्रम का जोरदार समर्थन किया है और इसके लिए 'युद्ध करने' की अपनी तत्परता व्यक्त की है।

मस्क और रामास्वामी अमरीकी श्रम बाजार में, विशेष रूप से एस.डी.ई.एम. क्षेत्रों में, एक महत्वपूर्ण कौशल अंतर की ओर इशारा करते हैं। उनका तर्क है कि सॉफ्टवेयर विकास, इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे कुछ विशेष क्षेत्रों में अत्यधिक कुशल श्रमिकों की वास्तविक कमी है।

न्यूयॉर्क पोस्ट ने ट्रम्प के हवाले से कहा, ''मुझे हमेशा से वीजा पसंद रहे हैं, मैं हमेशा से वीजा के पक्ष में रहा हूं। इसलिए हमारे पास ये हैं।'' उन्होंने आगे कहा,''मेरी संपत्तियों पर कई एच-1बी वीजा हैं। मैं एच-1बी वीजा में विश्वास करता रहा हूं। मैंने कई बार इसका इस्तेमाल किया है। यह एक बेहतरीन कार्यक्रम है।'' एच-1बी वीजा क्या है, और इस पर इतना विवाद क्यों है? अगर एच-1बी वीजा नहीं होगा तो क्या भारत को नुकसान होगा? राष्ट्रपति बुश ने 1990 में दूसरे देशों के कुशल श्रमिकों के लिए कानूनी रूप से काम करने के लिए वीजा प्रणाली शुरू की थी। आमतौर पर, यह 3 साल के लिए होता था, लेकिन इसे बढ़ाया जा सकता था। लोग एच-1बी वीजा के लिए तभी आवेदन कर सकते हैं, जब उनके पास अमरीका स्थित प्रायोजक कंपनी या संस्थान में नौकरी हो।

2004 से, नए एच-1बी वीजा की वार्षिक सीमा 85,000 है, जिसमें अमरीकी विश्वविद्यालयों से उन्नत डिग्री वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए 20,000 शामिल हैं। 2023 वित्तीय वर्ष (अक्तूबर 2022-सितंबर 2023) में 386,000 से ज्यादा एच-1बी आवेदन स्वीकृत किए गए। 2024 में पात्र पंजीकरणों की संख्या 758,994 थी, जबकि 2023 में यह 474,421 थी। अधिकांश स्वीकृत आवेदक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में काम करते हैं। यह मुद्दा सिर्फ आर्थिक चिंता से कहीं ज्यादा है। आर्टिफिशियल इंटैलीजैंस और नवीनतम कम्प्यूटिंग तकनीक में नए विकास इसे अमरीकी रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं। विवाद पिछले सप्ताह तब शुरू हुआ जब दूर-दराज के कार्यकर्त्ताओं ने ट्रम्प द्वारा भारतीय-अमरीकी उद्यमी पूंजीपति श्रीराम कृष्णन को कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर सलाहकार के रूप में चुने जाने की आलोचना की। विरोधियों को डर था कि कृष्णन ट्रम्प प्रशासन के भीतर आव्रजन नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। विरोधियों को डर था कि कंपनियों द्वारा अमरीकी नौकरी बाजार को कमजोर करने के लिए एच-1बी वीजा कार्यक्रम का कथित रूप से दुरुपयोग किया गया था।

वीजा कैप ने एच-1बी वीजा चाहने वालों को भी प्रभावित किया है। भारतीयों को लगभग 72 प्रतिशत एच-1बी वीजा मिलते हैं, उसके बाद चीनी नागरिकों को 12 प्रतिशत मिलते हैं। देश-विशिष्ट कैप को हटाने से अमरीका में भारतीयों के लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं, जो कई उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। एमाजॉन और गूगल जैसी तकनीकी दिग्गज कंपनियों सहित प्रमुख अमरीकी कंपनियां एच-1बी वीजा के अपने प्रयोजन को काफी हद तक कम कर रही हैं। शोध से पता चलता है कि ये एच-1 बी वीजा धारक अक्सर अमरीकी श्रमिकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय उनके पूरक होते हैं, जिससे नए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और आर्थिक गतिविधि का विस्तार होता है।

अमरीकन एंटरप्राइज इंस्टीच्यूट और पार्टनरशिप फॉर ए न्यू अमरीकन इकोनॉमी के अनुसार एच-1 बी वीजा कैप बढ़ाने से 1.3 मिलियन नए रोजगार सृजित हो सकते हैं और 2045 तक अमरीकी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 158 बिलियन डॉलर जुड़ सकते हैं। एच-1 बी वीजा पर ट्रम्प के हालिया बयानों ने कई वीजा चाहने वालों, विशेष रूप से भारतीयों के बीच आशा जगाई है।

'आप' से हिसाब चुकाना चाहती है कांग्रेस?

राजकुमार सिंह

कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन दिल्ली की राजनीति इसे बदलती दिख रही है। छह महीने पहले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर दिल्ली में भाजपा के विरुद्ध ताल ठोंकी थी, पर भाजपा फिर भी सातों सीटें जीत गई। तब भी आप से गठबंधन का विरोध हुआ था। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली तो पार्टी छोड़ भाजपा में ही चले गए। तब कांग्रेस और आप को भाजपा दुश्मन नंबर एक नजर आती थी। इसलिए जिस कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए आप 2013 में सत्ता में आई थी, उसी के साथ 2023 में दो दर्जन दलों के विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' में शामिल हो दोस्त बन गई। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद वह दोस्ती फिर दुश्मनी में बदल रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए दोनों आमने-सामने हैं। आप के प्रमुख उम्मीदवारों की घेराबंदी की जा रही है। केजरीवाल के विरुद्ध नई दिल्ली सीट से संदीप दीक्षित को उम्मीदवार बनाया गया है, जो 15 साल तक दिल्ली की कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहीं शीला दीक्षित के बेटे हैं। केजरीवाल सरकार में उपमुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया के विरुद्ध कांग्रेस ने पूर्व मेयर फरहाद सूरी को उम्मीदवार बनाया है। मुख्यमंत्री आतिशी के विरुद्ध अलका लांबा को चुनाव मैदान में उतारा है, जो खुद भी आप में रह आई हैं। चुनावी घेराबंदी से भी आगे बढ़ कर कांग्रेस ने आप के विरुद्ध खुली राजनीतिक जंग का ऐलान कर दिया है। शराब घोटाले के बाद अब जिस महिला सम्मान योजना के संकट में आप फंसती दिख रही है, उसकी शिकायत भी दिल्ली के उपराज्यपाल से कांग्रेस ने ही की। संदीप दीक्षित ने इसकी लिखित शिकायत करते हुए पंजाब पुलिस द्वारा कांग्रेस उम्मीदवारों की जासूसी और चुनाव के लिए पंजाब से दिल्ली कैश लाए जाने के आरोप भी लगाए। आश्चर्य नहीं कि तत्काल जांच के आदेश भी दे दिए गए। बदलते रिश्तों के पीछे बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने उसको लगातार कमजोर करनेवाली आप से अंततः हिसाब चुकता करने का फैसला कर लिया है। विधानसभा चुनाव परिणाम बताते हैं कि जैसे-जैसे आप चढ़ती गई, कांग्रेस रसातल में जाती रही। 1993 में जब भाजपा ने दिल्ली में सरकार बनाई थी, तब भी कांग्रेस ने 34.48 प्रतिशत वोटों के साथ 14 सीटें जीती थीं। 1998 में कांग्रेस ने 47.76 प्रतिशत वोटों के साथ 52 सीटें जीतीं और शीला दीक्षित के नेतृत्व में सरकार बनाई। 2003 में वोट प्रतिशत तो बढ़कर 48.13 हो गया, पर सीटें घट कर 47 रह गईं। 2008 में कांग्रेस ने 40.31 प्रतिशत वोटों के साथ 43 सीटें जीत कर लगातार तीसरी बार सरकार बनाई, लेकिन आप के अस्तित्व में आने के बाद हुए पहले चुनाव में 2013 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत घट कर 24.55 रह गया और सीटें आठ। 2015 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत घट कर 9.56 रह गया और खाता तक नहीं खुल पाया। फिर 2020 में तो वोट प्रतिशत 4.26 पर आ गया। जाहिर है, खाता फिर नहीं खुला।

आगे बढ़ने के लिए 'सकारात्मक सोच' जरूरी

महात्मा गांधी का प्रसिद्ध कथन है कि नकारात्मकता से दूर रहते हुए पूरे मन से इंसान वैसा ही बनता जाता है, जैसी वह प्रयास करेंगे तो सफलता मिलनी तय है। सोच रखता है। यह कथन छोटे या बड़े हर व्यक्ति पर लागू होता है। आप जिंदगी में सफल तभी हो सकते हैं, जब आप सफलता हासिल करने के प्रति अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे। अगर अपनी खामियां ढूंढ-ढूंढकर खुद को कमतर ही आंकते रहेंगे तो कभी सफलता की ओर कदम नहीं बढ़ा सकोगे। दीजिए काबिलियत का सौ प्रतिशत अगर आप थोड़ी-सी परेशानियों से घिरने पर खुद की क्षमताओं पर ही संदेह करने लगेंगे तो सफल होना मुश्किल है। हो सकता है कि एक बार प्रयास करने पर सफलता न मिले लेकिन अगर आप

प्रभावित होता है मानसिक स्वास्थ्य नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति अपने आसपास एक ऐसा नकारात्मक माहौल बना लेते हैं जो उनके साथ- साथ उनके आसपास के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है इसलिए इससे जितना हो सके बचें।

लक्ष्य बनाकर चलें जिंदगी का लक्ष्य बनाकर चलें तो दिमाग को भटकने से बचाया जा सकता है। किसी भी अप्रिय स्थिति का सारा दोष खुद पर ही न मढ़ लें। इसके लिए परिस्थितियां भी दोषी हो सकती हैं। आपकी काबिलियत इसमें है कि आप इन परिस्थितियों को खुद पर हावी न होने दें।

'होटल इंडस्ट्री' सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र

वर्ष 2020 में शुरू हुई कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित होने के पश्चात हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है। इसमें तेजी आई है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर करियर के मौके पैदा होंगे।

आने वाले दिनों में इस इंडस्ट्री को सबसे अधिक रोजगार देने वाले क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है। अनुमान है कि वर्ष 2027 तक भारत में तीन करोड़ से भी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक पहुंचेंगे, जिसके चलते होटल और रैस्टोरैंट के क्षेत्र में करियर की संभावनाएं बढ़ेंगी।

कोरोना के बाद छात्रों को कांटैक्ट लैस हॉस्पिटैलिटी सर्विस देने का अभ्यास कराया जा रहा है। इसमें इम्युनिटी बढ़ाने वाले व्यंजनों की जानकारी, कॉंटैक्ट लैस चैक-इन से लेकर चैक-आऊट की जानकारी, हाऊसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस व कमरों का सैनिटाइजेशन भी सिखाया जा रहा है। जायकेदार खाना बनाने की कला के जरिए आप एक छोटे लोकल पब से लेकर फाइव स्टार या फिर इंटरनैशनल होटल में अपनी जगह बना सकते हैं। बस बनाना है ऐसा खाना कि सामने वाला सिर्फ खाना ही नहीं, बल्कि अपनी उंगलियां भी चाटता रह जाए।

अगर आपका इंट्रेस्ट कुकिंग, बेकिंग और लजीज खाना बनाने में है, अगर आप डिफरैंट डिशेज के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते

हैं तो एक नया करियर ऑप्शन आपके इंतजार में है। होटल मैनेजमेंट में इन दिनों करियर बनाने के कई ऑपशन मौजूद हैं।

कोर्स एवं अवसर

बी.एस.सी. इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन कुकरी, क्राफ्टसमैनशिप कोर्स इन फूड एंड बेवरेज सर्विस मैनेजमेंट, सर्टीफिकेट कोर्स इन कुकरी सर्टीफिकेट कोर्स इन कुकरी फॉर होम मेकिंग, डिप्लोमा इन बेकरी एंड कंफैक्शनरी जैसे ढेरों कोर्स कर करियर बनाया जा सकता है।

सबसे अहम है कि आप फूड एंव

बेवरेज डिवीजन सर्विस के अलावा बतौर शैफ बनकर अपने करियर को रौशन कर सकते हैं। मुख्य तौर पर होटल, रेस्तरां, क्रूज, टूरिज्म एसोसिएशन एयरलाइन कैटरिंग और केबिन सर्विस, क्लब मैनेजमेंट, लॉज, गैस्ट हाऊस भी होटल मैनेजमैंट पासआऊट प्रोफैशनल्स ही चलाते हैं।

बेकर्स के लिए भी जॉब ऑपशंस की कमी नहीं है। बेकरी, हॉट ब्रेड शॉप, डिपार्टमैंटल स्टोर्स, होटल और कैफे में भी बेकर्स की काफी डिमांड है।

पूरी दुनिया में टूरिज्म और एविएशन ने होटल बिजनैस के लिए अवसरों को बहुत बड़ा बना दिया है। आने वाले समय में होटल इंडस्ट्री में जॉब की कमी नहीं होगी। इसके अलावा आप धीरे-धीरे खुद का होटल, बेकरी शॉप, रेस्तरां या फिर कैटरिंग बिजनैस भी शुरू कर सकते हैं।

योग्यता

इस फील्ड में सर्टीफिकेट कोर्स, डिप्लोमा व डिग्री कर सकते हैं। इन पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं या स्नातक होना जरूरी है। 12वीं में अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ी होनी चाहिए।

इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए कुछ व्यक्तिगत गुणों का होना भी जरूरी है, जैसे मृदुभाषी होना। द्विभाशी (अंग्रेजी, हिन्दी) ज्ञान हो तो और भी बेहतर। बेहतर पर्सनैलिटी, सुनने-समझने की अच्छी आदत, समस्याओं को सुलझाने की योग्यता, लीडरशिप और मैनेजीरियल स्किल भी बेहद जरूरी हैं।

प्रमुख संस्थान

नैशनल काऊंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टैक्नोलॉजी, नोएडा www.nchm.nic.in इग्नू, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली www.ignou.ac.in लक्ष्य भारती इंटरनैशनल होटल मैनेजमेंट संस्थान, नई दिल्ली www.lbiim.com कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र, हरियाणा।।

'वाणी में मिठास' यानी बातचीत की कला

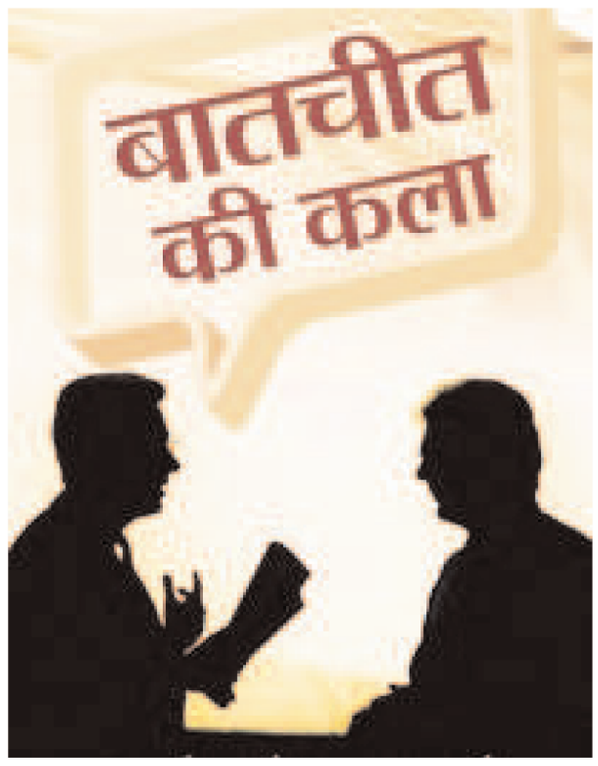

मनुष्य के व्यक्तित्व की पहचान उसके बातचीत करने के ढंग से होती है। भले ही कोई व्यक्ति कितना ही सुंदर हो, परंतु वाणी में कर्कशता या रूखापन हो तो वह कभी किसी को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता।इसके विपरीत सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति यदि सौम्य हैं और उसकी वाणी में मिठास है तो वह सहज ही सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। उचित - अनुचित का ज्ञान रखकर बोलने से आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बन सकता है इसलिए आवश्यक है तोल-मोल कर बोलना ।* अपनी आवाज पर ध्यान दें, बहुत ऊंचे स्वर में चिल्ला-चिल्लाकर न बोलें।

* बोलते समय विषय का पर्याप्त ज्ञान हो इसका ध्यान रखें ।* बोलते समय अवसर व स्थान का विशेष ध्यान रखें। अस्पताल में धीरे बोलें।

* दो लोगों के बीच कभी न बोलें। न ही बिन मांगे अपनी सलाह दें।* दूसरों की बात ध्यान से सुनें, तभी बोलें। साथ ही उनकी रुचि का ध्यान रखकर बोलें।* बोलते समय बेवजह न हाथ नचाएं, न आंखें मटकाएं, न दूसरों को छुएं।* कुछ खाते हुए कभी न बोलें। बोलते समय थूक के छींटें दूसरों पर न उड़ाएं।* किसी दूर खड़े व्यक्ति से दूर से ही चिल्लाकर बात करने की कोशिश न करें, पास जाकर बोलें। * बच्चों के स्कूल में उनकी अध्यापिकाओं आदि से शिष्टाचार से बोलें।* अपने उच्चाधिकारी होने का मान करते हुए अपने मातहतों को बिना सोचे-समझे कभी न बोलें। तुच्छ न समझें।

'वकालत' में बढिया करियर

यदि आप किसी भी प्रकार के अन्याय को देख विचलित होते हैं, यदि आपको चिंता है कि पड़ोस में जो व्यक्ति मोल-भाव कर रहा है, उसे उचित भाव नहीं मिल रहा एवं यदि आप एक नागरिक की हैसियत से अपने मूलभूत अधिकारों के प्रति सजग हैं तो आपको वह चाहिए, जो एक विधि व्यवसायी चाहता है।

यदि आप करियर के रूप में विधि को चुनते हैं तो आप एक वकील, सोलिसिटर, अधिवक्ता, विधि विशेषज्ञ एवं अंततोगत्वा एक न्यायाधीश बन सकते हैं। एक वकील होने के नाते आपका कार्य सिर्फ बहस करना या तर्क-वितर्क करना ही नहीं, आपको निरन्तर अध्ययन करना तथा खुद को दुनिया की नवीनतम घटनाओं से अद्यतन रखना होता है। एक सोलिसिटर के रूप में आपको क्लाइंट के साथ को ऑर्डिनेट करना व कागजी कार्रवाई करनी होती है, जबकि एक अधिवक्ता के रूप में आपको मामला माननीय न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होता है।

एक विधि विशेषज्ञ के रूप में आप कार्पोरेट फर्म के लिए कार्य करेंगे तथा फर्म के रूप में कार्रवाई करेंगे। इन गतिविधियों के अतिरिक्त, आप कार्पोरेट या वैयक्तिक, तकनीकी कानून पर सलाह, कार्पोरेट विलयन एवं अभिग्रहण, कानून का अनुपालन इत्यादि के लिए पक्षकारों के बीच उत्तम कार्य भी करेंगे। आप वास्तविक संपदा, बीमा, कराधान, संविदा इत्यादि के कार्यों को देखेंगे।

आपके पास देश ही नहीं, विदेशों में भी मौकों की कमी नहीं। उदाहरण के लिए, करिश्मा वोरा एक भारतीय वकील हैं, जिन्होंने इंगलैंड में काफी नाम कमाया है।

आवश्यक गुण

सफल अधिवक्ता में अच्छी वार्तालाप कला, अच्छे तर्क, विशलेषणात्मक सोच, एकाग्रता, धैर्य, अभिरक्षण, आत्मविश्वास, अच्छी संप्रेषण दक्षता, अच्छी आवाज, कूटनीति एवं विवेकशीलता, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विषयों के बारे में जागरूकता एवं पढ़ने की आदत होनी चाहिए।

किस तरह बन सकते हैं वकील

पहला मार्ग

किसी भी विषय में 10+2 करने के बाद आप बी.ए.एल. बी. एस.सी. कर ऑफ मास्टर एल.एल.एम. कर सकते हैं। यह विकल्प 5 वर्ष की अवधि का हो सकता है।

दूसरा मार्ग

किसी भी विषय में 10+2 करने के बाद आप किसी भी विषय में स्नातक करने के उपरांत 3 वर्ष की अवधि का एल.एल.बी. कोर्स कर सकते हैं।

रोजगार के अवसर

आप किसी सोलिसिटर फर्म में कार्पोरेट विधि/ दंड प्रक्रिया / आयकर कानून/ वास्तविक संपदा कानून एवं विधि के अन्य विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए कार्य कर सकते हैं।

आपको सबसे पहले किसी वरिष्ठ वकील के अधीन कनिष्ठ वकील के रूप में प्रैक्टिस करनी होगी, बाद में एक कार्पोरेट या आपराधिक प्रक्रिया में स्वतंत्र वकील के रूप में कम्पनी के विधि एवं सचिवीय विभाग, सरकारी न्यायिक सेवा, जैसे-केंद्रीय सरकार विधि सेवा एवं राज्य सरकार विधि सेवा, आसूचना सेवाएं, जैसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो आदि में कार्य कर सकते हैं। सोलिसिटर के रूप में कार्य करने के लिए आप सोलिसिटर की परीक्षा दे सकते हैं। कानून की डिग्री पूरी होने एवं बार काऊंसिल से प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद आप एडवोकेट के रूप में कार्य कर सकते हैं। आप रक्षा सेवाओं, जैसे आर्मी लॉ काडर्स, प्रबंधन परामर्श फर्म्स, कार्पोरेट लेखा परीक्षण फर्म, नोटरी के रूप में कार्य कर सकते हैं। नोटरी अर्थात पब्लिक ऑफिसर, जो कि राज्य सरकार द्वारा प्रलेखन, प्रमाणन एवं विभिन्न प्रकार के विलेख तथा प्रपत्रों के सत्यापन के लिए लोक अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाते हैं।

आप पत्रकारिता में भी जा सकते हैं, जहां आप विधि संबंधित विषयों पर समाचार पत्रों में तथा विधि पत्रिकाओं में एवं विधि पुस्तकों और आवधिक पत्रिकाओं में प्रकाशन हेतु लिख सकते हैं।

आप संपादकीय सहायक के रूप में प्रकाशकों के साथ कार्य कर सकते हैं, जिससे जरूरी अनुभव प्राप्त हो सकेगा। अध्यापन संस्थानों को भी वकीलों की आवश्यकता होती है, आप संकाय सदस्य के रूप में या अनुसंधान सहायक के रूप में काम कर सकते हैं।

टॉप करना है तो अपना लें ये टिप्स बहुत नजदीक है बोर्ड परीक्षा

सीबीएसई, आईसीएसई, आईएससी, यूपी, बिहार समेत अधिकांश बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन फरवरी से अप्रैल 2025 के बीच किया जाएगा। इस साल 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्र इन दिनों बोर्ड परीक्षाओं की अंतिम तैयारी में लगे हुए हैं। बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने और टॉप करने के लिए अभी से पूरी तैयारी शुरू कर दें।

छात्रों को सबसे पहले एक सुव्यवस्थित टाइम-टेबल (बनाना जरूरी है। आइए जानते है किन बातों का ध्यान रखकर एग्जाम में टॉप कर सकते है। यहां जानें बोर्ड परीक्षा में टॉप करने के उपाय। इन सुझावों की मदद से आप परीक्षा में बेहतर स्कोर प्राप्त कर सकते हैं।

टाइम-टेबल बनाएं और पालन करें

आपका टाइम-टेबल सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि आपका मार्गदर्शक होना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि आप पूरे दिन में पर्याप्त समय सभी विषयों को दे पा रहे हैं। विषयों के बीच बैलेंस बनाए रखें और मुश्किल विषयों के लिए ज्यादा समय तय करें। सुबह के समय गणित और विज्ञान जैसे विषयों की पढ़ाई करें क्योंकि इस समय आपका दिमाग सबसे अधिक सक्रिय होता है। आसान विषयों को दोपहर या शाम के लिए रखें।

समय का सही विभाजन करें

पढ़ाई के लिए दिनभर का समय तीन भागों में बांटें- सुबह, दोपहर और शाम। प्रत्येक विषय को उचित समय दें। उदाहरण के लिए, कठिन विषयों को 2 घंटे, आसान विषयों को 1.5 घंटे और रिवीजन को 1 घंटा दें। छोटे-छोटे ब्रेक के साथ पढ़ाई करने से थकान कम होती है और ध्यान केंद्रित रहता है।

रिवीजन को प्राथमिकता दें

हर दिन रिवीजन के लिए समय जरूर निकालें। दिनभर जो भी पढ़ा है, उसे रात को दोहराएं। सप्ताह के अंत में पूरे सप्ताह का रिवीजन करें। रिवीजन करने से याद की गई जानकारी लंबे समय तक बनी रहती है और परीक्षा के समय तनाव कम होता है।

मॉक टेस्ट और पुराने प्रश्न पत्र हल करें

मॉक टेस्ट और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करना परीक्षा की तैयारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे परीक्षा पैटर्न का अंदाजा होता है और समय प्रबंधन में सुधार होता है। यह आपके कमजोर क्षेत्रों को पहचानने और उन्हें मजबूत बनाने में मदद करता है।

खुद को पुरस्कृत करें

पढ़ाई को मजेदार बनाने के लिए खुद को लक्ष्य पूरा करने पर पुरस्कृत करें। यदि आप दिनभर का टाइम टेबल पूरा करते हैं, तो अपने पसंदीदा शो देखें या दोस्तों के साथ समय बिताएं। इससे आप अगली बार और बेहतर करने के लिए प्रेरित होंगे।

तेलंगाना हाईकोर्ट ने जूनियर असिस्टेंट समेत 1000+ पदों पर निकली वैकेंसी, 8 जनवरी से शुरू होंगे आवेदन

सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर आया है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने टेक्निकल और नॉन-टेक्निकल पदों पर 1000 से ज्यादा वैकेंसी निकाली है। कोर्ट मास्टर, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट, जूनियर असिस्टेंट और एग्जामनर जैसे पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इच्छुक उम्मीदवार 8 जनवरी 2025 से आवेदन कर सकते हैं, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है।

कुल 1385 वैकेंसी जारी

आयु सीमा

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 34 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया

कुछ पदों के लिए कंप्यूटर बेस्ड लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जिसमें कुल 90 प्रश्न शामिल होंगे। 50 प्रश्न जनरल नॉलेज और 40 प्रश्न जनरल अंग्रेजी के पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न 1 अंक के होंगे। पेपर को हल करने के लिए उम्मीदवारों को कुल 120 मिनट मिलेंगे।

आवेदन शुल्क

कुछ पदों के लिए ओसी व बीसी कैटेगरी उम्मीदवारों को 600 रुपए बतौर फीस देने होंगे। जबकि एससी, एसटी व ईडब्ल्यूएस व एक्स

सर्विसमैन के लिए फीस 400 रुपए तय की गई है।

कैसे करें आवेदन

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट tshc.gov.in पर जाएं।

होम पेज पर दिए नोटिस पर क्लिक करें।

अलग-अलग पदों के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

मांगी गई जरूरी जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करें।

रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करें।

सावधानी पूर्वक आवेदन फॉर्म भरकर सबमिट करें।

फॉर्म सबमिट करते ही यूनिक नंबर जनरेट हो जाएगा।

भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें।

अग्निवीर वायु भर्ती के लिए 7 से शुरू होंगे आवेदन

अग्निपथ योजना के तहत भारतीय वायुसेना ने अग्निवीर वायु पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। इच्छुक उम्मीदवार 7 जनवरी से आवेदन कर सकते हैं। अग्निपथ योजना के तहत भारतीय वायुसेना ने अग्निवीर वायु पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। इच्छुक उम्मीदवार 7 जनवरी 2025 से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 27 जनवरी 2025 की रात 11 बजे तक जारी रहेगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थी भारतीय वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट (agnipathvayu.cdac.in) पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं।

शैक्षणिक पात्रता और सीमा

इसके लिए वायु सेना ने आयु सीमा साढ़े 17 से 21 वर्ष तक रखी है। 12वीं पास युवक-युवती जिन्हें गणित, भौतिकी व अंग्रेजी में कुल औसत अंक 50 फीसदी और

अंग्रेजी में 50 फीसदी अंक होगा। वे इसके लिए योग्य होंगे।

परीक्षा और चयन प्रक्रिया

सलेक्शन लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट के आधार पर होगा। पहले चरण में लिखित परीक्षा 22 मार्च 2025 से ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा की तारीख से 24-72 घंटे पहले अभ्यर्थियों को ईमेल के जरिए एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी होगी।

वहीं दूसरे चरण में शारीरिक दक्षता और मेडिकल जांच की जाएग। पुरुष अभ्यर्थियों को 1.6 किमी दौड़ 7 मिनट में पूरी करनी होगी। जबकि महिला अभ्यर्थियों को 1.6 किमी दौड़ 8 मिनट में पूरी करनी होगी।

आवेदन शुल्क

ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन के वक्त अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क के तौर पर 550 रुपये जीएसटी अतिरिक्त के साथ भुगतान करना होगा। अगर किसी तकनीकी कारण से शुल्क एक से अधिक बार कट जाता है, तो एक्स्ट्रा राशि वापस कर दी जाएगी।

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर जाएं।

अब होमपेज पर आवेदन लिंक पर क्लिक करें।

इसके बाद सभी आवश्यक विवरण भरें और आवेदन पत्र जमा कर दें।

अंत में भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट ले लें।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

राष्ट्रगान के अपमान पर नाराज हुए राज्यपाल आरएन रवि

चेन्नई। राजभवन ने एक बयान में कहा कि

एक चौंकाने वाली घटना में तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान और राष्ट्रगान के घोर अपमान पर गहरे दुख में सोमवार को राज्य विधानसभा छोड़ दी। वह सदस्यों को पारंपरिक संबोधन देने के लिए सदन में पहुंचे। राज्यपाल के कार्यालय ने %एक्स% पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि सदन की कार्यवाही के दौरान, राज्यपाल ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और स्पीकर एम अप्पावु से राष्ट्रगान गाने की अपील की। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तमिलनाडु विधानसभा में आज एक बार फिर भारत के संविधान और राष्ट्रगान का अपमान किया गया। राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारे संविधान में निहित प्रथम मौलिक कर्तव्य में से एक है। इसे सभी राज्य विधानमंडलों में राज्यपाल के अभिभाषण के आरंभ और अंत में गाया जाता है। आज सदन में राज्यपाल के आगमन पर केवल तमिल थाई वाज़्थु गाया गया।

दिल्ली में कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना लॉन्च की

नईदिल्ली। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और

वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने सोमवार को दिल्ली चुनाव से पहले पार्टी के अभियान के हिस्से के रूप में प्यारी दीदी योजना का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये मिलेंगे। महिला कल्याण के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए शिवकुमार ने मतदाताओं को आश्वासन दिया कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने के तुरंत बाद इस पहल को लागू किया जाएगा। लॉन्च इवेंट में बोलते हुए शिवकुमार ने कहा कि आज, मैं प्यारी दीदी योजना का शुभारंभ करने के लिए यहां आया हूं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस दिल्ली में सरकार बनाएगी और हम महिलाओं को 2,500 रुपये देंगे। यह कैबिनेट की पहली बैठक में ही तय किया जाएगा- उसी मॉडल पर जिसे हमने कर्नाटक में लागू किया था।

आतिशी को लेकर रमेश बिधूड़ी का विवादित बयान

नईदिल्ली। भाजपा के कालकाजी उम्मीदवार

रमेश बिधूड़ी एक और विवाद में घिर गए जब उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर उनके उपनाम को लेकर निशाना साधा। रोहिणी में एक परिवर्तन रैली में, जिसे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बाद में संबोधित किया, बिधूड़ी ने कहा कि आतिशी ने अपना उपनाम मार्लेना से बदलकर सिंह कर लिया। उन्होंने कहा कि यही मार्लेना (आतिशी द्वारा पहले इस्तेमाल किया गया उपनाम) सिंह बन गई। केजरीवाल ने अपने बच्चों को दिलाई थी भ्रष्ट कांग्रेस के साथ न जाने की कसम, मार्लेना ने बदला पिता पहले वो मार्लेना थीं, अब सिंह बन गई हैं। यही उनका चरित्र है। आम आदमी पार्टी ने बिधूड़ी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि भाजपा के नेता बेशर्मी की सारी हदें पार कर रहे हैं। केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि बीजेपी के नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी।

प्रशांत किशोर को क्यों किया गया गिरफ्तार?

पटना। पटना में गांधी मैदान इलाके के पास

पुलिस और जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर के समर्थकों के बीच झड़प के बाद तनाव बढ़ गया। यह विवाद सोमवार को किशोर की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के दौरान हिरासत में लिए जाने के बाद हुआ, जिसमें कथित बीपीएससी परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। किशोर की गिरफ्तारी की उनके समर्थकों ने व्यापक निंदा की, जिन्होंने सरकार पर किशोर द्वारा जनता के बीच पैदा की गई एकता के डर से विरोध को चुप कराने का प्रयास करने का आरोप लगाया। इन सबके बीच पटना डीएम डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने प्रशांत किशोर को लेकर बड़ा बयान दिया है। चन्द्रशेखर सिंह ने कहा कि गांधी मैदान के प्रतिबंधित क्षेत्र में गांधी प्रतिमा के सामने कुछ लोग अवैध रूप से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध रूप से विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में गांधी मैदान थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

एकनाथ शिंदे को मिली जान से मारने की धमकी

मुंबई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

को धमकी देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जानकारी के मुताबिक, इंस्टाग्राम लाइव पर एक युवक ने डिप्टी सीएम शिंदे को गाली दी और धमकी दी। बताया जा रहा है कि शिंदे को धमकी देने वाला शख्स ठाणे का रहने वाला हितेश प्रकाश ढेंडे (24) है। इस मामले में ठाणे के श्रीनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस युवक की तलाश कर रही है। शिवसेना पदाधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर इलाके के हितेश ढेंडे नाम के शख्स ने इंस्टाग्राम पर लाइव वीडियो बनाकर एकनाथ शिंदे को अभद्र पोस्ट करते हुए जान से मारने की धमकी दी है। जानकारी के मुताबिक, वीडियो वायरल होने के बाद गुस्साए शिवसेना पदाधिकारी बड़ी संख्या में श्रीनगर पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए। उन्होंने युवक के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। पुलिस द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद भी शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है।

दिल्लीवालों को प्रधानमंत्री मोदी ने दिलाया भरोसा

भाजपा सत्ता में आई तो बंद नहीं होगी कोई कल्याणकारी योजना

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लोगों को आश्वासन दिया कि अगर विधानसभा चुनाव में भाजपा सत्ता में आई तो कोई भी जन कल्याणकारी योजना बंद नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार एक कदम आगे बढ़ेगी और योजनाओं के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार को खत्म करेगी। आप पर वार करते हुए मोदी ने कहा कि दिल्ली चुनाव में अपनी हार को देखते हुए उन्होंने झूठ फैलाना शुरू कर दिया है कि अगर बीजेपी आएगी तो इसे रोक दिया जाएगा, उसे रोक दिया जाएगा। मोदी ने साफ तौर पर कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा।

मोदी ने रोहिणी में परिवर्तन रैली में कहा कि मैं दिल्ली की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बीजेपी सरकार में जन कल्याण की कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि जिन योजनाओं में आपदा लोगों ने लोगों का पैसा लूटा है, उन योजनाओं में भी ईमानदार लोगों को लगाकर पूरी ईमानदारी से चलाया जाएगा। चुनाव से पहले दिल्ली में यह मोदी का दूसरा राजनीतिक भाषण था, जहां उन्होंने आप पर बिना किसी रोक-टोक के हमला जारी रखा और दोहराया कि पार्टी दिल्ली के लिए आपदा है। यह शब्द उन्होंने शुक्रवार को अशोक विहार में अपने भाषण में गढ़ा था।

आप सरकार वर्तमान में कई योजनाएं चला रही है, जिनमें मुफ्त 200 यूनिट बिजली, मुफ्त 20,000 लीटर पानी और डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शामिल है। आप पदाधिकारी पहले भी दावा कर चुके हैं कि भाजपा इन मुफ्त सुविधाओं को खत्म कर देगी। वहीं, मोदी ने दिल्ली की आप सरकार पर केंद्र के साथ लड़ाई में एक दशक बर्बाद करने का आरोप लगाया और अपने लोगों

से भाजपा को राष्ट्रीय राजधानी को भविष्य का शहर बनाने का मौका देने का आग्रह किया। मोदी ने कहा कि जब दिल्ली में इस आपदा से छुटकारा मिलेगा तभी विकास का डबल इंजन आएगा।

प्रधानमंत्री ने दी रेल परियोजनाओं की सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये रेल परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने जम्मू रेलवे डिवीजन का शुभारंभ किया। साथ ही तेलंगाना में चार्लापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन किया। इसके अलावा पूर्वी तट रेलवे के रायगडा रेलवे डिवीजन भवन की आधारशिला रखी।

पीएम मोदी ने कहा कि 2025 की शुरुआत से ही भारत कनेक्टिविटी की तेज रफ्तार बनाए हुए है। मैंने रविवार को दिल्ली एनसीआर में नमो भारत ट्रेन का शानदार अनुभव लिया और दिल्ली मेट्रो की अहम परियोजनाओं की शुरुआत की। कल भारत ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हमारे देश में अब मेट्रो नेटवर्क एक हजार किलोमीटर से ज्यादा का हो गया है।

पीएम मोदी ने कहा कि 2-3 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था इसमें वंदे भारत ट्रेन का नया स्लीपर वर्जन ट्रायल में 180 किमी/घंटा की गति से चल रहा था। यह न केवल मुझे अच्छा लग रहा है, बल्कि निश्चित रूप से सभी को अच्छा लगा होगा। यह तो बस शुरुआत है। वह समय दूर नहीं जब देश में पहली बुलेट ट्रेन चलेगी।

उन्होंने कहा कि हमने देखा है, पिछला एक दशक भारतीय रेलवे के ऐतिहासिक परिवर्तन का रहा है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बदलाव आया है। इससे देश की छवि बदली है और देशवासियों का मनोबल भी बढ़ा है। भारत में रेलवे के विकास को हम चार पैरामीटर्स पर आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें पहला रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण, दूसरा रेलवे के यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं, तीसरा रेलवे की देश के कोने-कोने में कनेक्टिविटी और चौथा रेलवे से रोजगार का निर्माण, उद्योगों को सहयोग शामिल है।

पीएम मोदी ने कहा कि बीते 10 साल में रेल कनेक्टिविटी का भी अद्भुत विस्तार हुआ है। 2014 तक देश में सिर्फ 35 प्रतिशत रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ था। आज भारत रेल लाइनों के शत-प्रतिशत विद्युतीकरण के करीब है। हमने रेलवे की पहुंच को भी लगातार बढ़ाया किया है। बीते 10 साल में 30 हजार किमी से ज्यादा नए रेलवे ट्रैक बिछाए गए हैं। साथ ही सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए हजारों ओवरपास और अंडरपास भी बनाए गए हैं। आज लोग कम समय में लंबी दूरी तय करना चाहते हैं। इसलिए हमने पूरे देश में हाई-स्पीड ट्रेनें चलाई हैं। आज 50 से अधिक रूटों पर वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। 136 वंदे भारत सेवाएं लोगों की यात्रा को आरामदायक बना रही हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि हमारा जम्मू-कश्मीर आज रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में नए रिकॉर्ड बना रहा है। उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लाइन की चर्चा आज पूरे देश में है। ये परियोजना जम्मू-कश्मीर को देश के और हिस्सों के साथ और बेहतरी से जोड़ेगी। इसी परियोजना के तहत दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे केबल पुल चिनाब का काम भी पूरा हुआ है।

दिल्ली में फाइनल वोटर लिस्ट जारी

दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जिसको लेकर चुनाव आयोग ने सोमवार को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। इस बार एक करोड़ 55 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे।

चुनाव आयोग के मुताबिक, दिल्ली विधानसभा चुनाव की अंतिम मतदाता सूची में कुल 1,55,24,858 मतदाता है। जिसमें 83 लाख पुरुष और 71 लाख महिला मतदाता शामिल हैं। फाइनल वोटर सूची जारी होने के बाद अब जल्द ही चुनाव की तारीखों का एलान हो सकता है।

चुनाव आयोग की ओर से कई बैठकों का दौर चल रहा है। बताया जा रहा है कि चुनाव की तारीख की घोषणा 6 से 10 जनवरी के बीच हो सकती है। हालांकि, अभी तारीखों पर दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है।

विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी, 2025 तक का है। इससे पहले दिल्ली विधानसभा का गठन करने के लिए चुनाव होने हैं। इसके लिए दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। सूत्रों का कहना है कि चुनाव के लिए दिसंबर की जगह जनवरी के पहले या फिर दूसरे सप्ताह के बीच तारीखों की घोषणा होगी। पिछले चुनाव की बात की जाए तो 6 जनवरी 2020 को तारीखों की घोषणा की गई थी।

सरपंच हत्याकांड में शरद पवार ने सीएम फडणवीस को लिखा पत्र

मुंबई। सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड को लेकर महाराष्ट्र में सियासत तेज है। अब एनसीपीएसपी प्रमुख शरद पवार ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को देशमुख हत्याकांड और उसके बाद पूरे राज्य में पैदा हुई स्थिति के बारे में पत्र लिखा है।

उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि बीड में संतोष देशमुख की मौत के खिलाफ आंदोलन कर रहे सभी जन प्रतिनिधियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

पुलिस के अनुसार, सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के पीछे एक बड़ी जबरन वसूली का मामला है। बीड जिले में पवन चक्कियां स्थापित करने वाली एक ऊर्जा कंपनी से कथित तौर पर दो करोड़ रुपये की वसूली की जा रही थी। देशमुख ने इस जबरन वसूली का विरोध किया था, जिसके बाद नौ दिसंबर को उनका अपहरण किया गया और फिर हत्या कर दी गई। उनकी मौत के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया, जिसके बाद चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं, कुछ दिन पहले, महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे के करीबी सहयोगी वाल्मीक कराड ने पुणे में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। कराड को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अभी तक कुल सात आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं।

इस मामले में सीएम फडणवीस लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं। उन्होंने साफ कहा कि वह किसी भी दोषी को नहीं बख्शेंगे। सीएम ने हाल ही में कहा था, %बीड मामले में सरकार और पुलिस पूरी ताकत व दृढ़ता से काम कर रही हैं। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। देशमुख एक लोकप्रिय सरपंच थे, इसलिए उनकी हत्या को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यहां तक कि अगर आरोपी फरार हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हम उन लोगों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, जिन्होंने आरोपियों की मदद की। एजेंसियों को मामले की सही तरीके से जांच करने दिया जाना चाहिए।

वाल्मिक कराड की पत्नी से भी हुई थी पूछताछ

इस मामले में वाल्मिक कराड की पत्नी मंजिली कराड से भी पुलिस ने इस मामले को लेकर पूछताछ की है। सीआईडी ने मंजिली कराड, उनके दो बॉडीगार्ड, अजित पवार गुट के बीड जिला अध्यक्ष समेत कई लोगों के खिलाफ जांच की है। पुलिस ने बीड के जिला अध्यक्ष संध्या सोनावणे से भी पूछताछ की है। इस पूरे मामले में संध्या सोनावाणे और तीन अन्य की जांच सीआईडी ने की है। इन लोगों से रविवार को आठ घंटे से भी ज्यादा देर तक पूछताछ की गई है। इस पूछताछ के बाद संध्या सोनावणे ने मीडिया को बताया कि राजनीति में रहते हुए हर किसी से संपर्क हो जाता है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे आगे जब भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा मैं आगे भी पूछताछ में सहयोग करूंगी।

कांग्रेस ने की सीबीआई जांच की मांग

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने बीड सरपंच संतोष देशमुख की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। वडेट्टीवार ने कहा कि सरकार बीड में भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर अपनी आंख मूंदे हुए है। कराड को राजनीतिक आशीर्वाद प्राप्त है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि इस पूरे मामले में सरपंच देशमुख के परिवार को न्याय मिलना चाहिए।

खेल
प्रमुख समाचार

टीम इंडिया को नहीं जंच रही गंभीर की कोचिंग?

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हारने के बाद

भारतीय टीम और उसके कोचिंग स्टाफ पर सवाल खड़े होने लगे हैं। महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने तो भारतीय खिलाड़ियों के साथ-साथ कोचिंग टीम पर भी निशाना साधा था। सवाल उठना लाजमी भी है क्योंकि गौतम गंभीर और उनकी नई कोचिंग टीम के पदभार संभालने के बाद से भारतीय टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। टीम लगातार अनचाहे रिकॉर्ड बना रही है और हार पर हार मिल रही है। ऑस्ट्रेलिया में हार के साथ ही टीम इंडिया ने लगातार दूसरी टेस्ट सीरीज गंवा दी। फैंस का तो यहां तक कहना है कि गंभीर की कोचिंग टीम इंडिया को नहीं जंच रही है। भारतीय टीम ने पिछले साल जून में टी20 विश्व कप जीता था। हालांकि, इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद से टीम इंडिया की स्थिति कुछ खास नहीं रही है। फैंस को पिछले जून में जश्न मनाने का मौका मिला था, लेकिन इसके बाद से फैंस टीम इंडिया के प्रदर्शन कुछ खास खुश नहीं हैं। टी20 विश्व कप 2024 में टीम इंडिया की जीत के बाद राहुल द्रविड़ के कार्यकाल का अंत हुआ था और गौतम गंभीर ने मुख्य कोच के रूप में कदम रखा था। ऐसा माना जा रहा था कि वह अपने साथ एक नया दृष्टिकोण लाएंगे और भारतीय टीम और ज्यादा आक्रामक होकर खेलेगी। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ उनकी सफलता के बाद गंभीर की नियुक्ति ने फैंस के मन में उम्मीदें जगाई थीं। हालांकि, जुलाई में गंभीर के पद संभालने से लेकर अब तक भारत की अप्रत्याशित हार की कल्पना किसी ने नहीं की थी। गंभीर की देखरेख में टीम इंडिया ने एक टी20 सीरीज, एक वनडे सीरीज और तीन टेस्ट सीरीज खेली है, जिसमें खराब परिणाम मिले हैं। गंभीर ने टी20 में अपने 100 प्रतिशत जीत के रिकॉर्ड को बनाए रखा है, लेकिन उनकी कोचिंग में टीम इंडिया अभी भी अपनी पहली वनडे सीरीज जीत की तलाश में है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स दो दिन में करीब 2000 अंक गिरा

नईदिल्ली। अमेरिकी शेयर बाजारों में तेजी के बावजूद भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सेशन सोमवार को औंधे मुंह लुढ़क गए। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस के भारत में 2 मामले दर्ज किए जाने के बाद बाजार में चौतरफा बिकवाली देखी गई। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स सोमवार (6 जनवरी) को 50 से ज्यादा अंक चढ़कर 79,281.65 पर खुला। कुछ देर उतार-चढ़ाव के बाद यह लाल निशान में फिसल गया। कारोबार के दौरान यह 1440 अंक तक गिर गया था। अंत में सेंसेक्स 1258 अंक या 1.59% की गिरावट लेकर 77,964.99 पर बंद हुआ। इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी50 भी बढ़त के साथ खुला। भारी बिकवाली बिकवाली के बाद 24,700 से नीचे फिसल गया। अंत में निफ्टी 388.70 अंक या 1.62% की बड़ी गिरावट के साथ 23,616.05 पर क्लोज हुआ।

बाजार की चौतरफा बिकवाली में चमका टाटा ग्रुप का दिग्गज

नईदिल्ली। टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन के शेयर सोमवार के इंट्रा-डे कारोबार में बीएसई पर 3 प्रतिशत तक की बढ़त के साथ 3,527.20 रुपये के दो महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। कंपनी के शेयरों में यह उछाल चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के अपडेट जारी करने के बाद आया है। जूलरी स्टोर तनिष्क ब्रांड चलाने वाली कंपनी के शेयर की कीमत पिछले तीन कारोबारी दिनों में 8.4 प्रतिशत बढ़ी है। यह 15 अक्टूबर 2024 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रहा है। टाइटन अपने ब्रांड तनिष्क के साथ भारत में एक भरोसेमंद जूलरी ब्रांड है। साथ ही यह दुनिया में पांचवी सबसे बड़ी घड़ी बनाने वाली कंपनी है। कंपनी के पास 429 शहरों में 3,171 स्टोरों की सितेल सीरीज है। इसमें उसके सभी ब्रांडों के लिए 4.44 मिलियन वर्ग फुट का रिटेल क्षेत्र है।

दिसंबर में सर्विस सेक्टर का पीएमआई 59.3 पर पहुंचा

नईदिल्ली। दिसंबर 2024 में भारत का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) बढ़कर 59.3 अंक पर पहुंच गया, जो नवंबर में 58.4 था। यह देश में सर्विस सेक्टर में हो रही बढ़ोतरी को दर्शाता है। एसएंडपी ग्लोबल द्वारा जारी एचएसबीसी इंडिया सर्विस पीएमआई ने सोमवार को बताया कि निरंतर मांग में उछाल ने व्यापार को बढ़ाने में मदद की, जिसने उत्पादन बढ़ा और फर्मों को अधिक से अधिक लोगों को काम देने का मौका किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि एचएसबीसी इंडिया सर्विस बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स नवंबर में 58.4 से बढ़कर दिसंबर में 59.3 हो गया, जो चार महीनों में सबसे मजबूत विस्तार को दिखाता है। उत्पादन में बढ़ोतरी के पीछे मुख्य कारण मांग में बढ़ोतरी है, जिसमें लगातार इकतालीसवें महीने नए ऑर्डर बढ़े। कंपनियों ने इस बढ़ोतरी का श्रेय विस्तार के लगातार चल रहे प्रयासों को दिया, जिससे उन्हें अधिक काम संभालने में मदद मिली।

कोटक एमएफ की नई स्कीम में 100 रुपये से निवेश शुरू

नईदिल्ली। एसेट मैनेजमेंट कंपनी कोटक महिंद्रा म्युचुअल फंड ने इक्विटी कैटेगरी में नया स्माल कैप फंड लॉन्च किया है। म्युचुअल फंड हाउस के एनएफओ कोटक निफ्टी स्मालकैप 250 इंडेक्स फंड का सब्सक्रिप्शन 6 जनवरी से खुल गया है। सब्सक्राइबर 20 जनवरी 2025 तक इस एनएफओ में आवेदन कर सकते हैं। यह ओपन एंडेड स्कीम है और यह अलॉटमेंट के बाद 30 जनवरी या उससे पहले खरीद-बिक्री के लिए दोबारा खुलेगी। कोटक म्युचुअल फंड हाउस के मुताबिक, कोटक निफ्टी स्मालकैप 250 इंडेक्स फंड में मिनिमम 100 रुपये और उसके बाद किसी भी अमाउंट में निवेश कर सकते हैं। इसका बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी स्मालकैप 250 इनडेक्स है। इस स्कीम में एग्जिट लोड नहीं है। स्कीम के फंड मैनेजर देवेन्द्र सिंघल, सतीश डोंडापति और अभिषेक बिसेन हैं।

क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा के संन्यास का समय आ गया है?

विनोद पाठक

सिडनी टेस्ट मैच में टीम इंडिया के आत्मसर्मपण ने एक बार फिर नामचीन खिलाड़ियों पर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया है। टीम इंडिया न केवल ऑस्ट्रेलिया में मेजबानों से बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी दस साल बाद हारी, बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस से भी बाहर हो गई है। घर में न्यूजीलैंड से हारकर आई टीम इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरा बुरे सपने जैसा है।

सिडनी टेस्ट में एक कमाल यह भी हुआ कि कप्तान रोहित शर्मा को ही बाहर बैठना पड़ गया। यह कैसा प्रयोग था? जो किसी को समझ नहीं आया। कई पूर्व खिलाड़ियों ने इसकी घोर आलोचना की है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, के.एल. राहुल जैसे वरिष्ठ खिलाड़ी सीरीज में बेहद नाकाम साबित हुए हैं। टीम इंडिया की बल्लेबाजी की जो दुर्गति ऑस्ट्रेलिया में हुई है, वो आज के दौर में अकल्पनीय है।

विराट-रोहित का प्रदर्शन निराशाजनक

शुरुआत विराट कोहली के प्रदर्शन से करते हैं। टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट, जो पर्थ में खेला गया था, केवल उसमें विराट ने एक पारी में नाबाद शतक लगाया था। उसके बाद चार मैचों में उनका प्रदर्शन बेहद खराब रहा। पर्थ के बाद विराट ने सात और परियों में बल्लेबाजी की, जिसमें केवल दो बार में दोहाई के आंकड़े तक पहुंचे। इन सात पारियों में उनका अधिकतम स्कोर 36 रन था। जब भी टीम इंडिया को विराट कोहली से अच्छी बल्लेबाजी की उम्मीद जागी, विराट विकेट गंवाकर पैवेलियन लौट आए।

कप्तान रोहित शर्मा पर्थ टेस्ट में पारिवारिक कारणों से नहीं खेल सके थे। शेष चार में से तीन टेस्ट मैचों में रोहित ने कप्तानी

की। इनमें उनका अधिकतम स्कोर 10 रन रहा। रोहित के बल्ले से न चौके निकले और न ही छक्के। उनकी कप्तानी में तीनों ही मैचों में भारत को निराशा मिली। इंतहां तो तब हो गई, जब सिडनी टेस्ट में रोहित को टीम से बाहर कर बैंच पर बैठा दिया गया, जिसकी क्रिकेट जगत में आलोचना हो रही है। एक नया विवाद ही खड़ा हो गया। हालांकि, रोहित ने सफाई दी कि यह उनका निर्णय था, लेकिन संभवत: उनकी खराब बल्लेबाजी को लेकर बीसीसीआई ने यह कदम उठाया है।

एक और खिलाड़ी है, जिनके कारण टीम इंडिया को सीरीज में नुकसान उठाना पड़ा, वो विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत है। ऋषभ टेस्ट मैच को टेस्ट की तरह न खेलकर टी-20 समझते हैं। उनके खराब शॉट सिलेक्शन से टीम को नुकसान हुआ है। पांच मैचों में केवल सिडनी में उनका प्रदर्शन थोड़ा बहुत ठीक रहा, जिसमें उन्होंने एक पारी में 40 और एक में 61 रन बनाए। बाकी चारों मैच में वो एक बेहद अनुभवहीन खिलाड़ी लगे।

धैर्य की कमी पंत में साफ नजर आई। बीसीसीआई को टेस्ट क्रिकेट के लिए जल्द नया विकेटकीपर ढूंढना चाहिए। पंत को टी-20 मैचों में मौका दिया जाता रहे, वही बेहतर होगा।

खुद को साबित नहीं कर पाए कई खिलाड़ी

के.एल. राहुल ने भी पर्थ और ब्रिस्बेन में थोड़े रन बनाए, लेकिन बाकी मैचों में उनका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। केएल राहुल को परी की शुरुआत का मौका दिया गया, लेकिन वो खुद को साबित नहीं कर पाए। टीम में अंदर और बाहर हो रहे केएल राहुल के लिए यह सीरीज झटका देने वाली साबित हो सकती है। शुभमन गिल हो या नीतीश कुमार रेड्डी, यह भी एक-दो मैचों को छोड़कर बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। कुल मिलाकर भारतीय बल्लेबाजों की ऑस्ट्रेलिया में पोल खुल गई।

विराट और रोहित टी-20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं। दोनों अब केवल वनडे और टेस्ट खेल रहे हैं, लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में दिया है, उससे लग रहा है कि बीसीसीआई को एक सख्त निर्णय लेने की जरूरत है। समय आ गया है कि युवाओं को आगे मौका दिया जाए। एक नई टीम का गठन बीसीसीआई जल्द करे।

सरकार कर्मियों के हर सुख-दुख में उनके साथः साव

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव आज रायपुर के स्वर्गीय बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय अधिकारी-कर्मचारी अधिवेशन में शामिल हुए। नगरीय निकायों के विभिन्न अधिकारी-कर्मचारी संघों द्वारा प्रदेश में पहली बार प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन किया गया था। उप मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में ईव्ही फास्ट चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ भी किया। रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल और विधायकगण सुनील सोनी और पुरंदर मिश्रा भी अधिवेशन में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय अधिकारी-कर्मचारी अधिवेशन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का दायित्व मिलने के बाद नगरीय निकायों में काम करने वाले कर्मचारियों का कल्याण पहले दिन से मेरी प्राथमिकता में रहा है। पिछले एक वर्ष में अनुकंपा नियुक्ति और पदोन्नति के विषय में सक्रियता से काम हुए हैं। विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों पर संवेदनशीलता से विचार करते हुए 353 नए पद स्वीकृत किए हैं।

डिप्टी सीएम साव ने कहा कि उन्होंने सभी नगरीय निकायों को इन स्वीकृत नए पदों पर 10 जनवरी तक अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। विभाग में पदोन्नति की प्रक्रिया भी लगातार चल रही है। अभियंताओं की पदोन्नति के बाद अभी 36 कर्मचारियों को सीएमओ पदोन्नत किया गया है। अन्य पदों पर भी इसकी कार्यवाही चल रही है। सभी निकायों के सेट-अप पुनरीक्षण के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं।

उप मुख्यमंत्री साव ने अधिवेशन में कहा कि कर्मचारियों की जरूरतों व मांगों को लेकर सरकार संवेदनशील है। विगत एक वर्ष में वेतन के भुतान के लिए नगरीय निकायों को 373 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। लंबित वेतन के भुगतान के लिए 51 करोड़ 77 लाख रुपए जारी करने की फाइल पर आज ही दस्तखत करके आ रहा हूं। ओपीएस तथा छटवें एवं सातवें वेतनमान के एरियर्स के लिए भी हम लोग वित्त विभाग से चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए विभाग निकायों के नए सिरे से वर्गीकरण के साथ ही इनकी संरचना को मजबूत करने की पहल कर रहा है। डिप्टी सीएम साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अधिकारियों-कर्मचारियों के हर सुख-दुख में उनके साथ है। उनकी सभी समस्याओं के निवारण के लिए तत्पर है।डिप्टी सीएम साव ने अधिकारियों-कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि नगरीय निकाय के कर्मचारी शहर के हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा होता है। शहरों को संवारने की महती जिम्मेदारी आप लोगों पर है। शहर और शहरवासियों को आप लोग अपना परिवार मानकर काम करेंगे तो काम के साथ बेहतर जुड़ाव होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि आप लोग इस अधिवेशन से अपने निकायों को मजबूत और सुदृढ़ करने का संकल्प लेकर जाएंगे। लोगों तक सरकार की योजनाएं पहुंचाने के लिए नए उत्साह और ऊर्जा से काम करेंगे।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोग निकायों के अधिकारियों-कर्मचारियों से लगातार जुड़े हुए हैं। उनकी समस्याओं से हम लोक वाकिफ हैं। सरकार आप लोगों के सुख-दुख से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता से कर रही है। उन्होंने निकाय के कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण का सुझाव दिया।

मेरी बात

✍ गिरीश पंकज

पत्रकार की हत्या

बस्तर में एक पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई. पुलिस की तत्परता के कारण पत्रकार के सभी निर्मम हत्यारे गिरफ्तार हो गए. हत्यारों की सारी अकड़ भी खाक में मिल गई. अपनी अर्जित आर्थिक हैसियत के कारण वे तन कर चला करते थे. शादी में करोड़ों रुपए काअपव्यय करके खुश थे. अब वही जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं. और इस देश में अगर न्याय जिंदा है तो उन्हें आजीवन कारावास मिलना चाहिए और मुख्य आरोपी को फांसी की सजा भी मिले तो कम है. अब बात पत्रकारिता की अभिव्यक्ति की. बस्तर में इसके पहले भी पत्रकारों की हत्याएं होती रही है. कुछ हत्याएं नक्सलियों ने की. एक पुरानी कविता है कि प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पर धावनों है. इस कविता में प्रेम की जगह प्रेस कर देना चाहिए. प्रेस को पंथ कराल महा तलवार की धार पर धावनो है. नि:संदेह.भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है. लेकिन क्या सचमुच पत्रकारिता में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है. पत्रकार दुनिया भर को आईना दिखा सकता है, लेकिन जैसे ही वह सरकार को आईना दिखाने लगता है, तो उसके सामने खतरे बढ़ने लगते हैं. पिछली कांग्रेस सरकार में हमने यह देखा. कुछ पत्रकारों को विशुद्ध रूप से अभिव्यक्ति के कारण प्रताड़ित किया गया. उन्हें जेल भेज दिया गया. वे और उनके परिवार के लोग मानसिक संत्रास से गुजरते रहे. मुझे लिखने में रत्ती भर का संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी पत्रकार प्रताड़ित होते रहे. अब यह सिलसिला बंद होना चाहिए. भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सरकार इस बार के लिए वचनबद्ध हो कि सरकार के विरुद्ध लिखे जाने पर किसी भी पत्रकार को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा. आपत्ति है, तो उसे पत्रकार पर मानहानि का मुकदमा चलाया जा सकता है. लेकिन फर्जी एफ़आइआर दर्ज करके उसे गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए. लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से कम होना चाहिए. न कि सामंती अंदाज में. राजतंत्र में ऐसा होता था. अंग्रेजों के शासनकाल में भी ऐसा होता था. जिस स्वतंत्रता सेनानी ने अंदर कर दिया जाता था. कहा जाता था, यह राजद्रोह कर रहा है. ठीक है उस समय अंग्रेजों के खिलाफ लिखा जाना, उनकी नज़रों में एक तरह से राजद्रोह ही था. लेकिन आपको देश आजाद है. अब तो किसी भी सरकार के विरुद्ध दिखा जा सकता है. अगर कोई चुनी हुई सरकार कुछ गलत कर रही है, तो हर पत्रकार और अख़बार का दायित्व है कि वह उसके विरुद्ध आवाज़ उठाए. लेकिन मेरा निजी अनुभव यह है की सरकार के विरुद्ध लिखने पर सरकार का कोई पिछलग्गू उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कर देता है. कुछ तो पत्रकार पर झूठे आरोप लगा देते है कि वह पैसे मांग रहा था. पत्रकार पर ब्लैकमेल का आरोप आसानी से लगाया जा सकता है. किसी आरोप के तहत देश के अनेक पत्रकारों पर कार्रवाई होती रही है. पत्रकारों पर ऐसे आरोप बिल्कुल उसी तरह के होते हैं, जैसे कोई बहू थाने में जाकर ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा दे. सबको पता है कि ज्यादातर आप झूठे होते हैं. मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगता है कि आज भी पत्रकारिता जिंदा है. आज भी पत्रकारों का जमीर जिंदा है. आज भी ऐसे पत्रकार हैं जो बिकते नहीं. बस्तर में ऐसे पत्रकारों की भरमार है. वे बेबाकी के साथ सच लिखते हैं. भले ही उनकी जान चली जाए. पिछले साल बस्तर के पत्रकार को सच लिखने के कारण फर्जी तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया था. उनकी गाड़ी में गांजा रखकर आरोप लगाया कि वह गांजा की तस्करी कर रहे थे. पत्रकारों के सामने बड़ी चुनौती यही है की पुलिस के खिलाफ लिखो तो पुलिस पीछे पड़ जाती है.नक्सलियों के विरुद्ध लिखो तो नक्सली पीछे पड़ जाते हैं, और माफिया के विरुद्ध लिखो तो वे जान लेने पर आमादा हो जाते हैं. लेकिन इतना सब होने के बावजूद सच्ची कलम न झुकती है, न रूकती है. चलती रहती है भले ही जान चली जाए. किसी पत्रकार की हत्या के मामले में कोई भी सरकार कुछ नहीं कर सकती भले ही अपराधी बाद में पकड़ में आ जाए, वह एक प्रक्रिया है. लेकिन वह पत्रकार सुरक्षा कानून तो बना ही सकती है. वर्तमान सरकार के मुखिया विष्णु देव साय ने पत्रकार सुरक्षा कानून की बात तो की है. उम्मीद है कि यह जल्द से जल्द बन जाएगा.

लीगल असिस्टेंट- 11 जनवरी को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में चयनित अभ्यर्थियों का होगा इंटरव्यू

बिलासपुर। लीगल असिस्टेंट पद के लिए जिन अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा पास कर ली है,उनको इंटरव्यू के लिए काल किया गया है। रजिस्ट्रार जनरल के. विनोद कुजूर ने लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए काल किया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट परिसर में 11/01/2025 को प्रात: 10.30 बजे जरुरी दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहने कहा गया है। देखें आदेश

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने जारी आदेश में कहा है कि इंटरव्यू के लिये पात्र अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की वेबसाइट में अपलोड कर दिया गया है। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र उच्च न्यायालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जो अभ्यर्थी के साक्षात्कार के लिये अधिकृत प्रवेश पत्र होगा। कृपया ध्यान रखें कि किसी भी आवेदक को अन्य किसी माध्यम से प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जायेगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार भी स्वीकार ना करने की बाब कही गई है।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने लीगल असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में पास 74 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए प्रवेश पत्र जारी करने के साथ ही तिथि भी तय कर दी है। पात्र उम्मीदवारों को 11 जनवरी को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया गया है। इनका इंटरव्यू हाई कोर्ट परिसर में होगा। किन-किन उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इंटरव्यू के लिए काल किया है। लीगल असिस्टेंट के पद हेतु पात्र पाये गये अभ्यर्थियों की सूची छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने वेबसाइट पर जारी कर दिया है। इसमें अपात्र अभ्यर्थियों की भी सूची अपलोड की गई है।

लाना होगा शैक्षणिक दस्तावेजों की ओरिजनल कापी: पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय समस्त शैक्षणिक, तकनीकी एवं अन्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति साथ ही अभ्यर्थियों द्वारा ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की गई नोटरीकृत घोषणा पत्र की मूल प्रति भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ये दस्तावेज ना लाने की स्थिति में उम्मीदवारों को साक्षात्कार से वंचित किया जा सकता है।

इन उम्मीदवारों को दिखाना होगा जरुरी दस्तावेज: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि साथ ही जिन अभ्यर्थियों को किसी शर्त के तहत पात्र किया गया है उन्हें उस शर्त के आधार पर चाही गई जानकारी / दस्तावेज साक्षात्कार के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा, दस्तावेज पेश ना करने की स्थिति में इंटरव्यू से बाहर भी किया जा सकता है

बैंकिंग सेक्टर में ग्राहक सुविधा सर्वोपरी: केएन कांडे

अपेक्स बैंक में नवनियुक्त एम्प्लाइज का तीन दिवसीय प्रशिक्षण शुरू

रायपुर।अपेक्स बैंक द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी प्रशिक्षण संस्थान पंडरी रायपुर में तीन दिवसीय प्रशिक्षण सत्र आज से शुरू हो गया है। प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ कोआपरेटिव्ह व अपेक्स बैंक के ज्वाइंट कमिश्नर व प्रबंध संचालक श्री के एन कान्डे ने किया। इस अवसर पर प्रशिक्षण संस्थान के डायरेक्टर व अपेक्स बैंक के डीजीएम श्री भूपेश चंद्रवंशी तथा डिप्टी डायरेक्टर व प्रबंधक श्री ए के लहरे उपस्थित थे।प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री के एन कान्डे ने नवनियुक्त सहायक प्रबंधको, सामान्य सहायको तथा कार्यालय सहायकों को संबोधित करते हुए कहा कि बैंकिंग सेक्टर में ग्राहक सुविधा सर्वोपरी है। छत्तीसगढ़ के किसान सीधे कोआपरेटिव्ह बैंकों तथा पैक्स सोसाइटियों से जुड़े है। किसानों की खेतीगत ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति कोआपरेटिव्ह बैंको से होती है। कोआपरेटिव्ह बैंको से खरीफ तथा रबी फसलों के अलावा डेयरी, मत्स्य, लाख पालन तथा उद्यानिकी लिए ब्याज मुक्त कृषि ऋण दिया जाता है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की पहल पर छत्तीसगढ़ में 'सहकार से समृद्धि' की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में नवगठित पैक्स सोसाइटी, डेयरी तथा मत्स्य सोसाइटियों का पंजीयन किया जा चुका है।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

सरकार नक्सलवाद पर अपना कोई राय नहीं बना पाई : बैज

रायपुर। बस्तर के बीजापुर में 9 जवानों की शहादत बेहद दुखद है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शहीद जवानों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है, शहीद जवानों के परिजनों के प्रति अपनी एकजुटता प्रदर्शित करती है तथा घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है। देश को इन जवानों की वीरता पर गर्व है। सरकार के नक्सल मोर्चे पर असमंजस नीति के कारण इतनी बड़ी क्षति उठानी पड़ी। हमारे जवान शहीद हुये। हमारी सरकार से मांग है कि सरकार अपनी नक्सलवादी नीति स्पष्ट करें। सरकार के अनिर्णय वाली स्थिति के कारण जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है नक्सली गतिविधियां बढ़ी है। भाजपा की सरकार को तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता है। सरकार बने एक वर्ष से अधिक हो गया है अभी तक सरकार ने नक्सलवाद जैसे महत्वपूर्ण मसले पर अपना कोई राय नहीं बना पाई है। सरकार मति भ्रम का शिकार है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने नक्सलवाद पर एक ठोस नीति बनाया था विश्वास, विकास, सुरक्षा के मूल मंत्र को लेकर कांग्रेस सरकार आगे बढ़ी थी जिसके सकारात्मक परिणाम आये और राज्य में नक्सली गतिविधियों में 80 प्रतिशत तक की कमी आई थी।

कांग्रेस ने स्व-मुकेश चंद्राकर कांग्रेस के बड़े अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए: संजय

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस द्वारा पत्रकार स्व. मुकेश चंद्रकार का जीवित रहते भी बहिष्कार और मृत्यु के बाद भी बहिष्कार करने के लिए कांग्रेस नेताओं पर तीखा हमला है। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि इस संबंध में 29 अप्रैल, 2024 को कांग्रेस द्वारा बाकायदा जिला कांग्रेस कमेटी जिला बीजापुर के लेटरपेड में पत्र निकाल कर दिवंगत पत्रकार स्व. मुकेश चंद्रकार पर झूठे आरोप लगाकर सार्वजनिक रूप से उन्हें अपमानित कर उनका बहिष्कार करने का ऐलान किया था। भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री श्रीवास्तव ने सोमवार को एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस ब्रीफ में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि 04 जनवरी 2025 को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का तय कार्यक्रम जारी किया गया था, उसमें उनका रात्रि विश्राम काँकेर यानी कि बस्तर ही था।

सरकार के भ्रष्टाचार के कारण पत्रकार की हत्या हुई: शुक्ला

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा पत्रकार मुकेश चंद्रकार की हत्या पर स्तरहीन राजनीति कर रही है। भाजपा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने के बजाय हत्यारे को संरक्षण देने वाले भाजपा नेताओं पर कार्यवाही करे। भाजपा सरकार की अकर्मण्यता और सरकार मे बढ़ते हुये अपराध और अपराधिक तत्वों के संरक्षण के कारण भाजपा के भ्रष्टाचार के कारण जाबाज पत्रकार मुकेश चंद्रकार की हत्या हुयी। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि भाजपा स्पष्ट करे कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर का हत्यारा सुरेश चंद्रकार मुख्यमंत्री निवास क्यों गया था? जब यह स्पष्ट हो चुका है कि भाजपा की सदस्यता ले ली थी अभी तक उसे भाजपा से निकाला क्यों नहीं गया? प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि स्व. मुकेश चंद्रकार ने ठेकेदार सुरेश चंद्रकार के जिस भ्रष्टाचार को उजागर किया उस पर भाजपा जवाब दे? बिना काम पूरा हुये 90 प्रतिशत अग्रिम भुगतान बिना मंत्री, बिना सत्ता में बैठे हुए लोगों के संरक्षण के संभव है क्या? किसको ठेकेदार का संरक्षण था, उन सत्तारूढ़ दल के लोगों पर कार्यवाही कब होगी? इस भ्रष्टाचार में कौन-कौन संलिप्त है?

डिप्टी सीएम शर्मा ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री से की मुलाकात

रायपुर । उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। इस दौरान पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव और छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक विवेक आचार्य उपस्थित थे। इस दौरान राज्य में पर्यटन विकास की दो बड़ी योजनाओं के प्रस्ताव के उपमुख्यमंत्री शर्मा ने केंद्रीय मंत्री को सौंपे।मुख्यमंत्री साय के मार्गदर्शन और निर्देशानुसार स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत महाप्रभु वल्लभाचार्य यज्ञ कुंड परिसर, चंपारण्य के सौंदर्यीकरण और भोरमदेव कॉरिडोर जिला कबीरधाम की परियोजनाओं के लगभग 200 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भारत सरकार को सौंपे गए। इस प्रस्ताव में महाप्रभु वल्लभाचार्य यज्ञ कुंड परिसर, चंपारण्य में परिसर का सौंदर्यीकरण, प्रवेश द्वार, तालाब ब्यूटीफिकेशन, पार्किंग एरिया, महाप्रभु वल्लभाचार्य की भव्य प्रतिमा, म्यूजियम, कन्वेंशन सेंटर, भागवत कथा एवं प्रवचन हॉल, बच्चों के लिए गार्डन, कैफेटेरिया, सड़क निर्माण, लैंडस्कैपिंग, सोवेनियर शॉप, पेयजल और पब्लिक टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास प्रस्तावित है।

सुबह 10 बजे से पहले पहुंचे अधिकारी कार्यालयः गौरव

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। कलेक्टर डॉ. सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री साय के निर्देश के अनुरूप सभी कार्यालयों के अधिकारी समय पर पहुंचे। कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक विभागीय अधिकारी निर्धारित समय 10 बजे से पहले कार्यालयों में पहुंचें। सप्ताह में दो दिन आमजनों से मुलाकात करें। सप्ताह में सोमवार एवं गुरूवार को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक सभी अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यालय में बैठेंगे। इसके अलावा जिला स्तरीय सभी अधिकारी अपनी उपस्थिति कार्यालयीन निर्धारित समय 10 बजे तक ग्रुप में भेजें। कलेक्टर डॉ. सिंह द्वारा प्रत्येक माह में तीन कार्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि कार्यालयों की साफ-सफाई, सभी की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएं। इसके अलावा समय-सीमा की बैठक सोमवार के स्थान पर प्रत्येक मंगलवार को होगी।कलेक्टर डॉ. सिंह ने कहा कि सभी पटवारियों की समीक्षा, माह के अंतिम सप्ताह में गुरूवार को शाम 4.30 बजे होगी। इसके लिए अपर कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी फार्मेट तैयार कर लें। साथ ही माह के अंतिम सप्ताह में कृषि विभाग की बुधवार, महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभाग की मंगलवार, पंचायत विभाग की शुक्रवार शिक्षा विभाग तथा अन्य विभागों की बैठक शनिवार को होगी।

वन अधिकार प्रबंधन में यह कार्यशाला

मील का पत्थर साबित होगी छत्तीसगढ़: सोनमणि बोरा

रायपुर। धरती आबा-जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के वन अधिकार अधिनियम 2006 के बेहतर क्रियान्वयन विषय पर आज राजधानी रायपुर में एक दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न हुई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य वन अधिकार अधिनियम 2006 के बेहतर क्रियान्वयन में देश में एक अग्रणी राज्य है।

आज की कार्यशाला एक शुरुआत है इस कार्यशाला के माध्यम से वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में मैदानी स्तर पर आ रही परेशानियों को दूर करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि वन अधिकार अधिनियम एवं पेसा एक्ट के बेहतर क्रियान्वयन हेतु एक टॉस्क फोर्स के गठन का प्रस्ताव विचाराधीन है इसके माध्यम से ऐक्ट के प्रावधानों को बेहतर ढंग से लागू किया जा सकेगा।

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने कहा कि राज्य में अब तक 4 लाख 79 हजार 502 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र तथा 4377 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। इसके अलावा सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्य ग्राम सभाओं में सामुदायिक वन संसाधनों के प्रबंधन हेतु सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति के गठन की कार्यवाही की जा रही है। अब तक 2081 सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समितियों का गठन किया जा चुका है।

राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से अब व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र धारकों की मृत्यु होने पर वारिसानों के नाम पर काबिज भूमि का नामांतरण एवं अन्य प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है। अब तक नामांतरण, सीमांकन और त्रुटि सुधार से संबंधित 881 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। इससे वंशानुगत रूप से वन भूमि के हस्तांतरण में आ रही कठिनाई को दूर करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में वन अधिकार के बेहतर क्रियान्वयन के संबंध में अनेक बिंदुओं पर चर्चा की गई जिनमें मुख्य रूप से वन अधिकारों का डिजिटलाईजेशन एवं ऑनलाइन प्रक्रियाकरण, वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में एफआरए सेल की भूमिका, सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन व्यवस्था का क्रियान्वयन एवं स्टेकहोल्डरर्स की भूमिका, वन अधिकार पत्र धारकों का अभिसरण के माध्यम से आजीविका संवर्धन, ग्राम सभाओं तथा समितियां के क्षमता विकास के माध्यम से सशक्तिकरण आदि प्रमुख हैं। कार्यशाला में इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा से प्राप्त सुझावों से वन अधिकार अधिनियम के और बेहतर क्रियान्वयन में यह कार्यशाला मील का पत्थर साबित होगी।

हर रोज जारी रहेगी निरीक्षण अभियानः कलेक्टर

बिलासपुर। अवैध धान संग्रहण और परिवहन के विरुद्ध संयुक्त टीम ने आज फिर बड़ी कार्रवाई की। पांच अलग - अलग स्थानों पर दबिश देकर 264 क्विंटल धान जब्त किए। जब्त किए गए धान की कीमत 8.18 लाख रुपए की है। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर खाद्य, राजस्व, मंडी और मार्कफेड की संयुक्त टीम ने मिलकर कार्रवाई को अंजाम दिया। कलेक्टर ने आकस्मिक जांच की कार्रवाई आगे भी जारी रखने के कठोर निर्देश टीम के अफसरों को दिए हैं।

जिला खाद्य अधिकारी अनुराग भदौरिया ने जारी विज्ञप्ति में बताया है कि तहसील बोदरी के ग्राम सारधा में राजस्व एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा जाँच अभियान चलाया गया। जॉच के दौरान ग्राम सारधा में दुकान संजय किराना, प्रोपाईटर संजय केवट के यहां 60 बोरी (24 क्विंटल) धान अवैध रूप से भण्डारण किया जाना पाया गया। उपरोक्तानुसार धान की मण्डी अधिनियम के तहत् जब्त कर कार्रवाई की गई। तहसील कोटा में खाद्य नियंत्रक बिलासपुर, जिला विपणन अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा सलका नवागाँव के समीप 02 वाहनों में 300 बोरा अवैध धान का परिवहन किये जाने पर उपरोक्त धान को जब्त करते हुए पुलिस अभिरक्षा में दिया गया।तहसील कोटा में ही खाद्य नियंत्रक बिलासपुर, जिला विपणन अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा सलका नवागाँव में गुप्ता ट्रेडर्स द्वारा धान का परिवहन किये जाने पर परिसर में उपलब्ध 200 बोरा धान को जब्त करते हुए पुलिस अभिरक्षा में दिया गया। तहसील सीपत में राजस्व एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा जाँच अभियान चलाया गया। जॉच के दौरान ग्राम सीपत में दुकान मां प्रोविजन स्टोर्स, प्रोपाईटर इंद्रकुमार वर्मा पिता रामदत्त वर्मा के यहां 60 बोरी (24 क्विंटल) धान अवैध रूप से भण्डारण किया जाना पाया गया।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.